सत्यमेव जयते

असंशोधित

बिहार विधान–सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

15 मार्च, 2023

सप्तदश विधान सभा
अष्टम सत्र

बुधवार, तिथि 15 मार्च, 2023 ई0
24 फाल्गुन, 1944 (शक)

(कार्यवाही प्रारंभ होने का समय- 11.00 बजे पूर्वाह्न)
(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष: सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है । अब प्रश्नोत्तर काल होगा ।
अल्पसूचित प्रश्न । माननीय सदस्य श्री विजय कुमार खेमका ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से एक अनुरोध करना चाहता हूं।

अध्यक्ष : ठीक है, बोलिये ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, कल इस सदन में कुछ अप्रिय घटनाएं हुई हैं और हम समझते हैं कि सदन के किसी भी माननीय सदस्य को और विशेष रूप से आसन को उस तरह के अशोभनीय आचरण या घटना की उम्मीद नहीं रही होगी लेकिन महोदय कभी-कभी भावावेश में कोई घटना घट जाती है । हमने कल भी कहा था अब मजबूरन आपको कुछ अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी पड़ी । बात वाजिब है कि आसन को भी सदन और जो प्रजातांत्रिक तरीके हैं, प्रक्रिया है उसकी मर्यादा के लिए कभी-कभी अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी पड़ती है जो आपने की तो कल से बाहर हैं अब आज सारे विपक्ष के सदस्य बाहर हैं । महोदय, किसी भी हाल में सरकार को या हम लोगों का जो सत्ताधारी गठबंधन है उसको यह स्थिति अच्छी नहीं लगती है क्योंकि हम लोग इस सिद्धान्त में पूर्णतया गहराई से विश्वास करते हैं कि विपक्ष भी सरकार का अंग होता है और महोदय देखिये उस तरफ, आप अगर देखते हैं तो कितना सूनापन दिखता है, सदन सूना हो जाता है अगर हमारे विपक्ष के साथी नहीं रहते हैं और महोदय हमने तो अनेक अवसरों पर कहा है कि अगर विपक्ष के कोई माननीय सदस्य या कोई सत्ता पक्ष के भी माननीय सदस्य अगर प्रश्नों के माध्यम से विभिन्न प्रस्तावों के माध्यम से जमीनी हकीकत की जानकारी सरकार को नहीं दें तो बहुत सारी कमियां सरकार के संज्ञान में ही नहीं आ पायेंगी । इसलिए सरकार तो एहसानमंद होती वैसे सदस्यों की जो सरकार की कमियां उजागर करते हैं और वे जब कमियां उजागर करते हैं तो सरकार को रास्ता दिखता है आगे काम करने का तरीका समझ में आता है । इसलिए हम लोग इनकी किसी बात का कभी बुरा नहीं मानते हैं लेकिन सदन की भी मर्यादा होती है, अनुशासन होता है उस पर जब आघात होता है और कल ही जो घटना घटी हम उसको दोहराना नहीं चाहते हैं । आज हम सिर्फ इतना ही अनुरोध करना चाहते हैं अपनी तरफ से भी और सत्ताधारी दल की तरफ से,

सरकार की तरफ से, आसन से कि इनके बिना सूनापन है और एक बार जरूर हम लोगों की इच्छा है कि वे सदन में आयें और हम समझते हैं कल ही हम लोगों ने अधिकतम स्पेस जिसको कहते हैं, अधिकतम जगह दे के उनको हम लोगों ने उस मामले को सुलझाने का रास्ता दिया था । महोदय, अगर सदन में कोई खेद प्रकट करता है, सदन की मर्यादा पर कोई आघात हो तब सदन के प्रति सदन के सम्मान में खेद प्रकट करना, इससे कोई छोटा या नीचा नहीं होता है । सदन से तो हम सब लोग नीचे हैं, इस आसन से हम सब लोग नीचे हैं तो यह तो एक रास्ते की बात होती है और उसमें भी सरकार या किसी पक्ष-विपक्ष की बात नहीं थी, आसन ने उसको सदन की मर्यादा के खिलाफ माना था और आसन ने नियमन दिया था कि ये ऐसा आचरण है जिसके विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी उस परिस्थिति में आपने भी यह आसन की उदारता, महानता थी कि हम लोगों के अनुरोध पर आपने उन्हें मौका भी दिया और सही बात है कि अगर भावावेश में हम ही से कोई गलती हो जाये तो आदमी खेद प्रकट करता है सदन के सामने, आसन के सामने तो आदमी छोटा नहीं होता है उसकी ऊंचाई बढ़ती है और सदन से और आसन से तो हम सब लोग नीचे हैं इसलिए यह रास्ता था । आज हम लोगों की इच्छा है महोदय कि एक बार आप जब भी हो, अभी हो या सदन अभी जब ब्रेक करेगा आप उनसे बुलाकर बात कर लीजिये माननीय सदस्य कम से कम अपनी बातों के लिए दुख प्रकट कर दें और वे सदन में रहें । महोदय, सरकार चाहती है कि विपक्ष सदन में रहे, हर हालत में रहे लेकिन यह भी बात है कि सदन की मर्यादा रहेगी तभी तो सदन रहेगा । इसलिए आप हम लोगों की इच्छा से एक बार जरूर उनको खबर देकर बात करियेगा, एक रास्ता निकल जाये कि दोनों हम लोग सत्ता पक्ष, विपक्ष दोनों साथ बैठकर बिहार की जनता के हित में सभी अनुकूल निर्णय ले सकें, सार्थक विमर्श कर सकें ।

श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन : अध्यक्ष महोदय,..

अध्यक्ष : बोलिये ।

श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी बता रहे थे कल ही की तारीख में हमने देखा है कि उत्तराखंड में जहां भाजपा की सरकार है वहां सभी विपक्ष के विधायकों को निलंबित कर दिया गया, कल की तरीख में, लगभग 15 विधायक हैं उत्तराखंड में कांग्रेस के और अन्य दलों के सभी पर सख्त कार्रवाई की गई सिर्फ मेज थपथपाने और वेल में आने के लिए । इसी मार्च के महीने में गुजरात जिसको वे लोग आदर्श मानते हैं गुजरात विधान सभा में 19 विधायकों को निलंबित कर दिया गया । इसी महीने में आप देखियेगा कि मध्यप्रदेश जहां भाजपा की सरकार है वहां जीतू पटवारी को पूरे सत्र के लिए निष्कासित कर दिया गया है, एक नहीं अभी जिग्नेश

मेवानी सहित 9 विधायकों को इसी महीने की एक तारीख को 9 विधायकों को निष्कासित कर दिया गया तो जहां उनकी सरकार है वे अनुशासन में चलाना चाहते हैं, यहां पर अध्यक्ष जी आप हैं आप अनुशासित तरीके से, बेहतर ढंग से सरकार चलाइये जो भी सदस्य किसी भी पक्ष के हों, उसमें बाधा डालते हैं, वेल में आते हैं और प्रश्न काल नहीं चलने देते हैं, सही तरीके से संचालन नहीं होने देते हैं तो हम चाहेंगे कि आसन सख्ती से कार्रवाई करे और बेहतर ढंग से अनुशासित ढंग से चले, हम लोग आपके साथ हैं अध्यक्ष महोदय ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, माननीय मंत्री,संसदीय कार्य विभाग,बिहार सरकार ने अपना सुझाव दिया है । मैं विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वे सदन में आयें और जो कल घटना घटी है और आसन ने, सरकार से जो प्रस्ताव आया आपने उसको हां, ना में पारित किया । प्रतिपक्ष के लोग सदन में आयें और माननीय सदस्य अगर खेद प्रकट करें, दुख प्रकट करें तो अच्छा है । जो संसदीय व्यवस्था है उसमें सत्ता पक्ष की सरकार चलाने की जितनी जिम्मेवारी है उससे कम जिम्मेवारी विपक्ष की भी नहीं है । इसलिए मैं आग्रह करता हूं विपक्ष के माननीय सदस्यों से कि वे आयें और जो कल की घटना है और जो फैसले हैं उस फैसले के मुताबिक वे अपनी कार्रवाई करें और संसदीय कार्य में सम्मिलित हों ।

अल्पसूचित प्रश्न लिये जायेंगे । माननीय सदस्य श्री विजय कुमार खेमका ।

टर्न-2/यानपति/15.03.2023

प्रश्नोत्तर काल

अल्पसूचित प्रश्न संख्या-50 (श्री विजय कुमार खेमका, क्षेत्र संख्या-62, पूर्णिया)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता । माननीय मंत्री श्रम संसाधन विभाग ।

अल्पसूचित प्रश्न संख्या-51 (श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता, क्षेत्र संख्या-9, सिकटा)

श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता: पूछता हूं ।

श्री सुरेन्द्र राम, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, उत्तर, बिहार से अन्य राज्यों में रोजगार के लिए जानेवाले श्रमिकों की कुल संख्या संबंधित आधिकारिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है । उक्त प्रवासी संरक्षी कार्यालय से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार वर्ष 2022 में ई0सी0आर0 देशों में कुल 57 हजार 46 नन मैट्रिक श्रमिक विभिन्न रोजगार तथा समान श्रमिक राज मिस्त्री, ड्राइवर, इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर, प्लंबर इत्यादि गए हैं । वस्तुस्थिति यह है कि वर्तमान में नन मैट्रिक के लिए उपयुक्त कोर्स में प्रशिक्षण देने हेतु कुल 43 केंद्रों की स्थापना पश्चिमी चंपारण सहित राज्य के 24 जिलों में की गई है एवं इन केंद्रों के माध्यम से

राज्य के नन मैट्रिक युवाओं को भी प्रशिक्षण दिया जाता रहा है । वस्तुस्थिति यह है कि कंडिका-1 एवं 2 में स्पष्ट कर दी गई है । कोर्स एवं प्रशिक्षण केंद्र संबंधित विभागों में मांगों के अनुरूप एवं जिला के कौशल समिति की अनुशंसा के आधार पर खुलते रहते हैं ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय मंत्री ने जो जवाब दिया है आप संतुष्ट हैं ।

श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता: महोदय, उसी के आलोक में पूरक है कि जैसे उसमें कहा गया है कि बिहार के 24 जिलों में ऐसी ट्रेनिंग की व्यवस्था है जहां इलेक्ट्रिशियन से लेकर के, प्लंबर से लेकर के और जितने तरह के मजदूर बाहर काम करने के लिए जाते हैं उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था है लेकिन पश्चिम चंपारण में यह पूरे खोजने पर एक मात्र एक संस्था जो है जो जनशिक्षा संस्थान करके है उसमें जो है नन मैट्रिक के लिए नहीं है और यह जो मजदूर खाड़ी देशों में जा रहे हैं वह 4 लाख से ज्यादा जा रहे हैं और उसमें ज्यादा हम समझते हैं कि खाड़ी देशों में जो 53 हजार गए हैं वो नन मैट्रिक ही हैं, वहां वह जाते हैं वह फंस जाते हैं । यहां इनकी ट्रेनिंग है नहीं वहां उनसे वह चरवाही कराने लगते हैं, घर की सफाई कराने लगते हैं और हमारे गांव में जो इलेक्ट्रिशियन जगह-जगह काम करते हैं सरकारी तौर पर उतने......

अध्यक्ष: आप पूरक पूछिए ।

श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता: जी पूरक पूछ रहे हैं ।

अध्यक्ष: आप पूरक नहीं पूछ रहे हैं । यह पूरक नहीं हुआ ।

श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता: वह देख रहे हैं कि अभी भी हाल में दो घटनाएं हुईं, ट्रांसफर्मर पर दो मजदूर जलकर मर गए हैं वह बिजली को सुधार करने के चक्कर में तो उनके कम से कम सुरक्षात्मक उपायों का, एक न्यूनतम प्रशिक्षण की व्यवस्था प्रखंड लेवल पर होनी चाहिए और उसमें मैट्रिक से नीचे का ज्यादा इस ढंग से लें ।

अध्यक्ष: फिर आप पूरक नहीं पूछ पा रहे हैं ।

श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता: पूछे तो कि प्रखंड लेवल पर यह व्यवस्था सरकार करेगी या नहीं प्रशिक्षण की ?

अध्यक्ष: माननीय मंत्री श्रम संसाधन विभाग ।

श्री सुरेन्द्र राम, मंत्री: महोदय, नहीं अभी तो प्रखंड लेवल पर कोई विचार सरकार नहीं रखती है ।

अध्यक्ष: सरकार अभी विचार नहीं रखती है ।

श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता: तो कुल मिलाकर यह जरूरी है महोदय, सदन में यह बात आ गई है, यह बिहार के लिए जरूरी है इसपर विचार किया जाय आगे ।

अध्यक्ष: आप अपना स्थान ग्रहण करें । माननीय सदस्य श्री मिश्री लाल यादव ।

अल्पसूचित प्रश्न सं0-52 (श्री मिश्री लाल यादव, क्षेत्र सं0-81 अलीनगर)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष: अब तारांकित प्रश्न लिये जाएंगे । माननीय सदस्य श्री अरूण सिंह । माननीय मंत्री पंचायती राज विभाग जवाब देंगे, आपको प्राप्त होगा ।

श्री अरूण सिंह: उत्तर नहीं आया है ।

तारांकित प्रश्न सं0- 'क' 389 (श्री अरूण सिंह, क्षेत्र सं0-213 काराकाट)

श्री मुरारी प्रसाद गौतम, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, स्वीकारात्मक है प्रश्न इनका, जिला पदाधिकारी रोहतास सासाराम के पत्रांक- 608, दिनांक- 28 फरवरी 2023 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि रोहतास जिलांतर्गत काराकाट विधान सभा क्षेत्र के काराकाट प्रखंड में देवग्राम अवस्थित जिसके वार्ड नंबर- 5 में नल-जल का कार्य पूर्ण करा लिया गया है परंतु गांव के पूरब टोला एक कि0मी0 दूरी होने के कारण नल का जल नहीं पहुंच पाया । वर्तमान में उपलब्ध वार्ड संख्या-5 में नल-जल योजना से उक्त बसावट को आच्छादित किया जाना संभव नहीं है । अत: उक्त टोला में छूटे हुए बसावटों को पेयजल जलापूर्ति के लिए एक मिनी योजना का प्राक्कलन तकनीकी सहायक के माध्यम से तैयार करा लिया गया है कार्य को अविलंब पूर्ण कराने हेतु प्रखंड पंचायत पदाधिकारी को निर्देशित भी किया जा चुका है ।

श्री अरूण सिंह: महोदय, इतना ही पूरक है कि इसकी कोई समय-सीमा आप निर्धारित करें ।

श्री मुरारी प्रसाद गौतम, मंत्री: बहुत जल्द हो जाएगा ।

अध्यक्ष: वह समय सीमा कह रहे हैं ।

श्री मुरारी प्रसाद गौतम, मंत्री: दो महीने के अंदर हो जाएगा ।

श्री अरूण सिंह: ठीक है ।

अध्यक्ष: श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव ।

श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव: जी, पूछता हूं ।

तारांकित प्रश्न सं0- 'ख' 391 (श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव, क्षेत्र सं0-216 जहानाबाद)

श्री संजय कुमार झा, मंत्री: माननीय अध्यक्ष महोदय, यह ट्रांसफर है आर0सी0डी0 को, रोड को ।

श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव: अध्यक्ष महोदय, यह दूसरी बार ट्रांस्फर हुआ है । नगर विकास विभाग से जल संसाधन विभाग और जल संसाधन विभाग से पथ निर्माण विभाग ।

अध्यक्ष: एक मिनट, माननीय मंत्री जी आप इसको कहां स्थानांतरित कर दिए हैं किस विभाग को किए हैं ।

श्री संजय कुमार झा, मंत्री: यह गया है रोड में, पी0डब्लू0डी0 में क्योंकि ब्रिज से रिलेटेड है, पुल बनाने से रिलेटेड तो इसलिए वह रोड को गया है ।

अध्यक्ष: माननीय मंत्री, आपके यहां यह स्थानांतरण किए हुए हैं ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उपमुख्यमंत्री: अध्यक्ष महोदय, हम दिखवा लेंगे ।

अध्यक्ष: माननीय विभागीय मंत्री इसको दिखवा लेंगे, सुदय जी आप स्थान ग्रहण करें और इसी सत्र में इसका जवाब आपको दे दिया जाएगा ।

श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव: जी धन्यवाद ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्नकर्ता ने प्रश्न पूछ दिया, माननीय मंत्री जी ने जवाब दे दिया जो पूरक सवाल का इन्होंने स्थानांतरण कर दिया है रोड डिपार्टमेंट में तो जब वह बैठ गए और बातें समाप्त हो गईं तो पुन: आपको पूरक पूछने का कोई औचित्य नहीं बनता है इसलिए आप स्थान ग्रहण कीजिए ।

श्री अरूण सिंह: महोदय, अभी समाप्त कहां हुआ है ।

अध्यक्ष: हुआ तो । उस दिन आप पूरक पूछ लेंगे जिस दिन इस प्रश्न का जवाब आएगा । अभी तो जवाब ही नहीं आया है तो पूरक किस चीज पर पूछिएगा ।

श्री अरूण सिंह: महोदय, यही जानना चाहते हैं कि सिंचाई विभाग पुल का निर्माण कराती है या नहीं कराती है ।

अध्यक्ष: माननीय मंत्री ।

श्री संजय कुमार झा, मंत्री: माननीय अध्यक्ष महोदय, पुल का निर्माण हमलोग नहीं कराते हैं, पुल का निर्माण आर0सी0डी0 या आर0ई0ओ0 कराता है लेकिन कहीं एसेंशियल एक पथीय बनाना होता है तो वहां पर कुछ जगह कराते हैं । नॉर्मली पुल का निर्माण पी0डब्लू0डी0 या आर0ई0ओ0 कराता है ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री अजय यादव ।

तारांकित प्रश्न सं0-1469 (श्री अजय यादव, क्षेत्र सं0-233 अतरी)

(लिखित उत्तर)

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उपमुख्यमंत्री: स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ का प्रशासनिक स्वीकृति शीर्ष एम0एम0जी0एस0वाई0 अन्तर्गत प्रदत्त है जिसकी लंबाई 1.57 कि0मी0 है । इस पथ का निविदा प्रकाशन की प्रक्रिया की जा रही है, तदनुसार निर्माण कार्य करा लिया जायेगा ।

अध्यक्ष: माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उपमुख्यमंत्री: जवाब दिया गया है ।

अध्यक्ष: आप पूरक पूछिए ।

श्री अजय यादव: जवाब दिया गया है, माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बहुत-बहुत धन्यवाद अतरी विधान सभा की तरफ से, मैं इनके जवाब से संतुष्ट हूं ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री मनोज यादव ।

तारांकित प्रश्न सं0-1470, (श्री मनोज यादव, क्षेत्र सं0- 163 बेलहर)

श्री मनोज यादव: पूछता हूं ।

अध्यक्ष: माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग से आपको जवाब मिला होगा, पूरक पूछिए ।

श्री मनोज यादव: स्थानांतरित कर दिया गया है जबकि सड़क, ग्रामीण सड़क है और इसमें आंसर आया है कि स्थानांतरित है तो मैं जानना चाहता हूं कि कब तक इसका जवाब आ जाएगा ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उपमुख्यमंत्री: महोदय, जवाब आया हुआ है ।

अध्यक्ष: आप कैसे यह बात समझ गए माननीय सदस्य कि स्थगित कर दिया गया है । माननीय मंत्री जवाब लेकर के आए हुए हैं आप जवाब......

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उपमुख्यमंत्री: पढ़ देते हैं ।

अध्यक्ष: यह पढ़ देते हैं ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उपमुख्यमंत्री: वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्न दो पथों से संबंधित है । एक, बिरनिया अनुसूचित जाति टोला से देवघर सुल्तानगंज मेन रोड तक पथ- उक्त पथ अलाइनमेंट में एक मात्र बसावट बिरनिया अनुसूचित जाति टोला अवस्थित है जिसकी संपर्कता शीर्ष एम0एम0जी0एस0वाई0 अंतर्गत निर्मित आदिवासी टोला करनदिया से बिरनिया पी0एम0जी0एस0वाई0 दमरकोला पथ से प्राप्त है । उक्त बसावट के अलावा कोई अन्य योग्य बसावट नहीं रहने के कारण इसे किसी भी कोर नेटवर्क से शामिल नहीं किया गया है । इसके निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । दूसरा, सिलुवा डाक बांगला से खजुरिया गांव तक पथ, उक्त पथ वन क्षेत्र में पड़ता है जो वन विभाग की जमीन है, वन विभाग से अनापत्ति पत्र की मांग की गई है । वन विभाग से अनापत्ति मिलने के उपरांत पथ का निर्माण कार्य कराया जाना संभव होगा ।

श्री मनोज यादव: ठीक है, धन्यवाद ।

टर्न-3/अंजली/15.03.2023

तारांकित प्रश्न संख्या-1471 (श्री इजहारूल हुसैन, क्षेत्र संख्या-54, किशनगंज)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री इजहारूल हुसैन, आपको प्रश्न का जवाब मिल गया होगा, आप पूरक पूछिये ?

श्री इजहारूल हुसैन : महोदय, जवाब तो नहीं मिला है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी आप जवाब पढ़ दीजिए ।

श्री जयंत राज, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न ट्रांसफर है ग्रामीण विकास विभाग को ।

अध्यक्ष : ट्रांसफर है ग्रामीण विकास विभाग को ।

श्री जयंत राज, मंत्री : जी महोदय ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग आपके यहां स्थानांतरित है तो क्या आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे ?

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : महोदय, अभी तो स्थानांतरित ही हुआ है तो ग्रामीण विकास विभाग का जब अगला डेट रहेगा बुधवार को तो उस पर हमलोग जवाब देंगे ।

श्री इजहारूल हुसैन : महोदय, यह कितने दिन के अंदर हो जाएगा ?

अध्यक्ष : आपके प्रश्न का जवाब माननीय मंत्री जी, ग्रामीण विकास विभाग अगली तिथि को देंगे ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह तो नियम है ।

अध्यक्ष : बिल्कुल नियम की बात आप कह रहे हैं, सही बात है । माननीय सदस्य श्री आबिदुर रहमान । माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

तारांकित प्रश्न संख्या-1472 (श्री आबिदुर रहमान, क्षेत्र संख्या-49, अररिया)

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री (लिखित उत्तर) : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड में आई0टी0 मैनेजर की आवश्यकता के आलोक में प्रशासी पदवर्ग समिति की दिनांक-26.08.2020 की बैठक में बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड में एक आई0टी0 मैनेजर का पद सृजित किया गया । तत्पश्चात् मंत्री परिषद् द्वारा बिहार राज्य पुल निर्माण निगम में आई0टी0 मैनेजर का एकल नियमित पद पर सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई । उक्त के अनुपालन में बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा विज्ञापन संख्या-29, दिनांक-19.02.2022 द्वारा आई0टी0 मेनेजर के पद पर नियमित नियुक्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया है और कार्रवाई प्रक्रियाधीन है ।

श्री आबिदुर रहमान : माननीय अध्यक्ष महोदय, इनके जवाब से मैं संतुष्ट हूं । थोड़ा इसमें तेजी लाई जाय, पथ निर्माण, मंत्री जी ।

अध्यक्ष : धन्यवाद । माननीय सदस्य श्री मोती लाल प्रसाद ।

तारांकित प्रश्न संख्या-1473 (श्री मोती लाल प्रसाद, क्षेत्र संख्या-23, रीगा)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

माननीय सदस्या श्रीमती नीतु कुमारी । माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग ।

तारांकित प्रश्न संख्या-1474 (श्रीमती नीतु कुमारी, क्षेत्र संख्या-236, हिसुआ)

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री (लिखित उत्तर) : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन टोला को संपर्कता देने हेतु Habitation App के माध्यम से सर्वे किया गया है, जिसकी सर्वे आई0डी0 30190 है । समीक्षोपरांत निधि की उपलब्धता के आधार पर अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी ।

अध्यक्ष : आप पूरक पूछिये । आपको जवाब मिला है ?

श्रीमती नीतु कुमारी : महोदय, जी । मैं जवाब से संतुष्ट हूं और रोड बन जाना चाहिए बस यही माननीय मंत्री जी से आग्रह है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री प्रमोद कुमार ।

तारांकित प्रश्न संख्या-1475 (श्री प्रमोद कुमार, क्षेत्र संख्या-19, मोतिहारी)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

माननीय सदस्य श्री राजवंशी महतो ।

तारांकित प्रश्न संख्या-1476 (श्री राजवंशी महतो, क्षेत्र संख्या-141, चेरिया बरियारपुर)

श्री संजय कुमार झा, मंत्री (लिखित उत्तर) : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि बेगूसराय जिलान्तर्गत चेरिया बरियारपुर प्रखंड में पहसारा में सियूरी बूढ़ी गंडक के बायां तटबंध का शीर्ष पूर्णतया मिट्टी से बना है । इसका उपयोग बाढ़ अवधि में तटबंध की निगरानी एवं बाढ़ संघर्षात्मक सामग्रियों के ढुलाई हेतु विभागीय पदाधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा किया जाता है । यह आम रास्ता नहीं है ।

तटबंध के ऊपरी भाग पर सड़क निर्माण हेतु यदि सड़क निर्माण से संबंधित विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र की मांग की जाती है तो इस संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने पर विचार किया जा सकता है ।

अध्यक्ष : आप पूरक पूछिये ।

श्री राजवंशी महतो : अध्यक्ष महोदय, उक्त पथ की, जो बांध सिंचाई विभाग से, जल संसाधन विभाग से जो हम कहे थे माननीय मंत्री जी से आग्रह किए हैं कि कहीं-कहीं रोड बना हुआ है, बाढ़ के समय सामग्री ले जाते हैं पदाधिकारी लोग, आमजन को जो सुविधा होनी चाहिए हम उसके लिए मांग कर रहे हैं माननीय मंत्री जी से कि उनको ध्यान में रखते हुए पूरे बांध के किनारे बहुत बड़ा गरीब लोगों की आबादी है, उनकी सुविधा के लिए भी हम कहते हैं कि माननीय मंत्री जी विचार कीजिए और पूरे बांध पर सड़क का निर्माण करवा दीजिए ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग ।

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने जवाब में कहा है कि नॉर्मली जल संसाधन विभाग के द्वारा हमलोग मेंटन रखते हैं जो अपने पदाधिकारी इंस्पेक्शन करते हैं या जो मेटेरियल जाता है उसके लिए, लेकिन अगर कोई रोड बनाना है तो वह आर0सी0डी0 या पी0डब्लू0डी0 बनाता है । अगर वे लोग कोई प्रस्ताव देंगे तो हमलोगों को एन0ओ0सी0 देने में कोई दिक्कत नहीं है अगर वहां से बनता है तो ।

श्री राजवंशी महतो : महोदय, हमारे ही एक और प्रश्न डाले हैं जल संसाधन विभाग को । अध्यक्ष महोदय, मेरे ही प्रश्न संख्या-2870 के जवाब में जल संसाधन विभाग ने स्वीकार किया है तथा मुझे जवाब में प्राप्त है कि डेढ़ किलोमीटर सड़क का निर्माण बूढ़ी गंडक तटबंध पर विभाग के द्वारा कराया गया है तथा दो-ढाई किलोमीटर सड़क का निर्माण पंचायत स्तर से भी कराया गया है इसलिए हम आग्रह माननीय मंत्री जी से करते हैं कि पूरा करवा दीजिए जिससे कि लोगों को आवाजाही में सुविधा हो ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग उन्हें एक बार और बतला दिया जाय ।

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि कहीं-कहीं इंसेंशियल होता है तो हमलोग कराते हैं जैसे बता रहे हैं कि उसी रोड पर पंचायत के द्वारा काम कराया गया है । नॉर्मली हमलोग जो विभाग के पदाधिकारी फ्लड सीजन में इंस्पेक्शन करने जाते हैं, उनका मोटरेबुल रहे ये काम हमलोग करते हैं या जो मेटेरियल जाता है फ्लड में, उसके मूवमेंट में दिक्कत नहीं हो वह काम करते हैं लेकिन बांध पर रोड बनना है, अमूमन या तो आर0सी0डी0 या पी0डब्लू0डी0 बनाता है, एन0ओ0सी0 हमलोग देते हैं तो दोनों विभाग से वह आग्रह करें, उनका एन0ओ0सी0 आएगा तो जल संसाधन विभाग को कोई दिक्कत नहीं है हमलोग एन0ओ0सी0 दे देंगे ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या-1477 (डॉ0 संजीव कुमार, क्षेत्र संख्या-151, परबत्ता)</u>

अध्यक्ष : माननीय सदस्य डॉ संजीव कुमार । आप पूरक पूछिये ।

डॉ0 संजीव कुमार : अध्यक्ष महोदय, उत्तर नहीं आया है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, जरा एक बार आप पढ़ दें ।

श्री जयंत राज, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह स्थानांतरित है ग्रामीण विकास विभाग को ।

डॉ0 संजीव कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरक है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, संजीव जी, जब प्रश्न ही स्थानांतरित हो गया है और उसका जवाब ही नहीं आया तो आप किस चीज पर पूरक पूछ रहे हैं ।

डॉ0 संजीव कुमार : महोदय, किस विभाग में यह स्थानांतरित हुआ है मैं यह जानकारी चाह रहा हूं?

श्री जयंत राज, मंत्री : ग्रामीण विकास विभाग में ।

अध्यक्ष : ग्रामीण विकास विभाग में स्थानांतरित हुआ है ।

डॉ0 संजीव कुमार : अध्यक्ष महोदय, इसका कब तक आएगा बता दिया जाय, तालाब के जीर्णोद्धार को लेकर क्वेश्चन है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह तो नियम है कि अगर कोई विभाग से स्थानांतरित होकर कोई प्रश्न आता है तो जिस डेट में ग्रामीण विकास विभाग का प्रश्न की तिथि निर्धारित है पहले से तो उसी डेट पर वह प्रश्न आएगा ।

डॉ0 संजीव कुमार : ठीक है अध्यक्ष महोदय धन्यवाद ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्या श्रीमती अरूण देवी ।

तारांकित प्रश्न संख्या-1478 (श्रीमती अरूणा देवी, क्षेत्र संख्या-239, वारिसलीगंज)

(माननीय सदस्या अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या-1479 (श्री हरिशंकर यादव, क्षेत्र संख्या-108, रघुनाथपुर)

माननीय सदस्य श्री हरिशंकर यादव । आप पूरक प्रश्न पूछें, आपको जवाब मिला है ?

श्री हरिशंकर यादव : महोदय, जवाब नहीं आया है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग । जवाब उनको अप्राप्त है ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ की लंबाई 800 मीटर है जो एकीकृत है और इस पथ का सर्वे छूटे हुए बसावट अंतर्गत मोबाइल ऐप से किया गया है जिसकी सर्वे आई0डी0-23746 है । तद्नुसार अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी ।

श्री हरिशंकर यादव : अध्यक्ष महोदय, हम मंत्री जी से चाहते हैं कि जल्द से जल्द बनवा दीजिए। बहुत लोगों को कठिनाई है, वहां संपर्क रोड कहीं से है ही नहीं, एकदम कच्ची में लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, बरसात के दिन में बहुत कठिनाई होती है ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री : ठीक है । इसका सर्वे करा लिया गया है । आई0डी0 जेनरेट कर दिया गया है । हमलोग निधि की व्यवस्था करा कर इसको करवा लेते हैं ।

श्री हरिशंकर यादव : बहुत-बहुत धन्यवाद ।

तारांकित प्रश्न संख्या-1480 (श्री मोहम्मद अनजार नईमी, क्षेत्र संख्या-52, बहादुरगंज)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री मोहम्मद अनजार नईमी ।

श्री मोहम्मद अनजार नईमी : महोदय, जवाब नहीं मिला है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पुल के निर्माण हेतु तकनीकी संभाव्यता की समीक्षा की जा रही है । तद्नुसार समीक्षोपरांत निधि की

उपलब्धता के आधार पर अग्रसर कार्रवाई किया जाना संभव हो सकेगा । महोदय, यह जो टेक्निकल है उसकी समीक्षा के लिए विभाग को आदेश दिया गया है वह कर रही है, उसके उपरांत ही आगे की कार्रवाई की जाएगी ।

श्री मोहम्मद अनजार नईमी : महोदय, यह बहुत जरूरी है । चूंकि दोनों तरफ...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सरकार काफी गंभीर है और कार्रवाई चालू है । इंतजार कीजिए ।

श्री मोहम्मद अनजार नईमी : जी, जल्दी हो जाएगा इसके लिए धन्यवाद ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री सुर्यकांत पासवान ।

तारांकित प्रश्न संख्या-1481 (श्री सुर्यकांत पासवान, क्षेत्र संख्या-147, बखरी, अ0जा0)

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री (लिखित उत्तर) : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पुल स्थल एम0एम0जी0एस0वाई0 अंतर्गत निर्माणाधीन मुशहरी से अभुआर पथ के Alignment के चैनेज 420 मीटर पर अवस्थित है, जिसकी लंबाई लगभग 25 मीटर है । पुल निर्माण हेतु पथ का डी0पी0आर0 को पुनरीक्षित किया जा रहा है । तद्नुसार अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी ।

अध्यक्ष : आप पूरक पूछें ?

श्री सुर्यकांत पासवान : महोदय, जवाब आया है लेकिन जवाब भेग है । मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इस पुल का निर्माण कब तक होगा ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री : महोदय, डी0पी0आर0 बनाने के साथ दिया है, पुल निर्माण हेतु पथ के डी0पी0आर0 को पुनरीक्षित किया जा रहा है । तद्नुसार अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी ।

श्री सुर्यकांत पासवान : महोदय, किया जा रहा है यह हम समझते हैं दो साल से यह काम लंबित है और पुल के चलते रोड भी नहीं बन रहा है, रोड भी आपने दिया है ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री : महोदय, डी0पी0आर0 एक बार बन जाएगा उसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मंत्री जी ने स्पष्ट आपको जानकारी देने का काम किया कि जो डी0पी0आर0 है उसको रिवाइज किया जा रहा है और रिवाइज होने के बाद से नियमानुसार आगे की कार्रवाई माननीय मंत्री जी करेंगे । आप संतुष्ट होइए ।

टर्न-4/सत्येन्द्र/15.03.23

तारांकित प्रश्न संख्या-1482(श्री मुकेश कुमार यादव, क्षेत्र सं0-27 बाजपट्टी)

(लिखित उत्तर)

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव,उप मुख्यमंत्री: वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ की लम्बाई 1.30 कि0मी0 है । इस पथ का सर्वे छूटे हुए बसावट अन्तर्गत मोबाईल ऐप से कर लिया गया है, जिसकी सर्वे आई0डी0-22276 है । तदनुसार अग्रेत्तर कार्रवाई की जा सकेगी ।

श्री मुकेश कुमार यादव: अध्यक्ष महोदय, जवाब से संतुष्ट हूँ । मंत्री जी को धन्यवाद ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 1483(श्री प्रेम शंकर प्रसाद, क्षेत्र सं0-99 बैकुण्ठपुर)

(लिखित उत्तर)

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उपमुख्यमंत्री: वस्तुस्थिति यह है कि गोपालगंज जिलान्तर्गत प्रश्नगत पथ, ग्रामीण कार्य विभाग का राजापट्टी-कासी टेंगराही पथ पर अवस्थित बन्धौली ग्राम से उद्गमित होकर पकरिया-शीतलपुर होते हुए एन0एच0-227ए0 पर सत्तरघाट पुल के पहुँच पथ के समीप मिल जाती है ।

प्रश्नगत पथ, बन्धौली-पकरिया-शीतलपुर पथ की लम्बाई 7.50 कि0मी0 है, जो दिनांक-11.04.2018 को ग्रामीण कार्य विभाग से अधिगृहित है। पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त है । पथ का लगभग 3.50 कि0मी0 अंश (एन0एच0-227ए0 के मिलन बिन्दु से लेकर पथ का सारण बाँध के क्रॉस प्वाइंट तक) गंडक नदी के Meandering Portion के अन्तर्गत है।

3.50 कि0मी0 पथांश गंडक नदी के Meandering Portion के अन्दर होने के कारण प्रस्तावित पथ के संरचना के स्थायित्व हेतु उच्चस्तरीय तकनीकी दल के निरीक्षणोंपरान्त निर्माण संबंधी कार्रवाई की जायेगी ।

श्री प्रेम शंकर प्रसाद: जवाब आया है । माननीय मंत्री जी को धन्यवाद ।

तारांकित प्रश्न संख्या-1484(श्री पवन कुमार यादव,क्षेत्र सं0-155 कहलगांव)

(अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या-1485(श्री प्रमोद कुमार सिन्हा,क्षेत्र सं0-10,रक्सौल)

(अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या-1486(श्री संजय सरावगी,क्षेत्र सं0- 83 दरभंगा)

(अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या-1487(श्री छत्रपति यादव,क्षेत्र सं0- 149,खगड़िया)

(लिखित उत्तर)

श्री मुरारी प्रसाद गौतम, मंत्री: स्वीकारात्मक । विभागीय पत्रांक 2780, दिनांक 13 मई, 2020 के आलोक में जिला परिषद् में जिला अभियंता के पद पर लघु जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता अतिरिक्त प्रभार में कार्यरत हैं।

अध्यक्ष: आप पूरक पूछें।

श्री छत्रपति यादव: जिला परिषद में कार्यपालक अभियंता की नियुक्ति नहीं होने के कारण वहां काम ठप्प है खगड़िया जिला में और उत्तर में दिया गया है कि जो पत्रांक 2780 दिनांक 13 मई, 20 है उसके द्वारा प्रभार दिया गया है लघु सिंचाई विभाग के इंजीनियर को, जिससे काम न इस विभाग में हो रहा है न उस विभाग में हो रहा है इसलिए पता कर लिया जाय सदन के माध्यम से, जिला परिषद के माध्यम से वहां कोई काम नहीं हो रहा है, सारा जिला परिषद का कार्य अस्तव्यस्त है इसलिए हम मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि कबतक स्थायी जिला इंजीनियर की वहां नियुक्ति की जायेगी ?

अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री मुरारी प्रसाद गौतम, मंत्री: महोदय, जिला परिषद में जो कार्यपालक अभियंता का पद है पूर्व से अभी तक माईनर इरीगेशन के जो एक्सक्यूटिव इंजीनियर हैं उनको यहां प्रतिनियुक्त किया जाता है और आपके यहां भी अभी अतिरिक्त प्रभार में हैं और स्थायी के लिए हमलोग प्रयास कर रहे हैं। हमारे यहां डी0पी0एम0की बहाली हो चुकी है बहुत जल्द ही डी0पी0एम0 को हमलोग कार्यपालक अभियंता बनाने जा रहे हैं।

श्री छत्रपति यादव: मंत्री जी, कबतक आशा रखी जाय । इस साल हो जायेगा या दो महीने में, चार महीने में, छ: महीना में? चूंकि काम सफर हो रहा है ।

श्री मुरारी प्रसाद गौतम, मंत्री: जून के बाद महोदय कर दिया जायेगा ।

श्री छत्रपति यादव: ठीक है । धन्यवाद।

तारांकित प्रश्न संख्या-1488(श्री मुकेश कुमार रौशन,क्षेत्र सं0- 126 महुआ)

(अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या-1489(श्रीमती गायत्री देवी,क्षेत्र सं0-25,परिहार)

(अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या-1490(श्रीमती वीणा सिंह,क्षेत्र सं0-129,महनार)

(अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या-'ग'-1491(श्रीमती मंजु अग्रवाल,क्षेत्र सं0-226,शेरघाटी)

श्रीमती मंजु अग्रवालः पूछती हूँ ।

अध्यक्षः आपको प्रश्न का जवाब मिल गया है न ? मिल गया है तो आपको सप्लीमेंट्री पूछना चाहिए।

श्रीमती मंजु अग्रवालः उत्तर नहीं मिला है ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उपमुख्यमंत्रीः अच्छा हम पढ़ देते हैं। आंशिक स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्न दो पथों से संबंधित है, जिसकी स्थिति निम्नवत है:-

(1) जी0टी0 रोड ठाकुरबाड़ी से पुराना पुल से ग्राम चन्दा मोड़ होकर जी0टी0 सूर्यमंडल तकः- यह पथ पुराने जी0टी0 रोड का भाग है । यह पथ, पथ निर्माण विभाग के स्वामित्व में है ।

(2) ग्राम पंचायत पट्टी के भेलवा गॉव से चन्दा मेन रोड तथा प्राथमिक विद्यालय भेलवा से नदी किनारा तकः- यह पथ एल022-टी002 से गांगी नाम से पी0एम0जी0एस0वाई0 अन्तर्गत निर्मित है, जिसकी लम्बाई 4.80 कि0मी0 है । यह पथ वर्त्तमान में पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि से बाहर है । इस पथ की मरम्मती हेतु प्राक्कलन बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति-2018 अन्तर्गत प्राप्त है। समीक्षोपरान्त निधि की उपलब्धता के आधार पर अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी ।

इस पथ के आरेखन में ग्राम भेलवा एवं ग्राम गांगी के बीच पड़ने वाले इनबोरवा नदी पर पुल पी0एम0जी0एस0वाई0 अन्तर्गत निर्माणाधीन है, जिसका पैकेज सं0-बी0आर0-12आर-1126 है ।

अध्यक्षः माननीय विधायिका जी, माननीय मंत्री जी के स्तर से स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है और ये एन0एच0ए0आई0 का भी मामला है फिर जो पी0एम0जी0एस0वाई0 का है । दोनों चीजों की जानकारी आपको देकर के, अनुरक्षण नीति जो पांच वर्षो का है इसमें हैं कि जो बनायेगा वही उसकी मरम्मती भी पांच वर्ष तक करेगा उससे भी आगे चला गया है। अब उसको बनाने की कार्रवाई हो रही है । निधि की उपलब्धता के आधार पर इसको सरकार बनवा देगी इसलिए आप स्थान ग्रहण कर लें ।

श्रीमती मंजु अग्रवालः मैं कहना चाहूंगी कि अतिशीघ्र उस पर भी ध्यान दिया जाय, बहुत जरूरी है।

अध्यक्षः माननीय मंत्री जी, शीघ्र ध्यान देते हैं और काफी मेहनत भी करते हैं । आप स्थान ग्रहण करें ।

श्रीमती मंजु अग्रवालः धन्यवाद ।

तारांकित प्रश्न संख्या-1492(श्री प्रकाश वीर,क्षेत्र सं0- 235, रजौली(अ0जा0)

(लिखित उत्तर)

अध्यक्षः आपका जो इसमें प्रश्न है, इसी में उत्तर मुद्रित है। आप पूरक पूछें।

श्री प्रकाश वीर: उत्तर नहीं मिला है सर ।

अध्यक्ष: उत्तर तो मिल गया है इसलिए कि उसमें उत्तर लिखा हुआ है खाली पढ़ लेने की जरूरत है। अच्छा आप पढ़िये माननीय मंत्री जी।

श्री सुरेन्द्र राम,मंत्री: अच्छा पढ़ देता हूँ । अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि प्रभारी प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, नवादा के पत्रांक 53 दिनांक 23 फरवरी, 2023 एवं कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, नवादा के पत्रांक 241(अनु0) दिनांक 22 फरवरी, 2023 के अनुसार संस्थान का भवन निर्माणाधीन है तथा भवन निर्माण कार्य समाप्ति की संभावित तिथि दिनांक 31 मार्च, 2023 है। भवन निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत हस्तान्तरण प्राप्त कर संस्थान को अपने भवन में स्थानांतरित करते हुए प्रशिक्षण कार्य प्रारंभ कर दिया जायेगा ।

श्री प्रकाश वीर: धन्यवाद सर ।

तारांकित प्रश्न संख्या-1493(श्री ऋषि कुमार,क्षेत्र सं0-220,ओबरा)

(लिखित उत्तर)

श्री मुरारी प्रसाद गौतम,मंत्री: जिलाधिकारी, औरंगाबाद द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि ग्राम पंचायत सोनहुली में पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु चयनित भूमि खाता नं0-118, खेसरा 43, रकवा 50 डी0 भूमि का चयन कर प्रस्ताव प्राप्त हुआ है । अनुश्रवण समिति की समीक्षात्मक बैठक में भूमि का चयन कर लिया गया था, परंतु भूमि स्वीकृति के उपरांत सोनहुली के ग्रामीण जनता द्वारा पंचायत सरकार भवन निर्माण से संबंधित परिवाद पत्र प्राप्त होने के आलोक में प्रासंगिक भूमि की जाँच की जा रही है, जाँचोपरांत विषयांकित भूमि पर उपयुक्त पाये जाने पर पंचायत सरकार भवन निर्माण की प्रक्रिया हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाएगी ।

अध्यक्ष: क्या आपको उत्तर मिल गया है ?

श्री ऋषि कुमार: जी सर।

अध्यक्ष: तो पूरक पूछें ।

श्री ऋषि कुमार: महोदय मेरा पूरक यह है कि उत्तर में यह दिया गया है कि जांच की जा रही है जमीन की, जो खाता नं0-118 खेसरा 43 है और महोदय मेरे हाथ में जांच रिर्पोट है अंचल अमीन की, जिसमें निष्कर्ष में उन्होंने कहा कि वह प्लॉट नं0-118 जो है पंचायत सरकार भवन हेतु रिक्वायर्ड भूखंड संभव प्रतीत नहीं पाया है एवं नदी के तटीय भूमि होने के कारण भवन निर्माण हेतु उपयोगी भूमि नहीं प्रतीत होता है जबकि जांच रिपोर्ट चली गयी उसके बाद भी उत्तर में लिखा हुआ है। इसमें महोदय जिला पंचायती राज पदाधिकारी की भूमिका संदिग्ध है और वे जानबुझकर इसको रोक रहीं हैं कि वह बने नहीं दूसरे प्लॉट पर, जबकि दूसरा प्लॉट संख्या वहां दिया गया है उनको..

अध्यक्षः आप पूरक पूछ लीजिये।

श्री ऋषि कुमारः तो क्या सरकार माननीय मंत्री जी जो है जिला पंचायत राज पदाधिकारी पर कार्रवाई करने का विचार रखते हैं ?

अध्यक्षः माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग । माननीय सदस्य ने सूचना भी दिया है ।

श्री मुरारी प्रसाद गौतम,मंत्रीः माननीय सदस्य ने जो जानकारी दी है, मुझसे व्यक्तिगत रूप से मिलकर भी जानकारी दी है और जो भूमि पूर्व से चयनित हुई है और पंचायत सरकार भवन बनाने योग्य है तो निश्चित तौर पर उस भूमि पर हमलोग पंचायत सरकार भवन बनाने का कार्य करेंगे ।

श्री ऋषि कुमार : महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो जिला पंचायती राज पदाधिकारी हैं जो जानबुझकर अंचल अमीन की रिपोर्ट को दबा कर बैठी हैं। क्या उनके ऊपर ये एक्शन लेने का काम करेंगे ?

अध्यक्षः माननीय मंत्री ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, अगर आपको पूरक पूछना है तो ऊंगली उठाईए, हम आपको समय दे देंगे । माननीय प्रश्नकर्त्ता अभी प्रश्न पूछ रहे हैं और माननीय मंत्री जवाब दे रहे हैं तो अन्य माननीय सदस्य को इसमें प्रवेश करने की इजाजत नहीं दी जायेगी । माननीय मंत्री।

श्री मुरारी प्रसाद गौतम,मंत्रीः अगर जिला पंचायती राज की भूमिका संदिग्ध दिखेगी तो निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई की जायेगी ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या- 1494(श्री अखतरूल ईमान,क्षेत्र सं0- 56,अमौर)</u>

(अनुपस्थित)

टर्न-5/मधुप/15.03.2023

<u>तारांकित प्रश्न संख्या-1495(श्री ललित नारायण मंडल, क्षेत्र सं0 157 सुलतानगंज)</u>

श्री श्रवण कुमार, मंत्री (लिखित उत्तर) : आंशिक स्वीकारात्मक है । जिला द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि शाहकुंड प्रखंड में स्थित सुखसरोवर तालाब के संबंध में समाहर्त्ता, भागलपुर के न्यायालय में दाखिल-खारिज पुनरीक्षण वाद सं0- 51/2014-15 निष्पादन हेतु विचाराधीन है । वाद के निपटारा होने के उपरांत नियमानुसार समुचित कार्रवाई की जाएगी ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य मंडल जी, आपको उत्तर प्राप्त है ?

श्री ललित नारायण मंडल : जी सर, हम संतुष्ट हैं लेकिन जानना चाहते हैं कि जल्दी कार्य शुरू हो जाय तो अच्छा रहेगा ।

अध्यक्ष : आप जब संतुष्ट हो गये तो अब क्या, वह तो जल्दी होगा तभी तो आप संतुष्ट हो गये।

श्री ललित नारायण मंडल : कार्य जल्दी शुरू हो जाय, यही है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री ललित नारायण मंडल : धन्यवाद, सर ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या-1496 (श्री राणा रणधीर, क्षेत्र सं0 18, मधुबन)</u>

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

<u>तारांकित प्रश्न संख्या-1497 (श्री दिलीप राय, क्षेत्र सं0 26, सुरसंड)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री मुरारी प्रसाद गौतम, मंत्री : स्वीकारात्मक । जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि पुपरी प्रखंड के बौराबाजीतपुर पंचायत में पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु भूमि चिन्हित करने के लिए अंचलाधिकारी, पुपरी को निदेशित किया गया है एवं सुरसंड प्रखंड के रधाउर पंचायत में पंचायत सरकार भवन निर्माण के लिए उपयुक्त भूमि का चयन कर लिया गया है, जिसकी सूची जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी के पत्रांक-314 दिनांक 01.02.2023 द्वारा विभाग को प्राप्त है । पुपरी प्रखंड के बौराबाजीतपुर पंचायत में उपयुक्त भूमि उपलब्ध होने तथा पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु नये मॉडल की तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त होते ही नियमानुसार पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी ।

अध्यक्ष : आपको उत्तर प्राप्त है ?

श्री दिलीप राय : जी । समय-सीमा बता दिया जाय, कब तक होगा ?

अध्यक्ष : आप समय-सीमा जानना चाहते हैं । माननीय मंत्री जी ।

श्री मुरारी प्रसाद गौतम, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जो नया मोडल प्रस्तावित है, जैसे ही प्रशासनिक स्वीकृति मिल जाती है, जल्द निर्माण कार्य पूर्ण करा लिया जायेगा ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या-1498 (श्री आलोक रंजन, क्षेत्र सं0 75, सहरसा)</u>

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

<u>तारांकित प्रश्न संख्या-1499 (श्री प्रणव कुमार, क्षेत्र सं0 165, मुंगेर)</u>

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या-1500 (श्री अरूण सिंह, क्षेत्र सं0 213, काराकाट)

श्री सुरेन्द्र राम, मंत्री (लिखित उत्तर) : 1. स्वीकारात्मक है ।

2. अस्वीकारात्मक है ।

3. वस्तुस्थिति यह है कि राज्य सरकार के सात निश्चय कार्यक्रम के तहत राज्य के प्रत्येक अनाच्छादित अनुमंडल में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तथा प्रत्येक अनाच्छादित जिला में एक महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जा चुकी है ।

उल्लेखनीय है कि रोहतास जिला अन्तर्गत तीन अनुमंडलों में कुल 5 (पाँच) राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान संचालित हैं । बिक्रमगंज अनुमंडल में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, भेलारी की स्थापना की जा चुकी है ।

रोहतास जिलान्तर्गत कुल 5(पाँच) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान संचालित हैं, जो निम्नवत है :-

क्र0सं0	अनुमंडल का नाम	संस्थान का नाम
1.	डेहरी	(i)औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, डेहरी ऑन सोन
		(ii) औद्योगिकप्रशिक्षण संस्थान,तुम्बा,रोहतास(LWE)
2.	सासाराम	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सासाराम
3.	बिक्रमगंज	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, भेलारी
4.	जिला स्तरीय	महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, रोहतास

रोहतास जिलान्तर्गत स्थापित सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में बिक्रमगंज अनुमंडल सहित अन्य सभी अनुमंडलों के इच्छुक युवक/युवती तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त करने के पात्र हैं ।

उपर्युक्त के अतिरिक्त रोहतास जिले में कोई अन्य सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

अध्यक्ष : माननीय अरूण बाबू ।

श्री अरूण सिंह : जी, उत्तर मिला है ।

अध्यक्ष : हाँ उत्तर मिला है तो आप पूरक पूछिये ।

श्री अरूण सिंह : महोदय, जो हमारा प्रश्न है उस प्रश्न में औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र खोलने की हम माँग किये हैं । महोदय, भेलारी जो गाँव है यह बिक्रमगंज अनुमंडल का ही गाँव है लेकिन यह भेलारी गाँव बिक्रमगंज अनुमंडल और सासाराम अनुमंडल के बोर्डर पर है । यह शुद्ध रूप से ग्रामीण इलाके हैं जहाँ आने-जाने का कोई मेन रास्ता नहीं है । इसलिए मैं माँग करना चाहता हूँ कि डेहरी में जिस तरह से दो प्रशिक्षण केन्द्र खोला

गया है, बिक्रमगंज बड़ा अनुमंडल है इसलिए बिक्रमगंज में एक और प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का विचार सरकार रखती है ?

श्री सुरेन्द्र राम, मंत्री : चूँकि स्थिति यह है कि एक अनुमंडल में सिर्फ एक ही औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलना है तो बिक्रमगंज अनुमंडल में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भेलारी में यह ऑलरेडी पहले से खुल चुका है । आगे कहीं अभी इस तरह का विचार नहीं है कि एक अनुमंडल में दो-दो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खुलेगा । यदि खुलेगा तो आपकी बातों पर विचार रखते हुए आगे वहाँ देखा जायेगा ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य मिश्रा जी, एक मिनट आप बैठ जाइये ।
माननीय प्रश्नकर्ता सदस्य ।

श्री अरूण सिंह : महोदय, मैं कह रहा हूँ कि बिक्रमगंज अनुमंडल और सासाराम अनुमंडल के बोर्डर पर यह है और शुद्ध रूप से ग्रामीण इलाके हैं, हम प्रश्न जब कर रहे थे तबतक हमको जानकारी नहीं थी कि भेलारी में ही ऐसा कोई प्रशिक्षण केन्द्र खुला है, एकदम निरीह देहात में है जहाँ कोई सड़क नहीं है । चूँकि डेहरी में पहले से दो है और बड़ा अनुमंडल होने के चलते हम बिक्रमगंज में एक और प्रशिक्षण केन्द्र, अगर कहीं आठों प्रखंड में कोई एक मुख्यालय में खुलता तो इसकी उपयोगिता होती लेकिन वह ग्रामीण इलाके में खुला है और दिनारा प्रखंड का सबसे सुदूर इलाका है वह । लोग नहीं जा सकते हैं, अब किसलिए खोल दिया गया मैं इस संदर्भ में नहीं जाना चाहता हूँ लेकिन वह बहुत निर्जन जगह पर है जहाँ कोई आता-जाता नहीं है और हमको जानकारी भी नहीं थी कि वहाँ कोई प्रशिक्षण केन्द्र चलता है ।

इसलिए बिक्रमगंज अनुमंडल के किसी प्रखंड मुख्यालय में यह खोला जाय तो इससे वहाँ के बच्चे ज्यादा लाभान्वित होंगे ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग, आपने तो बहुत स्पष्ट कहा ।

श्री सुरेन्द्र राम, मंत्री : चूंकि हम तो स्पष्ट कर चुके हैं कि एक अनुमंडल में एक ही औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खुलना है जो पहले खुल चुका है और आगे कहीं उस तरह का होगा तो आपकी बातों पर विचार रखा जायेगा ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य मिश्रा जी ।

श्री संतोष कुमार मिश्र : महोदय, हमारे रोहतास जिला में ही सासाराम अनुमंडल में भी अगर देखिएगा तो दो-दो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हैं, डेहरी अनुमंडल में भी दो-दो है तो बिक्रमगंज तो स्वाभाविक रूप से बहुत बड़ा ही अनुमंडल है और जबकि उसके प्रखंडों में भी नहीं खुला हुआ है तो यह प्रावधान तो होना चाहिए निश्चित रूप में कि बिक्रमगंज में ही खुलना चाहिए किसी न किसी उसके प्रखंड में । बिक्रमगंज अनुमंडल से संबंधित काराकाट प्रखंड है जहाँ से माननीय सदस्य विधायक हैं, बिक्रमगंज प्रखंड

अपने है, संझौली प्रखंड है, तीनों में से किसी एक प्रखंड को चयनित करके वहाँ कहीं इसको कर दें क्योंकि सुदूर इलाके में देने से क्या फायदा होगा ? सासाराम में ऑलरेडी दो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान चल रहे हैं, डेहरी अनुमंडल में दो-दो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान चल रहे हैं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सरकार के जो नीतिगत फैसले हुए हैं अनुमंडल में एक, उसके संबंध में उन्होंने जानकारी देने का काम किया । आप सुनिए । फिर भी मंत्री जी ने कहा कि इस तरह का अगर खोलने का कोई निर्णय होगा तो माननीय सदस्य से मैं बात करूँगा और उनकी बात सुनकर जो उचित कार्रवाई होनी चाहिए हम उचित कार्रवाई करेंगे ।

श्री संतोष कुमार मिश्र : महोदय, मेरा एक और प्रश्न है ।

अध्यक्ष : नहीं-नहीं । अब आप बैठ जायं ।

तारांकित प्रश्न संख्या-1501(श्री हरीभूषण ठाकुर''बचोल'',क्षेत्र सं0 35 बिस्फी)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या-1502(श्रीमती ज्योति देवी, क्षेत्र सं0 228 बाराचट्टी(अ0जा0)

(माननीय सदस्या अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या-1503(श्री अशोक कुमार, क्षेत्र सं0 132 वारिसनगर)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप पूरक पूछें ।

श्री अशोक कुमार : जवाब नहीं आया है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग ।

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : महोदय, स्वीकारात्मक ।

वस्तुस्थिति यह है कि करेह नदी के बायीं तरफ स्थित करेह तटबंध के कि0मी0 21.50 एवं कि0मी0 28.00 पर शिवाजीनगर प्रखंड के छतौनी एवं लालपुर स्थल के पास ए0एफ0एस0 पूर्व से निर्मित है । कि0मी0 21.50 पर स्थित स्लूईस कार्यकारी है। जबकि कि0मी0 28.00 पर स्थिल स्लूईस के मरम्मति/पुर्नस्थापन की आवश्यकता है । प्रश्नगत क्षेत्र से जल निकासी/पटवन हेतु पूर्व से निर्मित चैनल में आंशिक रूप से गाद भरा हुआ है । प्रश्नगत स्थल से जल निकासी/पटवन हेतु विस्तृत सर्वेक्षण एवं तकनीकी संभाव्यता के उपरान्त अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी ।

जल निकासी/पटवन की समस्या के निदान हेतु मुख्य अभियंता, समस्तीपुर को विभागीय पत्रांक-1458 दिनांक-14.03.2023 से प्रतिवेदन उपलब्ध कराये जाने हेतु निदेशित किया गया है ।

श्री अशोक कुमार : महोदय, माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि इसी आने वाले फाइनेंशियल ईयर में इस कार्य को करा दिया जाय तो बड़ा उपकार होगा ।

अध्यक्ष : माननीय जल संसाधन मंत्री ने कार्रवाई शुरू कर दी है और मुख्य अभियंता को उन्होंने लिखा भी है, प्रतिवेदन भी माँगा है । आप संतुष्ट होइये, सरकार कार्रवाई करने में लगी है।

श्री अशोक कुमार : संतुष्ट हैं लेकिन आने वाले फाइनेंशियल ईयर में काम पूरा हो जाय ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : महोदय, मैंने अपने जवाब में कहा है कि एक कार्यरत है एंटी फ्लड स्लूईस है, दूसरा में रिपेयर की जरूरत है और कुछ गाद भी भरा हुआ है । यह फाइनेंशियल ईयर तो 31 मार्च को खतम हो जायेगा, अगले फाइनेंशियल ईयर में काम हो जायेगा ।

श्री अशोक कुमार : धन्यवाद । आने वाले फाइनेंशियल ईयर में ।

अध्यक्ष : अब तो अगला वित्तीय वर्ष आने ही वाला है ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 1504 (श्री जनक सिंह, क्षेत्र सं0 116 तरैया)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या-1505 (श्री आलोक रंजन, क्षेत्र सं0 75, सहरसा)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या-1506 (श्री कृष्णनंदन पासवान, क्षेत्र सं0 13 हरसिद्धि(अ0जा0)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या-1507 (श्रीमती वीणा सिंह, क्षेत्र सं0 129 महनार)

अध्यक्ष : माननीय सदस्या श्रीमती वीणा सिंह, आपको प्रश्न का जवाब उपलब्ध है ?

श्रीमती वीणा सिंह : नहीं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, पंचायती राज आप जवाब पढ़ दें ।

श्री मुरारी प्रसाद गौतम, मंत्री : महोदय, स्वीकारात्मक ।

बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 156(1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के आलोक में वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रश्नगत नाला का निर्माण कार्य

यथाशीघ्र पूर्ण करने हेतु संबंधित ग्राम पंचायत के मुखिया/पंचायत सचिव को निदेशित किया गया है ।

श्रीमती वीणा सिंह : महोदय, काम जल्दी पूरा करा दिया जाय । बरसात में काफी दिक्कत होती है।

श्री मुरारी प्रसाद गौतम, मंत्री : बरसात अभी आने में बहुत टाईम है ।

टर्न-6/आजाद/15.03.2023

तारांकित प्रश्न सं0-1508(श्री राम रतन सिंह,क्षेत्र सं0-143,तेघड़ा)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप पूरक पूछिए ।

श्री राम रतन सिंह : अध्यक्ष महोदय, इसमें उत्तर संलग्न नहीं है । इसलिए जरा उत्तर की जानकारी हो जायेगी, तब न पूरक प्रश्न पूछेंगे ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, 1. स्वीकारात्मक है ।

2. स्वीकारात्मक है ।

3. वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पुल का डी0पी0आर0 राज्य योजनान्तर्गत तैयार किया जा रहा है । निधि की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के आधार पर अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी ।

श्री राम रतन सिंह : माननीय मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद और हम चाहेंगे कि इस बरसात के पहले पुल का निर्माण हो जाय ताकि आम लोगों का जो आवागमन सही ढंग से नहीं हो पा रहा है, उसमें कठिनाई हो रही है, इसमें सहुलियत हो ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री : अभी तो इसका डी0पी0आर0 बनाया जा रहा है, जैसे होगा, उसको देखेंगे ।

श्री राम रतन सिंह : ठीक है ।

तारांकित प्रश्न सं0-1509(श्री मुहम्मद इजहार असफी,क्षेत्र सं0-55,कोचाधामन)

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि किशनगंज जिलान्तर्गत प्रश्नगत बरबट्टा से मस्तान चौक जाने वाली पथ में मौधो, अलता और मस्तान चौक अवस्थित है ।

अत: तकनीकी संभाव्यतायें, संसाधन की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के अनुरूप नाला निर्माण का विचार किया जायेगा ।

श्री मुहम्मद इजहार : शुक्रिया महोदय ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0-1510 (श्री हरिशंकर यादव,क्षेत्र सं0-108,रघुनाथपुर)</u>

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ की लम्बाई 700 मीटर है, जो ईटीकृत है । यह पथ किसी कोर नेटवर्क में शामिल नहीं है। प्रश्नाधीन रघुनाथपुर प्रखंड के रघुनाथपुर गांव एवं राधे बाबा को पी0एम0जी0एस0वाई0 योजनान्तर्गत निर्मित रघुनाथपुर से अहिर टोला पथ से सम्पर्कता प्राप्त है । लहलादपुर को पी0एम0जी0एस0वाई0 योजनान्तर्गत निर्मित नरहन से हरपुर वाया लहलादपुर पथ से सम्पर्कता प्राप्त है । इस प्रकार प्रश्नाधीन एलाईनमेंट में उल्लेखित सभी बसावटों को एकल सम्पर्कता प्राप्त है ।

अत: दोहरी सम्पर्कता का मामला होने के कारण पथ निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

श्री हरिशंकर यादव : अध्यक्ष महोदय, जो यह जवाब आया है, जो 70-80 गांव के लोग आकर बसे हैं जिस रोड पर, वह रोड अलग है और ये लोग दोनों रोड के बीच में है । नक्शा में रोड भी है । कच्चा रास्ता है और किसी भी रोड से उसकी सम्पर्कता नहीं है, लोग ऐसे ही आते-जाते हैं । जो अधिकारी ऐसी रिपोर्ट दिये हैं, वे गलत रिपोर्ट दिये हैं ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, इसलिए हम इसका नक्शा मंगवा करके देख लिये हैं, हमारे पास इसका नक्शा भी है और साथ ही साथ हम कोरनेट के साथ तस्वीर भी मंगा लिये हैं महोदय, जो कि स्थिति ठीक लग रही है और इसका कनेक्शन नेटवर्क भी ठीक बताया जा रहा है ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0-1511(श्री अखतरूल ईमान,क्षेत्र सं0-56,अमौर)</u>

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

<u>तारांकित प्रश्न सं0-1512(श्रीमती नीतु कुमारी,क्षेत्र सं0-236,हिसुआ)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री संजय झा, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि नवादा जिलांतर्गत फुलवरिया जलाशय से दायाँ मुख्य नहर एवं बायां मुख्य नहर निकलती है । बायां मुख्य नहर के चेन संख्या 215 से बायां शाखा नहर निकलती है, जो हिसुआ विधान सभा क्षेत्र के नरहट तक जाती है ।

फुलवरिया जलाशय योजनान्तर्गत नहर वितरण प्रणाली का खरीफ वर्ष 2022 में निर्धारित सिंचाई लक्ष्य 6180 हेक्टेयर क्षेत्र के विरूद्ध 5023 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई है ।

फुलवरिया जलाशय योजनान्तर्गत नहर वितरण प्रणाली का जीर्णोद्धार कार्य सात निश्चय पार्ट-2 के अंतर्गत ''हर खेत तक सिंचाई का पानी'' योजना के तहत

कराया जाना प्रस्तावित है । इस योजना को वित्तीय वर्ष 2023-24 में पूर्ण करने का लक्ष्य है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप पूरक पूछिए ।

श्रीमती नीतु कुमारी : अध्यक्ष महोदय, मेरा पूरक यही है कि जो अन्सर मिला है, इससे संतुष्ट हूँ लेकिन जल्दी करवा दिया जाय चूँकि नवादा जिला बिहार का सबसे पिछड़ा जिला है और वहां के किसान लोग बहुत परेशान हैं और सुखाड़ की स्थिति को देखते हुए समय पर पूरा किया जाय ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, इसपर त्वरित कार्रवाई कर रहे हैं, तभी तो आप संतुष्ट हो गई, इसलिए आप स्थान ग्रहण कीजिए ।

श्रीमती नीतु कुमारी : बहुत-बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी को ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0-1513(श्री राहुल तिवारी,क्षेत्र सं0-198,शाहपुर)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, संभाव्यता प्रतिवेदन प्राप्त कर संसाधन की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के आलोक में जल जमाव से स्थायी समाधान संबंधी अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री राहुल तिवारी ।

श्री राहुल तिवारी : महोदय, उत्तर मिल गया है ।

अध्यक्ष : आप पूरक पूछिए ।

श्री राहुल तिवारी : पूरक नहीं है । विभाग ने स्वीकार किया है मेरी समस्या को, जो मैंने उठाया था । विभाग अग्रेतर कार्रवाई के लिए प्रेरित है, आगे बढ़ रही है, इसलिए विभाग को हम धन्यवाद देते हैं ।

अध्यक्ष : आप माननीय मंत्री जी को धन्यवाद दे रहे हैं ।

श्री राहुल तिवारी : जी-जी ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0-1514(श्री नीरज कुमार सिंह,क्षेत्र सं0-45,छातापुर)</u>

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

<u>तारांकित प्रश्न सं0-1515(डॉक्टर संजीव कुमार,क्षेत्र सं0-151,परबता)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री : 1- वस्तुस्थिति यह है कि गंगा नदी पर सुलतानगंज से अगुवानी घाट के बीच बन रहे फोरलेन पुल का निर्माण प्रगति पर है, जिसे दिसम्बर, 2023 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है ।

2- 30 अप्रैल 2022 को इस पुल के एक स्पैन कार्य के प्रगति के दौरान दुर्घटना होने के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था, उक्त क्षतिग्रस्त स्पैन को तोड़ कर नये सिरे से तैयार करने का कार्य प्रगति पर है ।

3- दुर्घटना की जाँच प्रतिष्ठित संस्थान आई0आई0टी0,बॉम्बे, आई0आई0टी0 रूड़की एवं एन0आई0टी0 पटना के विशेषज्ञ प्रोफेसर द्वारा कराया जा रहा है ताकि इसके सही कारणों का पता लगाया जा सके ।

प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर अग्रेत्तर कार्रवाई की जायेगी ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपको जवाब मिल गया है ?

डॉक्टर संजीव कुमार : अध्यक्ष महोदय, जवाब मिल गया है । अध्यक्ष महोदय, मेरा पूरक है कि माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, जवाब मिला है कि 2023 तक वह पुल अगुवानी सुल्तानगंज कंप्लीट हो जायेगा । मैं माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि वर्ष 2021 में भी जब पूछा था तब बोला गया था कि दिसम्बर, 2021 तक हो जायेगा, वर्ष 2022 में जब मार्च में पूछा गया था तब बोला गया था कि दिसम्बर, 2022 तक हो जायेगा और इस बार बोला गया है कि दिसम्बर, 2023 तक हो जायेगा । उम्मीद करते हैं कि हो जाय और दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, वह पुल टूट गया था बीच में पिछले साल तो जवाब आया है तो मैंने पूछा था कि अभी तक इसपर कार्रवाई क्यों नहीं की गयी दोषी पदाधिकारियों पर, चाहे जो भी वहां पर हैं, इसमें तो इसका जवाब आया है कि आई0आई0टी0,बुम्बई, आई0आई0टी0, रूड़की और एन0आई0टी0, पटना से जॉच विशेषज्ञ प्रोफेसर गये हैं और इनके द्वारा जॉच कराया जा रहा है । लेकिन बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है अध्यक्ष महोदय कि एक साल में पुल टूटने का कारण पता नहीं चल पाया है । अगर कोई दुर्घटना फिर से घट जायेगा और किस कारण पुल टूटा, यह भी पता नहीं है, यह भी मैं माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूँ । वहां से मुझे कुछ फोटो आया है, वहां के स्टाफ ने मुझे दिया है तो मैंने डी0एम0 को, प्रधान सचिव को दिखाया । फिर से जो पिलर बना था, उसमें भी क्रेक आ गया । अब बताईए कि इतना डिजाईन में फॉल्ट है, स्ट्रक्चर में फॉल्ट है, फिर से सबको तोड़वाया जा रहा है तो बार-बार अगर ऐसा होगा, अगर उसपर आवागमन चालू हो जायेगा तो बड़ी दुर्घटना नहीं घट जाय, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसकी अविलम्ब जॉच हो और एक साल में जॉच रिपोर्ट तैयार करके दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए । चाहे अधिकारी हो या उसमें जो संवेदक लोग हों ।

अध्यक्ष : आपने सारी इनफॉरमेशन को दे दिया है । माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महादेय, स्पष्ट जवाब है । क्या इशुज है, यह तो जॉच के बाद पता चलेगा, पुल टूटने का कारण और हम सदस्य को निश्चिंत रहने के

लिए कहेंगे कि इस चीज को हम खुद रिव्यू मीटिंग में देख रहे हैं । एक बार जॉंच रिपोर्ट आ जायेगी तो जो दोषी होंगे, उसपर पूरी कार्रवाई की जायेगी और भविष्य में फिर से ऐसी घटना न हो क्योंकि आपने बताया कि तस्वीर आपको भेजी गयी है, जिसमें क्रेक आया है । इसलिए निर्णय लिया गया है कि क्षतिग्रस्त पिलर को तोड़कर नये सिरे से तैयार किया जायेगा तो भविष्य में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आये, इसको देखते हुए यह निर्णय लिया गया है ।

डॉक्टर संजीव कुमार : अध्यक्ष महोदय, मुझको पूछना है और यह बात माननीय मंत्री जी के संज्ञान में भी नहीं है, वह जो टूटा तो टूटा, लेकिन उसके बाद अभी एक महीने पहले नया पिलर का जो कंक्रीट हो रहा था, उसमें भी क्रेक आ गया है तो यह बहुत बड़ा मुद्दा है । इसको आप अपने स्तर से देखवा लें, मुझे उम्मीद है कि माननीय मंत्री जी इसको अच्छा से ही देखवायेंगे । धन्यवाद ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री : महोदय, अगर ऐसी कोई बात होगी तो जरूर दिखवा लिया जायेगा । किसी के जान-माल का नुकसान न हो, पैसे की बर्बादी न हो, सरकार इसका पूर्ण रूप से ध्यान रखने का काम करेगी ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब स्थान ग्रहण करें ।

अब प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ । जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हों, उसे सदन पटल पर रख दिये जायं ।

अब कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना ली जायेगी ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 15.03.2023 के लिए निम्न माननीय सदस्यों से कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें प्राप्त हुई है ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद, श्री विजय कुमार खेमका ।

आज सदन में वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में सम्मिलित अनुदानों की मांगों पर वाद-विवाद एवं मतदान का कार्यक्रम निर्धारित है ।

अतः बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-172(3) एवं 47(2) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण कार्य-स्थगन प्रस्ताव के सभी सूचनाओं को अमान्य किया जाता है ।

टर्न-7/शंभु/15.03.23

अध्यक्ष : अब शून्यकाल लिये जायेंगे ।

शून्यकाल

श्रीमती मंजू अग्रवाल : महोदय, गया जिला के शेरघाटी प्रखंड अन्तर्गत चेरकीडीह टोला नीमाडीह के पास जमुने नदी पर निर्माणाधीन आर0सी0सी0 पुलिया में संवेदक विश्वनाथ सिंह के द्वारा पूरी तरह से घटिया सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है । अतः निर्माणाधीन पुलिया में बरती गयी अनियमितता की जॉच की मांग करती हूँ ।

श्री इजहारूल हुसैन : महोदय, किशनगंज जिलान्तर्गत किशनगंज शहर के बीच अवस्थित रमजान नदी, जो डॉक नदी का एक भाग है, पर नमामि गंगे कार्यक्रम अधीन एसटीपी योजना की अति आवश्यकता है । अतः मैं उक्त स्थान में नमामि गंगे कार्यक्रम के अधीन एसटीपी योजना की स्वीकृति प्रदान करने की मांग सरकार से करता हूँ ।

श्री गोपाल रविदास : महोदय, पटना जिले में मनरेगा के सक्रिय मजदूरों की संख्या घटकर 35 हजार से 16 हजार हो गयी है । इसका मूल कारण आधार कार्ड और बैंक एकान्ट का एनपीसीआई से लिंक नहीं होना है । अतः एनपीसीआई से लिंक करने की अनिवार्यता खत्म करने की मांग सरकार से करता हूँ ।

श्री राम रतन सिंह : महोदय, सड़क दुर्घटना या अन्य आपदा के कारण मृत्यु होने पर दी जानेवाली पारिवारिक लाभ की राशि कम से कम पॉच लाख रूपये अग्रिम के रूप में प्रखंड कार्यालय में उपलब्ध कराने की मांग सरकार से करता हूँ ।

श्री महानन्द सिंह : महोदय, अरवल जहानाबाद में होमगार्ड की बहाली के लिए एक साल से सारा प्रक्रिया पूरा होने के बावजूद अभी तक सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं मिला है । होमगार्ड के लिए सफल अभ्यर्थियों को तत्काल बहाल करने की मांग करता हूँ ।

श्री भरत बिन्द : महोदय, कैमूर जिलान्तर्गत भारतमाला परियोजना में किसानों से होनेवाली भूमि अधिग्रहण का मुआवजा एक करोड़ रूपये प्रति एकड़ देने की सरकार से मांग करता हूँ।

श्री मुकेश कुमार यादव : महोदय, सीतामढ़ी जिला प्रखंड बोखरा मेन रोड बनौल हनुमान मंदिर अमिन साहब टोला भाया ब्रह्मस्थान तक की सड़क ग्रामीण कार्य एजेन्सी पुपरी द्वारा दिनांक 23.01.2020 को शुरू होने के साथ ही बंद हो गया । उक्त सड़क को जनहित में निर्माण कराने की मांग सरकार से करता हूँ ।

श्री अजीत कुमार सिंह : महोदय, बिहार के नियोजित शिक्षकों को एन0आइ0ओ0एस0 से प्रशिक्षण की तिथि से ही ट्रेंड शिक्षकों का वेतन देने तथा 15 फीसदी वेतन बढ़ोत्तरी के साथ, एरियर की राशि के शीघ्र भुगतान करने की मांग करता हूँ ।

श्री रामवृक्ष सदा : महोदय, खगड़िया जिला के अलौली विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत हथवन पंचायत के गढ़बन्नी, भिखारी घाट पंचायत के भिखारी घाट एवं गौराचक पंचायत के गौराचक में जर्जर हो चुके लोहे के पुल की मरम्मति करते हुए आर0सी0सी0 पुलिया के निर्माण की मांग करता हूँ ।

मो0 इजहार अशफी : महोदय, किशनगंज जिला अन्तर्गत किशनगंज प्रखंड के बेलवा पंचायत अन्तर्गत शर्मा टोला और टैंगरभारी में हर वर्ष महानन्दा नदी का जलस्तर बढ़ने से भीषण कटाव होता है जिससे सैंकड़ों एकड़ उपजाऊ जमीन और दर्जनों घर नदी में विलीन हो जाता है । मैं सरकार से उक्त दोनों स्थानों पर कटाव निरोधक कार्य कराने की मांग करता हूँ ।

श्री रामबली सिंह यादव : महोदय, जहानाबाद जिला के बराबर की पहाड़ी पर गुप्तकालीन सतधरवा गुफा को देखने के लिए पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है, जिनके सुविधा के लिए गुफा के आसपास शौचालय एवं पेयजल की व्यवस्था करने की मांग करता हूँ ।

श्री अजय कुमार : महोदय, राज्य में मदरसा एवं संस्कृत विद्यालय अनुदानित विद्यालय है ।

अध्यक्ष : आपने लिखा है अनुदानित नहीं है ।

श्री अजय कुमार : ऐसा लिखा है सर ?

अध्यक्ष : कोई बात नहीं, मैंने आपका ध्यान आकृष्ट कराया । आप पढ़िये ।

श्री अजय कुमार : महोदय, राज्य में मदरसा एवं संस्कृत विद्यालय अनुदानित विद्यालय है, जिसे पूर्ण अनुदान मिलता है जबकि अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों को पूर्ण अनुदान नहीं मिलता है । मैं सरकार से मदरसा एवं संस्कृत विद्यालयों के समान माध्यमिक विद्यालयों को भी पूर्ण अनुदान देने हेतु सरकार से मांग करता हूँ ।

श्रीमती भागीरथी देवी : (माननीय सदस्या सदन में अनुपस्थित) ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अमरजीत कुशवाहा ।

श्री अमरजीत कुशवाहा : महोदय, सिवान जिला के हसनपुरा निवासी नसीब कुरैशी को जिला सारण के रसूलपुर थाना अन्तर्गत योगियां गांव में दिनांक 08.03.2023 को गाय का मांस ले जाने का अफवाह फैलाकर मॉबलिंचिंग कर हत्या कर दी गयी, ऐसे नफरती साम्प्रदायिक ताकतों को स्पीडी ट्रायल चलाकर फांसी की सजा की मांग करता हूँ ।

श्री सूर्यकान्त पासवान : महोदय, राज्य सरकार ने वर्ष 2014 में राज्य के सभी छात्राओं और एस0सी0/एस0टी0 छात्रों को के0जी0 से पी0जी0 तक मुफ्त शिक्षा देने का फैसला किया था । सरकार के इस फैसले को लागू कराने की मांग करता हूँ ।

श्री अरूण सिंह : महोदय, रोहतास जिला अन्तर्गत राजपुर प्रखंड के महुअरी गांव निवासी आकाश कुमार पासवान की छः वर्षीय बेटी रिया कुमारी के बलात्कारी, वेधैला थाना कांड सं0-20/2023 के नामजद अभियुक्त को स्पीडी ट्रायल कराकर सजा एवं पीड़ित परिवार को सुरक्षा एवं मुआवजा की मांग करता हूँ ।

श्री रणविजय साहू : महोदय, समस्तीपुर जिला के पटोरी थाना अन्तर्गत हसनपुर टांरा में दिनांक 12. 03.2023 को छात्र अमनदीप कुमार को अपराधियों ने साजिश कर निर्मम हत्या कर दिया, जिसका कांड सं0-183/23 है । घटना में शामिल अपराधियों को शीघ्र गिरफ्तारी, उच्च स्तरीय जॉच एवं पीड़ित परिवार को 10 लाख मुआवजे की मांग करता हूँ ।

श्री मनोज मंजिल : महोदय, गुजरात दंगों पर आधारित बीबीसी डॉक्यूमेंट्री फिल्म को सरकार से सदन में दिखाये जाने की मांग करता हूँ ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आपने पढ़ दिया, स्थान ग्रहण कीजिए ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : (माननीय सदस्य सदन में अनुपस्थित)

श्री सत्यदेव राम : महोदय, पटना उच्च न्यायालय ने 74वां संविधान संशोधन का हवाला देते हुए नगर निकायों में चतुर्थवर्गीय कर्मियों के पद समापन का विरोध किया है । विकास आयुक्त के नेतृत्व वाली उच्च स्तरीय समिति ने आउटसोर्स की जगह स्थायी कर्मियों से सफाई कार्य कराने का सुझाव दिया है । इसकी मांग करता हूँ ।

टर्न-8/पुलकित/15.03.2023

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य आपने शून्यकाल की सूचना को पढ़ दिया है, अब अपना स्थान ग्रहण करें ।

(व्यवधान)

आपने अपना शून्यकाल पढ़ दिया । माननीय सदस्य श्री ललित नारायण मंडल ।

श्री ललित नारायण मंडल : अध्यक्ष महोदय, बिहार के पंचायतों एवं नगर निकायों के वार्ड परिसीमन में जनसंख्या की समरूपता लाने की मांग करता हूँ ।

श्री सुदामा प्रसाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, रोहतास जिला के डेहरी में 1984 से बंद डालमिया नगर कारखाने को जल्दी से चालू कराने की मांग करता हूँ ।

अध्यक्ष : धन्यवाद । अब ध्यानाकर्षण सूचनाएं ली जायेंगी ।

श्री मोहम्मद अनजार नईमी : अध्यक्ष महोदय, मेरा शून्यकाल 16 नंबर पर था, उसे नहीं पढ़वाया गया ।

अध्यक्ष : आपके शून्यकाल की सूचना 50 शब्दों से अधिक थी, इसलिए नहीं पढ़वाया गया । वह इसलिए नहीं आया क्योंकि जो नियम बनाये गये हैं उस नियम के तहत शून्यकाल नहीं था इसलिए उसको अस्वीकृत कर दिया गया । माननीय सदस्य, अभी सत्र का कार्यकाल लम्बा है इसलिए पुनः अच्छे तरीके से शून्यकाल दीजियेगा ।

अब ध्यानाकर्षण सूचनाएं ली जायेंगी ।

ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकारी वक्तव्य

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री नंद किशोर यादव अपनी सूचना को पढ़ें ।

सर्वश्री नन्द किशोर यादव, प्रमोद कुमार एवं अन्य तीन सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार (पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

(अनुपस्थित)

नहीं हैं । माननीय सदस्य डॉ0 रामानुज प्रसाद अपनी सूचना को पढ़ें ।

सर्वश्री डॉ0 रामानुज प्रसाद, शकील अहमद खाँ एवं अन्य दो सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, सारण जिला के सोनपुर सहित पूरे बिहार में टोपोलैण्ड की जमीन का रजिस्ट्रेशन एवं म्यूटेशन (निबंधन एवं दाखिल-खारिज) टोपोलैण्ड के सर्वे के नाम पर रोक दिया गया था । टोपोलैण्ड के एरिया में पड़ने वाले दियारा इलाके में किसानों, गरीबों एवं छात्रों के साथ ही अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग तथा सामान्य वर्ग के गरीबी रेखा के नीचे जीवन-बसर करने वाले लोगों को इंदिरा आवास योजना एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण विकास योजना के साथ-साथ जमीन के कागजात के आधार पर मिलने वाले अन्य प्रमाण पत्र से बहुत बड़ी आबादी वंचित हो जा रही है । इन परिस्थितियों को देखते हुए मा0 पटना उच्च न्यायालय के आदेश

के आलोक में निबंधन (रजिस्ट्रेशन) शुरू हुआ, लेकिन म्यूटेशन का कार्य अभी भी नहीं हो रहा है, जिससे बहुत बड़ी जनसंख्या तमाम सुविधाओं से वंचित हो जा रही है। जैसे सोनपुर के दियारा इलाका के मात्र सात पंचायत में ही 2772 इंदिरा आवास की दावेदारी वाले गरीब परेशान हो रहे हैं । इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि टोपोलैण्ड के एरिया में कितनी बड़ी आबादी तमाम सुविधाओं से वंचित हो रही है ।

अतः उपरोक्त परिस्थितियों की ओर हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, इसमें समय चाहिए ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य इसमें समय चाहिए ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, समय निर्धारित किया जाए कि कब माननीय मंत्री जी इसका जवाब देंगे और सरकार कार्रवाई करेगी ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी समय का निर्धारण करके सूचना दे देंगे । इसी सत्र में आपके ध्यानाकर्षण सूचना का जवाब सरकार दे देगी, तिथि ये तय करेंगे ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद : बहुत-बहुत धन्यवाद ।

सभा के समक्ष प्रतिवेदनों का रखा जाना

अध्यक्ष : माननीय सभापति, प्रत्यायुक्त विधान समिति ।

श्री अजीत शर्मा, सभापति, प्रत्यायुक्त विधान समिति : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-211 (1) के तहत सप्तदश बिहार विधान सभा की प्रत्यायुक्त विधान समिति की सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित विशेष प्रतिवेदन सं0-1 की प्रति सदन पटल पर रखता हूँ ।

अध्यक्ष : अब सभा की कार्यवाही 02.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

टर्न-9/अभिनीत/15.03.2023

(अंतराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है । अब वित्तीय कार्य लिये जायेंगे ।

वित्तीय कार्य

माननीय सदस्यगण, उद्योग विभाग के अनुदान की मांग पर वाद-विवाद तथा सरकार का उत्तर एवं मतदान होगा । इसके लिए 3 घंटे का समय उपलब्ध है । विभिन्न दलों को उनकी सदस्य संख्या के आधार पर समय का आवंटन निम्न प्रकार किया जाता है । इसी समय में से सरकार को उत्तर के लिए भी समय दिया जायेगा ।

राष्ट्रीय जनता दल	- 58 मिनट
भारतीय जनता पार्टी	- 58 मिनट
जनता दल यूनाइटेड	- 33 मिनट
इंडियन नेशनल कांग्रेस	- 14 मिनट
सी0पी0आई0 (एम0एल0)	- 09 मिनट
हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा	- 03 मिनट
सी0पी0आई0 (एम0)	- 02 मिनट
सी0पी0आई0	- 02 मिनट
ए0आई0एम0आई0एम0	- 01 मिनट

माननीय मंत्री, उद्योग विभाग अपनी मांग प्रस्तुत करें ।

श्री समीर कुमार महासेठ, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''उद्योग विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 16,48,81,73,000/- (सोलह अरब अड़तालीस करोड़ इक्यासी लाख तिहत्तर हजार) रुपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय ।''

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, कल की दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद आज सदन में विपक्षी दल के माननीय सदस्यों के सदन में न होने की स्थिति में माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग द्वारा यह भाव प्रकट किया गया और सुझाव दिया गया कि विपक्ष भी सरकार का अंग ही हैं और उनके न रहने से सदन सूना है । उन्होंने विपक्ष के सभी सदस्यों को सदन में बुलाने का आसन से अनुरोध किया । आसन ने माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग के अनुरोध पर कांग्रेस विधायक दल के नेता श्री अजीत शर्मा जी से अनुरोध किया कि

वे माननीय नेता, विरोधी दल के समक्ष जायं और उन्हें आसन की भावना से अवगत करायें ताकि वे सदन में आयें और सदन की कार्यवाही में भाग लें । इसके बाद सदन के भोजनावकाश की अवधि में भी हमलोगों ने नेता विरोधी दल एवं अन्य विपक्षी दल के नेताओं से विमर्श भी किया । उन्हें सदन में भाग लेने का आग्रह किया ।

मैं पुनः कांग्रेस विधायक दल के नेता श्री अजीत शर्मा जी से अनुरोध करता हूं कि वे स्वयं जायं और विपक्ष के उन सभी माननीय सदस्यों को जिन्हें सदन से निष्कासित नहीं किया गया है उन्हें सदन में आने का आग्रह करें ।

श्री अजीत शर्मा : धन्यवाद महोदय ।

अध्यक्ष : माननीय संसदीय कार्य मंत्रीजी ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, ये आपने एक बड़ा ही प्रजातांत्रिक प्रणाली के अनुरूप निर्णय भी लिया है, पहल भी की है । जैसा कि हमने आज की कार्रवाई प्रारंभ होते समय ही कहा था कि विपक्षी दल के बिना सरकार भी अधूरी दिखती है और इसीलिए आप भी महसूस करते होंगे कि सदन की कार्यवाही में अगर विपक्षी सदस्य नहीं हैं तो यह बड़ा खालीपन महसूस होता है । इसीलिए हमने अनुरोध किया था और मैं आसन का विशेष रूप से आपका सरकार और महागठबंधन विधायक दल की तरफ से भी आभार प्रकट करता हूं कि आपने हमारी बातों का संज्ञान लिया और उन बातों का संज्ञान लेकर आपने इस दिशा में एक सार्थक पहल की । मुझे भी उसमें शामिल किया और कांग्रेस विधायक दल के नेता श्री अजीत जी से अनुरोध किया गया कि वे हमारे विपक्ष के नेता और सभी माननीय सदस्य से अनुरोध करें कि वे सदन की कार्यवाही में भाग लें । उसमें भी महोदय, हमारी चिंता, सरकार की चिंता या सत्तारूढ़ दल की चिंता इस बात से थी कि अभी जो सदन के सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक दायित्व होते हैं किसी सरकार के बजट को अंतिम रूप देना और उस अंतिम रूप देने के बाद अलग-अलग विभागों के जो मांगों की अनुदान होती हैं वह सदन की इजाजत से ही सरकार खर्च कर पाती है । बजट में हम अपनी योजनाएं बताते हैं और अनुदान की मांग में, उन योजनाओं के क्रियान्वयन में जो राशि खर्च होने की संभावना या अनुमान होता है उसके लिए हम सदन से इजाजत मांगते हैं । महोदय, विधायिका के जो कुछ महत्वपूर्ण संवैधानिक दायित्व हैं ये उनमें से एक हैं और जब विपक्षी दल, सरकार और इस सदन के अविभाज्य अंग हैं उनको अलग करके सदन की कल्पना नहीं की जा सकती है । वैसी स्थिति में आपने जो पहल करके इसे एक नतीजे तक पहुंचाने की कोशिश की है इसके लिए हम सरकार की तरफ से आपको धन्यवाद देते हैं और आभार भी प्रकट करते हैं । महोदय, हमलोग तो चाहते हैं कि स्वस्थ प्रजातंत्र की निशानी होती है सक्रिय और सकारात्मक विपक्ष । वे जब हमारी आलोचना करते हैं...

(इस अवसर पर माननीय नेता, विरोधी दल एवं अन्य विपक्षी माननीय सदस्यगण सदन में आ गये)

श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह : हमलोग आ गये ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : आ गये । महोदय, हम राघवेन्द्र जी की घोषणा का स्वागत करते हैं । आपलोग जो आ गये समझिए कि हमलोग तो पलक पाँवड़े विछाये बैठे थे कि आप आ ही जाइये । आपके बिना तो हमलोगों को अकेलापन महसूस हो रहा था । महोदय, हमने माननीय सदस्य या विपक्ष के नेता के साथ सभी माननीय सदस्यों को सदन में बुलाने का आग्रह भी किया था, आपने सार्थक पहल भी की इसलिए हमने आपके प्रति आभार भी जताया है और आपकी पहल पर हमारे विपक्ष के सभी सम्मानित सदस्य सदन में वापस आ गये इसलिए सरकार की तरफ से हम आप सभी सदस्यों के प्रति भी आभार प्रकट करते हैं । आपके आने से देखिए, आपके आने से तो सदन की रौनक ही बढ़ गयी है । आप नहीं थे तो इतना सूना लगता था इसलिए हम आसान के साथ इन्हें भी धन्यवाद देते हैं ।

अध्यक्ष : आप आये बहार लाये । माननीय सदस्यगण, मुझे प्रसन्नता है कि सदन की भावना और आसन के अनुरोध को नेता विरोधी दल एवं विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों ने बहुत ही पॉजीटिव रूप से लिया । मैं नेता विरोधी दल से आग्रह करता हूं कि वे इस विषय पर अपना पक्ष रखें ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देता हूं कि अपनी सदन की परंपरा को आपने आगे बढ़ाया । सदन में गतिरोध होते रहते हैं और सदन में बैठे सभी माननीय सदस्य वरीय हों या कनीय, सभी मिलकर सदन के गतिरोध को दूर करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये सदन दल से अलग नहीं है । सत्ता पक्ष हो या विपक्ष सभी सरकार के अंग हैं और विधायिका का मान लोकतंत्र में बराबर है । इस लोकतंत्र के मंदिर में सभी की जिम्मेवारी है कि जनता के विश्वास पर हम खड़े उतरें और संविधान के तहत जो हमें जिम्मेवारी मिली है, सत्ता पक्ष और विपक्ष जनता की आवाज बनकर बेहतर करने के लिए अपना सुझाव देना, आईना दिखाना और उस कार्य में सभी अपनी भूमिका जनता के हित में ही निभाते हैं । हम धन्यवाद देते हैं अपने सभी माननीय विधायकों को कि जिसने संयमित रूप से आपके आदेश के बाद, बाहर हमलोग बैठे थे...

..क्रमशः..

टर्न-10/हेमन्त/15.03.2023

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल(क्रमशः) : लेकिन माननीय सदस्य, कुछ नये सदस्य यह भूल जाते हैं कि विधायिका की भी अपनी एक जमात और एक जाति होती है और विधायिका दल से बंधी हुई नहीं होती है । विधायिका संविधान से बंधी हुई होती है । इसका सम्मान और गरिमा सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी हमको मिलकर रखना है और कोई ऐसी हल्की बात नहीं होनी चाहिए जिससे किसी को ठेस लगे । अध्यक्ष महोदय, आपको हमने अवगत भी कराया है कि इस तरह की व्यवस्था बदलती रहती है । आज धरना पर हम बैठे हैं, कल आप थे, परसो कोई और होगा, उसका भी सम्मान हो । क्योंकि लोकतंत्र की यही खूबसूरती है और उसमें व्यवधान, उसका उपहास या उसका मजाक उड़ाना कहीं-न-कहीं हमारी उस मानसिकता को प्रदर्शित करता है और एक चीज मैं कहना चाहूंगा-

''कभी किसी के चेहरे को मत देखो, उसके मन को देखो, क्योंकि सफेद रंग में वफा होती, तो नमक जख्मों की दवा होती ।''

महोदय, जैसे-जैसे नाम आपका ऊंचा होता है, वैसे-वैसे शांत रहना सीखिये, क्योंकि आवाज हमेशा सिक्कों में होती है, नोट को कभी बजते हुए नहीं देखा है । आप सत्ता में हैं और सत्ता की जिम्मेवारी बड़ी होती है । हम जब आसन पर थे, तो सत्ता पक्ष के लोग हमसे बड़े नाराज होते थे । इस बात को याद रखिये, क्योंकि सत्ता के संरक्षक मुख्यमंत्री भी होते हैं, लेकिन प्रतिपक्ष का संरक्षक आसन होता है और अध्यक्ष होते हैं । प्रतिपक्ष में खनक हो सकती है, लेकिन रुपया को शांत रहना चाहिए और हमने तो कल ही कहा था महोदय, कि कोई भी सदन की गरिमा न गिराये, हम प्रतिवाद करेंगे, अपनी बात को रखेंगे, अध्यक्ष से निवेदन, आग्रह करेंगे । जो अधिकार मिला है उसके द्वारा हम लोकतांत्रिक पद्धति से विपक्ष की भूमिका निभायेंगे और इसीलिए आग्रह किया था कि अगर जो किसी को गाहे-बगाहे उत्तेजना में सदन की गरिमा को कभी भी ठेस लगे, तो निश्चित तौर पर यह परंपरा रही है खेद व्यक्त करके, दुख व्यक्त करके, कई बार अवरोध पैदा हुआ है, तो हमने उसका समाधान किया है और समाधान कोई ऊपर से आकर नहीं करेगा, क्योंकि वरीय लोग जो बैठे हैं उसी के बीच में निकलता है । हम माननीय अजीत शर्मा जी और संसदीय कार्य मंत्री जी को भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस विषय को रखा है, लेकिन थोड़ी हड़बड़ी में कुछ ज्यादा गड़बड़ी हो जाती है । कल हमारी बात को ध्यान में रखा जाता, दोनों पक्ष के लोग खेद व्यक्त करें, तो समाधान निकलेगा और आगे व्यवस्थित ढंग से लोकतंत्र की खूबसूरती भी झलकेगी ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : आप असली बात तो भूल ही गये, असली बात न कहिये ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : महोदय, वह तो हम आपके लिए छोड़े थे । क्योंकि प्रस्ताव तो संसदीय कार्य मंत्री जी की ओर से आना चाहिए । क्योंकि आपने बुलाया, हमारे जो माननीय सदस्य हैं, सदन में आने की...

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, इनके दल की बात अगर हम करेंगे, तो यह तो...

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : संसदीय कार्य की जिम्मेवारी का आप निर्वहन करते हैं, उनको बुलायें और निलंबन वापस लें ।

अध्यक्ष : अब मैं सदन की अनुमति से माननीय सदस्य श्री लखेन्द्र कुमार रौशन, जिन्हें सदन द्वारा निलंबित किया गया था, उन्हें सदन में अपना पक्ष रखने के लिए बुलाता हूं । मार्शल, माननीय सदस्य को आप सदन में लायें ।

(इस अवसर पर माननीय सदस्य श्री लखेन्द्र कुमार रौशन मार्शल के साथ सदन में आये।)

माननीय सदस्य श्री लखेन्द्र कुमार रौशन जी, कल की घटना पर आपसे आग्रह है कि आप सदन की भावना और सदन के सम्मान को देखते हुए अपना पक्ष रखें ।

श्री लखेन्द्र कुमार रौशन : माननीय अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष सहित सभी सम्मानित विधान मंडल के सदस्यगण हम सब लोग लोकतंत्र के मंदिर में जिस अपेक्षा और आम जनता की आशा से आये हैं, उस अपेक्षा पर खरा उतरना हम सब लोग भी चाहते हैं । कहीं से भी हमारी और आपकी मानसिकता नहीं रहती है कि सदन के अंदर किसी प्रकार का अमर्यादित वातावरण बने । हम भी इस बात को बखूबी समझते हैं, इस विषय का सम्मान भी करते हैं । लेकिन जिस प्रकार यह घटनाक्रम हुआ, अध्यक्ष महोदय, उस चीज को पूरा सदन जान रहा है । मैं अपनी बातों को रख रहा था, तीन पूरक प्रश्न पूछने थे । दो पूरक प्रश्न पूछने के बाद माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा किन्हीं दूसरे सदस्य को उठाया गया प्रश्न पूछने के लिए, हमें लगा कि हमारा तीसरा पूरक प्रश्न बाकी है, हमें पूछना चाहिए । इसी बीच मैं अपना तीसरा पूरक प्रश्न पूछ रहा था, जो सेविका सहायिका का मामला था । हमने सरकार से ही प्रस्ताव रखा था कि सेविका सहायिका का मानदेय बढ़ाया जाय । माननीय मंत्री जी ने जवाब भी इस विषय पर दिया था, लेकिन जो भी घटनाक्रम हुआ, यह घटनाक्रम हमसे हो या विपक्ष के साथी से हो, आवेशित होकर प्रतिपक्ष के साथी के द्वारा इस प्रकार हमारे सामने कुछ अमर्यादित शब्द रखा गया और हममे भी उत्तेजना आयी, निश्चित रूप से हम में से किसी भी पक्ष में यह उत्तेजना नहीं आनी चाहिए । जो भी घटना घटी है, लोकतंत्र की

जीत होनी चाहिए, संविधान से देश चलता है, संविधान को हम मानते हैं । इस बात के लिए मैं दुख प्रकट करता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने सदन की भावना को देखते हुए कल की घटना पर दुख प्रकट किया है, खेद व्यक्त किया है । इसीलिए मैं सदन की अनुमति चाहता हूं कि इन्हें सदन की शेष अवधि से निलंबन मुक्त किया जाय ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''माननीय सदस्य, श्री लखेन्द्र कुमार रौशन को निलम्बन से मुक्त किया जाय।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

माननीय सदस्य श्री लखेन्द्र कुमार रौशन को निलंबन से मुक्त किया गया ।

टर्न-11/धिरेन्द्र/15.03.2023

अध्यक्ष : अब मैं माननीय सदस्य श्री सत्यदेव राम जी से आग्रह करता हूँ कि कल की घटना के संदर्भ में जो बातें हुई थी उसमें आपके प्रति भी कुछ आरोप लगे हैं । आपसे आग्रह है कि आप भी सदन में अपना पक्ष रखें ।

श्री सत्यदेव राम : अध्यक्ष महोदय, मेरे ऊपर जो भी आरोप लगे हैं, वे बिल्कुल बेबुनियाद हैं चूंकि मैं इस लोकतंत्र के मंदिर में वर्ष 1995 से हूँ और शायद मेरे किसी तरह के व्यवहार से किसी माननीय सदस्य की भावना पर ठेस नहीं पहुँची है । मैं लगातार गरीबों की बात करता रहा हूँ और इसको लेकर, लेकिन कल जो इस सदन के अंदर देखने को मिला यह एक सोची-समझी रणनीति के तहत थी और बिना सिर-पैर का सवाल खड़ा किया गया । मैं इतनी बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेरे जुबान से अपभ्रंश शब्द का प्रयोग तो नहीं ही हो सकता है चूंकि हमलोग बहुत ही अनुशासित पार्टी से आते हैं और हमलोग गरीबों का, दलितों का सम्मान करते हैं, हमारी पहचान दलितों और गरीबों से ही है । इसलिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह संसदीय मर्यादा को, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, फिर भी मैं सदन की भावना का आदर करते हुए, सम्मान करते हुए मैं, हालाँकि मैंने कोई गाली नहीं दी है फिर भी अगर ये बातें आयी हैं और सदन की भावना है तो मैं सदन की भावना का आदर करता हूँ । इस लोकतंत्र के मंदिर में लोकतंत्र का सम्मान करता हूँ और मैं खेद व्यक्त करता हूँ ।

अध्यक्ष : धन्यवाद । माननीय सदस्यगण, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है और यही संसदीय परंपरा भी है । यहाँ सदन में खेद प्रकट करने से कोई छोटा नहीं होता बल्कि संसदीय प्रणाली मजबूत होती है ।

माननीय सदस्यगण, मैं अपनी तरफ से सत्ता पक्ष और विपक्ष को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ । आप और हम मिलकर बेहतर और सुंदर बिहार के लिए, विकास के मामलों में काम करने के लिये हम चुन कर आये हुए हैं इसलिए जनता के प्रति हम जिम्मेवार हैं । हम सब लोग अपनी जिम्मेवारियों को इस सदन में शांतिपूर्ण तरीके से उठाने का काम करें और एक ही निवेदन मैं करूँगा माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी से कि जो प्रश्नकाल है, मैं चाहूँगा कि प्रश्नकाल को, अन्य कार्यक्रम को भी नहीं बाधित किया जाये लेकिन प्रश्नकाल को बिल्कुल चलने दिया जाये क्योंकि बड़ी मेहनत से आप अपने क्षेत्र की समस्या को लाते हैं और सरकार भी बड़ी मेहनत कर आपके प्रश्नों का जवाब लेकर आती है, इसलिए प्रश्नकाल को कभी भी बाधित नहीं किया जाये और जो कल घटना घट गयी, उस क्रम में जो लोकतांत्रिक तौर-तरीके रहे हैं, आज ही नहीं पूर्व से, माननीय विरोधी दल के सदस्यों ने जो धरना दिया विधान सभा के पोर्टिको या उसकी जो सीढ़ी है उस पर बैठकर तो मैं कहना चाहता हूँ अपने सभी माननीय सदस्यों से कि यह परंपरा कोई नई नहीं है, चलती रहती है, यहाँ विचारों का संघर्ष और लड़ाई होती है, कोई शारीरिक संघर्ष करने की यह जगह नहीं है । इसलिए कोई भी अगर धरना पर बैठें तो कोई भी माननीय सदस्य उनको छेड़-छाड़ न करें, न उन्हें लड्डू खिलायें, न उन्हें पानी पिलायें, अगर इस तरह की बातें हुई हैं तो मैं चाहूँगा कि भविष्य में यह नहीं होनी चाहिए । माननीय सदस्यगण...

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय...

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, संसदीय कार्य ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, हम सरकार की तरफ से भी आसन के प्रति आभार प्रकट करना चाहते हैं कि आज सुबह जो हमारे अनुरोध पर जिस सकारात्मक पहल की आपने शुरूआत की है, आज सदन उसका इस वक्त साक्षी बना है कि एक बड़े ही, समझिये सौहार्दपूर्ण वातवरण में सभी माननीय सदस्यों के सहयोग से हम फिर से बिहार की जनता के हित में, चाहे सत्ता पक्ष हो या प्रतिपक्ष हो, सभी लोग मिलकर जनता के अधिकतम हित का काम करेंगे परन्तु महोदय, यह आपने सही ही कहा है कि आगे से हमलोगों को इस तरह की घटनाओं से सीख लेनी चाहिए कि कोई भी काम ऐसा नहीं करें क्योंकि देखिये हमारे सदन के अंदर स्थायी रूप से लिखा हुआ है कि बोलने की आजादी होती है लेकिन लिखा हुआ है कि भाषण स्वतंत्रता का अर्थ आत्म-नियंत्रण है। भाषण स्वतंत्रता का मतलब जो मन में आये वह बोलना नहीं है, आत्म-नियंत्रण है वहाँ लिखा हुआ है । विनय और संयम संसदीय भाषा के गुण हैं, मतलब अगर हमलोग संसदीय प्रणाली में हिस्सा ले रहे हैं, बोल रहे हैं तो हमारी वाणी में विनय और संयम

होनी चाहिए और मेरी समझ से इस सदन के सभी माननीय सदस्य, क्योंकि सब जनता के द्वारा अधिकृत हो कर यहाँ आये हैं, कोई किसी से कम नहीं हैं, न कोई किसी से कम सक्षम है, हर आदमी इस बात को समझता है और हर आदमी दिल से, ईमान से इन बातों को लागू कर सकता है और मुझे पूरा यकीन है कि आपने जो पहल की है भविष्य में हमलोग इसका ख्याल रखेंगे और सदन अच्छे ढंग से अपनी कार्यवाही सम्पादित करते हुए बिहार की जनता का अधिकतम हित करने का फैसला करेगा ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : महोदय...

अध्यक्ष : माननीय नेता प्रतिपक्ष ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : महोदय, संसदीय कार्य मंत्री जी का सुविचार बहुत अच्छा है । महोदय, दुनिया वह किताब है जो आने वाले जमाने में बता देता है, सीखा देता है, अध्यापक बना देता है । नये सदस्यों को आज सीखने का मौका भी मिला है लेकिन जो भाव हम दूसरों के प्रति रखते हैं, वह हम अपने प्रति भी उतारेंगे तो खूबसूरती और ज्यादा झलकेगी और ये लोकतंत्र की दो आँखें पक्ष और प्रतिपक्ष हैं, दोनों आँखें स्वस्थ रहे तो लोकतंत्र स्वस्थ रहेगा और लोकतंत्र की गाड़ी जनता के हित में मालिक के रूप में नहीं, सेवक के भाव से बढ़ते रहेगा ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब वित्तीय कार्य लिये जायेंगे ।

अभी उद्योग विभाग के संबंध में जो माँग प्रस्तुत की गयी है, उस माँग पर माननीय सदस्य श्री अरूण शंकर प्रसाद, श्री कुमार शैलेन्द्र, श्री जनक सिंह, श्री अखतरूल ईमान से कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं । ये सभी व्यापक हैं जिस पर सभी माननीय सदस्य विचार-विमर्श कर सकते हैं । माननीय सदस्य श्री अरूण शंकर प्रसाद जी का प्रस्ताव प्रथम है ।

अतएव, माननीय सदस्य श्री अरूण शंकर प्रसाद अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।

टर्न-12/संगीता/15.03.2023

श्री अरूण शंकर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय,...

अध्यक्ष : माननीय अरूण बाबू, एक मिनट । माननीय सदस्य अभी कुछ समय अन्य कार्यों में चला गया है, उन्हें भी एडजस्ट करना होगा, आप सबके समय में कुछ कटौती भी होगी, यह मैं सूचना आपको दे रहा हूं सदन को । हां, आप अपना जारी रखें ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, माननीय उद्योग विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा 16,48,81,73,000/-(सोलह अरब अड़तालीस करोड़ इक्यासी लाख तिहत्तर हजार) रुपये से अनधिक राशि प्रदान करने का जो प्रस्ताव आया है, उसमें मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

''इस शीर्षक की मांग 10/-रुपये से घटायी जाय''

यह मैं प्रस्ताव करते हुए इसलिए कहता हूं कि उद्योग नीति पर विमर्श की जरूरत है महोदय । ये उद्योग विभाग का अतीत बिहार के अंदर अत्यंत ही गौरवशाली रहा है और आज उद्योग विभाग एक ऐसे मुकाम पर आकर खड़ा है जहां हम इन्वेस्टर को बुलाते जरूर हैं, लुभाते जरूर हैं लेकिन ठहरा नहीं पाते हैं, यह बिहार का दुर्भाग्य है महोदय और संयोग यह है कि इतिहास स्वयं को दोहराता है और पिछली बार इस तरफ से जो व्यक्ति उद्योग विभाग के विरूद्ध खड़े थे संयोग ने उन्हीं को मंत्री बना दिया और आदरणीय मंत्री जी का पूरा का पूरा भाषण महोदय मेरे पास है जो इन्होंने दिया है उद्योग विभाग पर और किस प्रकार से मधुबनी की चीनी मिल, दरभंगा की अशोक पेपर मिल की चिन्ता इन्होंने की थी और सरकार को यहां से कोसते थे पानी पी-पीकर और आज मंत्री बनकर बैठे हैं और जिस मधुबनी जिले की चीनी मिल की बात कर रहे थे लोहट, रैयाम, सकरी उसी मधुबनी से भी आते हैं महोदय और एक चीनी मिल खोलने की बात तो छोड़ दीजिए उसपर कोई प्रस्ताव भी आया हो कहीं से तो बहुत बड़ी बात हो जाती लेकिन जिस समय जिनको वे कोस रहे थे वे संयोग से भारतीय जनता पार्टी के कोटे के मंत्री थे माननीय शाहनवाज हुसैन साहब और उन्होंने जिस इथेनॉल के कारखाने को मधुबनी में ला दिया था, सौभाग्य इनका देखिए कि इन्हीं को उसका शिलान्यास करने का अवसर मिला क्यों लेकिन वह चलेगा नहीं चलेगा, क्या होगा यह तो उद्योग विभाग के भविष्य के गर्त में है । महोदय, दरभंगा अशोक पेपर मिल की शुरूआत वर्ष 1958 ई0 में दरभंगा महाराज ने की थी और आज वह मिल बंद पड़ा हुआ है, क्या उसकी चिन्ता माननीय मंत्री जी करेंगे ? महोदय, यह बिहार लोकतंत्र की जननी है, लिच्छवी गणतंत्र वैशाली की धरती उसकी साक्षी है और लोकतंत्र के इस मंदिर में महज संयोग है कि दूसरे दिन के गतिरोध के बाद मुझे बोलने का आपने अवसर दिया है इसीलिए मैं आपके आसन को भी धन्यवाद करता हूं । महोदय, यह बिहार बार-बार माननीय मुख्यमंत्री जी इस बिहार में जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं ताकि उद्योगपति आकर्षित हो सकें लेकिन जब उद्योगपति देखता है कि माननीय मुख्यमंत्री के बगल में, के ठीक बगल के सीट पर बैठा हुआ आदमी अगर भ्रष्टाचार में लिप्त व्यक्ति हो तो स्वाभाविक है कि उद्योगपति वहीं से लौट जाता है, वह हवाई अड्डे पर उतरना भी पसंद नहीं करता है । जिस बिहार में

2005 के पहले का बिहार, माननीय मुख्यमंत्री जी बार-बार इस सदन में उस दिन भी कह रहे थे धन्यवाद प्रस्ताव पर भाषण करते हुए कि 2005 के पहले कुछ था ? हम भी कह रहे हैं कि 2005 के पहले कुछ नहीं था, 2005 के बाद आया लेकिन जिनके सहयोग से आया वह क्यों आप भूल जाते हैं और जिनके कारण 2005 के पहले नहीं था उनको बगल में बिठाकर आप क्या संदेश देना चाहते हैं देश और दुनिया में महोदय मैं यह पूछना चाहता हूं माननीय उद्योग मंत्री जी से कि आप भी बगल में बैठते हैं और आप भी उनके साथ मंत्री हैं । आप इसपर बताइये कि कैसे उद्योगपति आकर्षित होगा, उद्योग लगाने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है कि यहां आधारभूत संरचना बिजली के साथ-साथ उसको कानून व्यवस्था का राज मिलना चाहिए । अगर रंगदारी मांगेगा, उससे अगर पैसे मांगे जायेंगे, लेवी मांगा जायेगा तो कौन उद्योगपति टिकेगा महोदय, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि माननीय उद्योग मंत्री जी की चिन्ता थी और इनके भाषण का यह पार्ट है महोदय कि मधुबनी जिले में जो प्रॉपर्टी है पंडौल में, वहां कम से कम एक सौ उद्योग धंधा आप खोल सकते हैं । सुझाव दिया था माननीय मंत्री जी को आज संयोग से मंत्री हैं, इस एक सौ में से कितना दर्जनों खोलेंगे कि नहीं ये तो आज अपने भाषण में बता दें और खोलेंगे तो किस-किस नाम से खोल रहे हैं, किस-किस जगह पर खोल रहे हैं जरा आज इसकी चर्चा माननीय मंत्री जी करें तो यह बेहतर इस सदन के लिए होगा और लोकतंत्र की इस जननी के, लोकतंत्र के इस मंदिर में बड़ा ही इनका सकारात्मक पहल होगा महोदय । दूसरा, इन्होंने कहा था नीति तो आप कहते हैं और नीयत में जिनकी भी खोट है, इसके बारे में इन्होंने कहा था तो अब तो नीयत में जिनकी खोट था जिस मंत्री को इनके साथ नहीं हैं, अब तो अच्छे नीयत वाले लोग हैं तो अब क्या हो रहा है महोदय, इस बिहार के अंदर, उद्योग को अब क्या हो रहा है यह मैं जानना चाहता हूं महोदय । बियाडा की संस्था के बारे में इन्होंने कहा था आज बियाडा की क्या स्थिति है उसके बारे में जरा बतायें और संयोग से उधर से जवाब देने के लिए माननीय संजय सरावगी जी खड़े हुए थे मैं उनके भी पूरे भाषण का अंश ले आया हूं महोदय, जो मेरे पास है तो पिछली ही बार जो वे बोले थे जितना उसको अगर ठीक प्रकार से उतनी ही बातों को कर दें तो मुझे नहीं लगता है कि हमको बहुत कहने की जरूरत पड़ेगी महोदय, मैं यही इनसे अनुरोध करूंगा । महोदय, हमने कहा कि हमारा बेहतर अतीत रहा है, हम बहुत ज्यादा अब आपके भाषण में नहीं पड़ेंगे आपका भाषण तो अंश है यहां रखा हुआ है आप उसको निकालकर पूरा पढ़ लीजिएगा एक बार और उसके अनुसार कार्रवाई करिएगा । मैं आता हूं महोदय, अविभाजित बिहार में, बिहार में चीनी, जूट, पेपर, सूत और सिल्क उद्योग का गौरवशाली अतीत रहा है । राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री श्रीकृष्ण बाबू के समय बिहार देश की दूसरी सबसे

बड़ी सबसे बेहतर अर्थव्यवस्था वाला राज्य था लेकिन आज हम किस पायदान पर खड़े हैं जरा इसको भी माननीय उद्योग मंत्री जी अपने भाषण में बताने की कृपा करेंगे । बरौनी रिफाइनरी, सिन्दरी, बरौनी उर्वरक कारखाना, बोकारो स्टील प्लांट, बरौनी डेयरी, भारी इंजीनियरिंग उद्योग, हटिया उन दिनों ही स्थापित हुये थे महोदय किन्तु सरकार की गलत नीतियों और इच्छाशक्ति के कारण इच्छाशक्ति में जो कमी हुई उसके कारण कल-कारखानें धीरे-धीरे बंद होते गए । इसी के साथ रोजगार की समस्या हुई महोदय, और रोजगार की समस्या के कारण आज पलायन हो रहा है और आज जिस प्रकार से अन्य राज्यों में बिहार के मजदूरों के साथ जिस प्रकार की स्थिति पैदा हो रही है महोदय, वह दुर्भाग्यपूर्ण है और इसके लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो एक उद्योग विभाग भी जिम्मेवार है, बिहार की कृषि नीति के साथ उद्योग विभाग भी इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेवार है ।

(क्रमशः)

टर्न-13/सुरज/15.03.2023

श्री अरूण शंकर प्रसाद (क्रमशः) : अगर मनरेगा की योजना पर दोष लगाया जाता है माननीय मंत्रियों द्वारा तो उद्योग विभाग भी इसके लिये कम जिम्मेवार नहीं है । क्योंकि बिहार जैसे राज्य में अगर उद्योग-धंधा नहीं होगा तो गरीबों का पलायन कोई नहीं रोक सकता है और छोटे-छोटे उद्योगों की संभावना है महोदय लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी एक बात कहकर टाल जाते हैं विषय को क्योंकि सबकुछ तो किया, बहुत कुछ किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने एन0डी0ए0 के शासन में । लेकिन कहीं न कहीं उद्योग विभाग में जो कमी थी, जब उसको पूरा करने का काम शुरू किया माननीय शाहनवाज हुसैन जी ने तो इनको शायद अच्छा नहीं लगा और गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिये और आज जो उद्योग विभाग एक ऊंचाई की ओर जा रहा था, वह फिर से आज नीचे चला गया और मैं माननीय उद्योग मंत्री जी से ये भी कहूंगा कि मेरे ही विधान सभा क्षेत्र में, मैंने इनसे पर्सनली भी कहा था मिलकर कि 22 एकड़ जमीन जहां रेशम उद्योग था, रेशम का सूता तैयार होता था, रेशम के कीट का प्रबंधन हो रहा था । वह आज वीरान पड़ा हुआ है, वैसे ही पड़ा हुआ है । उस पर आज तक कोई उद्योग नहीं लगा और केवल यह कहकर टाल दिया जाता है कि बाढ़ प्रणव क्षेत्र है, वहां पानी लग जाता है, वहां कुछ हो नहीं सकता । तो क्या बिहार को हमलोग ऐसे ही छोड़ देंगे महोदय उद्योग के मामले में । क्या बाकी राज्यों में जहां समुद्री किनारा नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा कह जाते हैं कि हमारे यहां कोई समुद्री किनारा है क्या जो उद्योग लगेगा । लेकिन जहां समुद्री किनारा नहीं है महोदय ऐसे प्रांतों में भी उद्योग-धंधे हैं

और उद्योग-धंधों के कारण उनकी आय बढ़ रही है, उनके लिये रोजगार का श्रृजन हो रहा है उन राज्यों में । इसलिये बिहार में भी इस काम को किया जा सकता है लेकिन छोटे-छोटे जो कल कारखाने हैं । महोदय, अब मैं बात करूंगा पटना का, पटना में एक 50 वर्षों से पटना सिटी में जी0एस0एल0 बल्ब उद्योग चल रहा है । वह एल0ई0डी0 बल्ब में तब्दील करने हेतु क्लस्टर में अनुदान विमुक्त करने के संबंध में है महोदय और माननीय नंद किशोर जी जैसे सीनियर मेंबर के पत्र लिखने के बाद भी उसके अनुदान की राशि वहां नहीं जा पा रहा है और यह दुख का विषय है महोदय । कैसे उद्योग बढ़ेगा जब पुराना बल्ब हटाकर एल0ई0डी0 बल्ब का वह लगाना चाह रहा है, उसका जब आधुनिकीकरण करना चाह रहा है तो उसके मार्ग में रोड़ा अटक रहा है । रोड़ क्या है वही भ्रष्टाचार । रोड़ क्यों अटकता है, यहां जो ब्यूरोक्रेसी बढ़ा हुआ है । बिहार में ब्यूरोक्रेसी नियंत्रित नहीं हो रहा है और ये एक जगह की बात नहीं है महोदय आपके क्षेत्र की भी वही बात है, मेरे क्षेत्र की भी वही बात है और माननीय उद्योग मंत्री जी क्यों नहीं हों, उनके यहां भी यही स्थिति है कि आज जो ब्यूरोक्रेसी बिहार के अंदर बढ़ा है, ब्यूरोक्रेसी जो चरम पर पहुंच गया है । ब्यूरोक्रेसी के राय के बिना सरकार एक कदम नहीं उठाती है । आज सरकार का अपना मौलिक चिंतन समाप्त हो गया है, पूर्ण ब्यूरोक्रेसी से घिरा हुआ । क्या हुआ महोदय ब्यूरोक्रेसी के कारण आई0ए0एस0 और बासा के बीच लड़ाई, बासा के लोगों की मांग नहीं मानी जा रही है। किस प्रकार से बिहार और बिहारियों को गाली दी जा रही है और एक तरफ हमलोग बिहार की गौरवगाथा गाने के लिये यहां बैठते हैं और दूसरी ओर जो अन्य राज्यों से आया हुआ पदाधिकारी है वह बिहार के लोगों को ही गाली देता है, बिहार के बासा के लोगों को गाली देता है और भ्रष्टाचार चरम पर जा रहा है । इसको रोकने की जरूरत है महोदय और जब तक इस पर अंकुश नहीं लगेगा, तब तक बिहार का उद्योग फल-फूल नहीं सकता है, ये उसके मार्ग में एक बड़ी बाधा है । महोदय, इसलिये मैं कहना चाहूंगा कि आज चीनी मिल की हालत खराब है और जो भी चीनी मिल निजीकरण के हाथ में है, उसकी भी स्थिति खराब है । सीतामढ़ी में रीगा चीनी मिल चल रहा था, दो साल पहले वह भी बंद हो गया । निगम की चीनी मिल इतनी तेजी से बिहार में फैली हुई थी जिसकी कोई सीमा नहीं थी महोदय और लगातार निगम के द्वारा बिहार के अंदर चीनी बनाने का काम और बिहार का चीनी दुनिया के अंदर खासकर के हमारे मधुबनी में लोहट और रैयाम की चीनी विश्वप्रसिद्ध चीनी की श्रेणी में थी महोदय । महोदय, इसलिये मैं कहना चाहूंगा कि:

''कहीं बेहतर है तेरी अमीरी से मुफलिसी मेरी
चन्द सिक्कों की खातिर तूने क्या नहीं खोया
माना नहीं है मखमल का बिछौना मेरे पास
पर तू ये बता कि कितनी रातें चैन से सोया ।''

ये जो बिहार की स्थिति है महोदय मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि:

''फलसफा न समझो असरारे सियासत समझो
जिंदगी सिर्फ हकीकत है उसे हकीकत समझो
जाने किस दिन हो जायें हवा भी नीलाम यहां
आज तो सांस भी लेते हो गनीमत समझो ।''

महोदय, यहां जो उद्योग की स्थिति है वह कैसे ठीक होगी, यह हम सबके लिये चिंता का विषय है, चाहे वह सत्ता पक्ष हों, विपक्ष हों । महोदय, बिहार में उद्योग धंधों का जो खस्ता हाल है वह कैसे रूकेगा, प्रवासी जो कामगार हैं वह कैसे बिहार लौटेगा । इसकी चिंता हम सबको मिल बैठकर करना चाहिये महोदय और यहां देश का 40 प्रतिशत चीनी का उत्पादन बिहार में होता था, आज वह नहीं हो पा रहा है । उसकी जगह इथेनॉल धीरे-धीरे लेना शुरू किया है लेकिन आज उसमें भी जितनी बाधायें आ रही हैं, उन बाधाओं को अगर दूर नहीं किया गया तो बिहार की स्थिति इसी प्रकार बनी रहेगी और बिहार बाकी चीजों में तो थोड़ा सुधार हो रहा है लेकिन अगर हमलोग विचार करें । हमलोग भी शासन में रहे हैं, एन0डी0ए0 का भी शासन रहा है, आर0जे0डी0 का भी शासन रहा है, कांग्रेस का भी शासन रहा है लेकिन आज तक बिहार में मानव सूचकांक के उस स्तर को हम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, केवल आधारभूत संरचनाओं में हम सिमट कर रह गये हैं । उसी के अंदर कुछ बातें हम कर पाये हैं लेकिन बिहार का जो मानव सूचकांक बढ़ना चाहिये देश और दुनिया के स्तर पर आज वह नहीं बढ़ रहा है । किसी भी विभाग की जब चर्चा होती है तो आकर हम ठहर जाते हैं उस विभाग की गुणवत्ता पर । जब आधारभूत पर जाते हैं तो कुछ तो काम हुआ लेकिन जब गुणवत्ता पर आते हैं तो पता चलता है कि गुणवत्ता के मामले में हम अत्यंत पीछे हैं महोदय इसलिये हमको समेकित रूप से विचार करके बिहार के अंदर जो उद्योग-धंधे हैं, उसको बढ़ाने के लिये हमको लगातार प्रयास करना पड़ेगा । महोदय, मिलों के बंद होने का असर खेती पर भी पड़ा है, किसानी पर भी पड़ा है और हमारे कृषक बेरोगार हुये हैं । नकदी फसल के रूप में जो हमारे यहां सबसे ज्यादा गन्ना उपजता था, आज उस गन्ने की खेती समाप्त हो रही है । किसी-किसी प्रकार से किसान उस गन्ने की पेराई करके, गुड़ बनाकर किसी तरह से उसका खपत कर पा रहा है और आज, जो किसान कभी मधुबनी में ब्रासलेट धोती उस जमाने में

कीमती होता था, ब्रासलेट धोती पहन कर निकलता था । आज उसको पहनने के लिये साधारण धोती भी नहीं मिल रहा है, उसकी माली हालत इतनी खराब हो गयी है महोदय । नहीं तो जिस दिन मिल से पैसा मिलता था लोहट, रैयाम और सकरी मिल से पुर्जा छुड़ाकर जब किसान लौटता था तो मधुबनी के इन्हीं के बड़ा बाजार में भीड़ लग जाती थी किसान के द्वारा और खरीदारी, क्रय शक्ति बाजार का भी उसके कारण बढ़ता था महोदय । तो आज इन मिलों के बंद होने के कारण हम उसको फिर से चालू नहीं कर पा रहे हैं महोदय । सरकार ने नीतिगत निर्णय ले लिया कि हम चीनी मिल नहीं चलायेंगे, हमसे नहीं चलेगा । महोदय, सरकार पूरी तरह से सरेंडर कर चुकी है । अब लोगों को जब आमंत्रित कर रहा है तो लोगों के लिये वातावरण नहीं मिल रहा है...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य...

श्री अरूण शंकर प्रसाद : इसलिये लोग बिहार...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य आप संक्षेप में अपनी बात को रखें ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : महोदय, हमको तो जब कहियेगा हम बैठ जायेंगे । हम तो आपके आसन का सम्मान करते हैं..

अध्यक्ष : संक्षिप्त में ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : और आसन का सम्मान ही सर्वोपरि है और आसन को भी निरपेक्ष दिखना चाहिये महोदय । ये मैं अनुरोध करूंगा क्योंकि ये बिहार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि बिहार देश को दिशा देती है । तो क्या ये बिहार की विधान सभा देश के सभी विधान सभा को दिशा नहीं दे सकती है निरपेक्षता के मामले में, अपने बहस के मामले में, बहस की गुणवत्ता के मामले में ।

(क्रमशः)

टर्न-14/राहुल/15.03.2023

श्री अरूण शंकर प्रसाद (क्रमशः): हमको यह भी लागू करना चाहिए महोदय । माननीय मुख्यमंत्री जी का अगर वह सपना है तो यह भी सपना होना चाहिए और इस सदन की गरिमा को बढ़ाने के लिए हम सभी माननीय सदस्यों को आप जैसे कहें हम लोग वैसे करने के लिए तैयार हैं लेकिन विपक्ष की बात भी सम्यक रूप से सुनी जानी चाहिए । सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर काम करेंगे तभी महोदय इस सदन में सामने लिखा हुआ है कि ''राजनीतिक दल राष्ट्र निर्माण के साधन हैं वे साध्य नहीं हो सकते हैं'' लेकिन हम दल के साधक हो जाते हैं, राष्ट्र को तिलांजलि दे बैठते हैं यही कारण है कि पार्टी प्रथम कहने लगते हैं, राष्ट्र बाद में आने देते हैं लेकिन जिस दिन हम राष्ट्र को प्रथम कहेंगे पार्टी को द्वितीय रखेंगे उसी दिन इस सदन में भी सुधार की प्रक्रिया शुरू हो

जायेगी यह मेरा विश्वास है महोदय और आप इस सदन के कस्टोडियन हैं महोदय । मैं अपनी बात संक्षेप करते हुए...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य आप अपना भाषण समाप्त करें ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : महोदय, मैं आपके आसन को इस बात के लिए धन्यवाद देते हुए कि आपने मुझे अवसर दिया, अपने नेता प्रतिपक्ष को भी धन्यवाद देता हूं, अपने सचेतक को भी धन्यवाद देता हूं और हम खजौली से चुनकर आते हैं अपनी खजौली की जनता को भी हम इस सदन के माध्यम से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं कि आपने मुझे इस सदन के लायक समझा और यहां भेजा इसलिए मैं आपके सामने अपनी बात रख सका महोदय । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री फते बहादुर सिंह अपना पक्ष रखें । आपका समय 10 मिनट है ।

श्री फते बहादुर सिंह : धन्यवाद महोदय । महोदय, मैं कटौती प्रस्ताव के विपक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । मैं आभार व्यक्त करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी का जो हमें सदन में अपनी बात रखने का मौका दिये । महोदय, बिहार उद्योग के क्षेत्र में काफी विकास कर रहा है । वस्त्र और चमड़ा प्रक्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2022 को स्वीकृत किया गया जिसके तहत 10 करोड़ रुपये तक के पूंजीगत अनुदान, पावर टैरिफ पर 2 रुपये प्रति यूनिट की सब्सिडी, 5 हजार रुपये प्रति कामगार प्रति माह का रोजगार अनुदान, 10 लाख रुपये तक की फ्रेट सब्सिडी और 10 लाख रुपये तक की पेटेन्ट सहायता का प्रावधान किया गया । इस नीति के तहत मुजफ्फरपुर और फतुहा में बैग कलस्टर का निर्माण किया गया है और जीविका दीदीयों को बैग कलस्टर से जोड़ा गया है । महोदय, राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद को प्रभावशाली बनाते हुए 7 दिनों के अंदर आवेदनों/समस्याओं के समाधान की व्यवस्था की गई और इस वर्ष 95.38 मामले सुलझाये गये । राज्य के नये सिंगल विंडो क्लियरेन्स पोर्टल को नेशनल सिंगल विंडो पोर्टल के साथ इन्टीग्रेट कर दिया गया । 255 आवेदकों को स्टेज-1 अनुमोदन प्रदान किया गया जिसमें 6816 करोड़ के निवेश प्रस्ताव हैं । 1155 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव वाली 65 परियोजनाओं को फाइनेंशियल क्लियरेन्स दिया गया । महोदय, स्टार्ट-अप को प्रोत्साहन देने के लिए नई स्टार्टअप नीति, 2022 लागू की गई । नई नीति के तहत 10 लाख रुपये तक के कैपिटल सीड फंड जो महिलाओं के मामले में 5 प्रतिशत अधिक और अनुसूचित जाति/जनजाति/दिव्यांग के मामले में 15 प्रतिशत है, राशि का प्रावधान किया गया है । नई नीति के तहत 90 स्टार्ट-अप का प्रमाणीकृत किया गया तथा कैपिटल सीड फंड के रूप में 5.10 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई । स्टार्ट-अप सनराइजर्स इमर्जिंग स्टार्ट-अप इको सिस्टम रैंकिंग में बिहार को एक करोड़ से अधिक

आबादी वाले राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों की श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है । को-वर्किंग स्पेस के रूप में पटना के मौर्यालोक में 16262 वर्गफीट ऑफिस स्पेस और फ्रेजर रोड स्थित वित्तीय भवन में 34 हजार वर्गफीट में ऑफिस स्पेस का निर्माण किया गया है । महोदय, बियाडा के 9 औद्योगिक क्षेत्रों में 24 लाख वर्गफीट को प्लग एण्ड प्ले औद्योगिक शेड के रूप में विकसित किया गया जो औद्योगिक इकाइयों को 4-8 रुपये प्रति वर्गफीट प्रतिमाह के रूप में दिया जा रहा है । साथ ही, औद्योगिक क्षेत्र में आवंटन हेतु 3 हजार एकड़ अतिरिक्त भूमि का प्रावधान किया गया है ।

महोदय, विपक्ष के साथी बोल रहे थे कि मुख्यमंत्री के बगल में बैठने वाले व्यक्ति के बारे में मैं पूछना चाहता हूं । सदन के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, मैं पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री के बगल में बैठने वाले व्यक्ति को न्यायालय ने तड़ीपार घोषित कर दिया था, जिले में प्रवेश पर रोक लगा दी गई थी वह व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री के बगल में बैठता है और देश की नीति निर्धारण करता है देश के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है, XXX

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य आप स्थान ग्रहण करें ।

श्री फते बहादुर सिंह : महोदय, जो बगल में बैठने की बात कर रहे हैं वे...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य उद्योग का बजट है उद्योग पर ही अपने को नियंत्रित करके आप बात को रखें । इसलिए माननीय सदस्य आप स्थान ग्रहण कीजिये ।

(व्यवधान)

आप बैठ जाइये, हो गया, मैंने बोल दिया कि आप उद्योग पर ही बोलें । आप बैठिये, आप उद्योग पर ही बोलें, बोलिये, आप भाषण जारी रखिये आपका समय बहुत कम है ।

श्री फते बहादुर सिंह : महोदय, ऐसे ही लोग बिहार को बदनाम कर रहे हैं । इन लोगों को पत्थर में भगवान और इन्सान में दानव दिखता है महोदय...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बचोल जी, बोलने वाला अपना बोल रहा है आप बैठिये न । आप भी बोलियेगा तो कौन रोकने आयेगा ।

श्री फते बहादुर सिंह : महोदय, आदरणीय लालू...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : असंसदीय शब्द हट जायेगा ।

श्री फते बहादुर सिंह : महोदय, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जब रेल मंत्री थे तो डेहरी डालमिया नगर को उन्होंने रोहतास इंडस्ट्रीज के एक कारखाना को लिया था रेल कारखाना बनाने के लिए और उस समय रेल कारखाना के लिए लिया गया । बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि केन्द्रीय बजट का, वर्ष 2023-24 का जो बजट आया है उसमें डालमिया नगर उद्योग के लिए एक रुपये का बजट मिला है महोदय एक रुपये का बजट मिला है और महोदय...

(व्यवधान)

यह उद्योग का ही तो है और...

अध्यक्ष : आप अपना भाषण जारी रखें । माननीय सदस्य टोका-टोकी न की जाय । माननीय सदस्य जो बोलते हैं उसको सुनिये ।

श्री फते बहादुर सिंह : महोदय, पूरे देश के उद्योग को चौपट कर दिया गया है । बहुत सारे लघु उद्योग देश में चल रहे थे उसमें करोड़ों लोग रोजगार पा रहे थे लेकिन जब नोटबंदी हुई नोटबंदी के समय देश के लाखों उद्योग-धंधे बंद हो गये और नतीजा यह हुआ कि करोड़ों लोग बेरोजगार हो गये महोदय । महोदय, सदन के माध्यम से बिहार की जनता को मैं बताना चाहता हूं कि जिस हिसाब के देश चलाने वाले लोग हैं, दो देश को बेच रहे हैं और दो देश को खरीद रहे हैं महोदय । कैसे विकास होगा, कैसे देश में उद्योग धंधा लगेगा ? महोदय, अभी जो...

(व्यवधान)

टर्न-15/यानपति/15.03.2023

(व्यवधान)

अध्यक्ष: माननीय सदस्य.....

श्री फते बहादुर सिंह: महोदय, 10 लाख 70 हजार करोड़ महोदय......

अध्यक्ष: माननीय सदस्य फते बहादुर सिंह जी, आपका समय समाप्त हुआ आप अपना स्थान ग्रहण करें । बहुत अच्छे तरीके से आपने उद्योग पर अपनी बात को रखा है ।

श्री फते बहादुर सिंह: महोदय, 5 मिनट और दिया जाय । महोदय, 10 लाख 70 हजार करोड़ देश की जनता की संपत्ति, अपने मित्रों को माफ करने का काम किया गया है ।

(इस अवसर पर माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

महोदय, और ये लोग बिहार में उद्योग की बात कर रहे हैं । सारे बिहारी, सारे बिहार की जनता का पैसा तो अपने मित्रों को माफ करने में खत्म कर दिए और महोदय जो पिछड़ा, सारा तो बेच दिए, तेल बेच दिए, रेल बेच दिए, खेल बेच दिए अब बचा ही क्या है सब तो बेच दिए । दो बेचनेवाला, दो खरीदनेवाला है ।

उपाध्यक्ष: अब समाप्त कीजिए ।

श्री फते बहादुर सिंह: महोदय, एक बात मैं पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग पर मैं कहना चाहता हूं कि पिछड़ा वर्ग के लिए.....

उपाध्यक्ष: समाप्त कीजिए आप, आपका समय हो गया ।

श्री फते बहादुर सिंह: महोदय, धन्यवाद ।

उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री श्यामबाबू प्रसाद । 10 मिनट है आपका ।

श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव: 12 मिनट होगा सर । उपाध्यक्ष महोदय, मैं कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हूं । कुछ बात रखने के पहले मैं अपनी पार्टी के शीर्ष नेता और अपने क्षेत्र पिपरा विधान सभा के तमाम मतदाता मालिकों का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि अपना स्नेह, प्यार, आर्शीवाद देकर मुझे अपनी बात को सदन में रखने के लिए विधान सभा में भेजने का काम किया है । महोदय, उद्योग पर तो हमलोग, सभी लोग जान लिए कि बिहार में उद्योग का काम क्या हो रहा है लेकिन मैं उसपर जाना नहीं चाहता हूं । मैं पर्यटन पर कुछ बोलना चाहता हूं । पर्यटन देश में आने के लिए विश्व भर के आगंतुकों को आकर्षित एवं आमंत्रित करता है, यह देश की आर्थिक प्रगति में भी मदद करता है और रोजगार के भी अवसर मिलते हैं लेकिन राज्य सरकार इसपर गंभीर नहीं है । बिहार समृद्ध, ऐतिहासिक धरोहर से भरा-परा है । पर्यटन में यह अपार संभावनाएं हैं लेकिन उस अनुरूप कार्य राज्य सरकार नहीं कर रही है । महोदय, बिहार बुद्ध, अशोक और चाणक्य की धरती है, रामायण सर्किट का महत्वपूर्ण स्थल जगत जननी मां जानकी की जन्मभूमि बिहार है, अगर सरकार मजबूत इच्छाशक्ति से पर्यटन के क्षेत्र में कार्य करे तो रोजगार के भी अवसर बढ़ेंगे । महोदय, केंद्र की मोदी सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कृतसंकल्पित है इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि राम जानकी पथ फोरलेन जो उत्तर प्रदेश से रामजन्म भूमि अयोध्या से चलकर चकिया, शिवहर, सीतामढ़ी होते हुए मिथिला नरेश राजा जनक की राजधानी जनकपुर धाम को जोड़ेगा । इसके लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने राम जानकी पथ सहित तीन सड़क परियोजनाओं के लिए 1807 करोड़ रुपये की स्वीकृति भी दे दी है । महोदय, प्रधानमंत्री विशेष पैकेज के तहत स्वदेश दर्शन योजना अंतर्गत पर्यटन स्थलों के विकास के कार्य किए गए हैं । महोदय, महागठबंधन के सभी साथी कहते हैं कि स्पेशल पैकेज कहां है, वह मैं दिखाना चाहता हूं कि इसी पैकेज के तहत जैन परिपथ, कांवरिया परिपथ, मंदार एवं अंग प्रदेश परिपथ एवं गांधी परिपथ के विकास हेतु स्वीकृत राशि 3396.56 लाख रुपये, 4476.29 लाख रुपये, 4652.28 लाख रुपये और 4426.75 लाख रुपये की योजनाओं का क्रियान्वयन मोदी सरकार ने किया है । महोदय, विगत वर्ष में राज्य में आनेवाले जो बिहार सरकार का आंकड़ा बताया गया है, विगत वर्ष राज्य में आनेवाले पर्यटकों की संख्या 25 लाख 2 हजार 239 थी जिसमें

देशी पर्यटकों की संख्या 25 लाख 1 हजार 193 तथा विदेशी पर्यटकों की संख्या 1 हजार 46 थी वहीं 2022 नवंबर तक कुल पर्यटकों की संख्या बढ़कर 1 करोड़ 73 लाख 96 हजार 850 हो गई है । यह आंकड़ा जो सर बताया गया है यह आंकड़ा जो है उस समय का है जब एन0डी0ए0 की सरकार, भाजपा की सरकार चल रही थी । उस समय का आंकड़ा यह बताया गया है लेकिन महोदय हाल के कुछ महीनों के अंदर बिहार में लॉ ऐंड ऑर्डर की स्थिति इतनी गिर गई है कि पर्यटक यहां आने से पहले जान माल की सुरक्षा के बारे में चिंतित हो रहे हैं । वर्तमान सरकार को चाहिए कि वह सबसे पहले लॉ ऐंड ऑर्डर ठीक करे तभी पर्यटक की संख्या बढ़ेगी । महोदय, राज्य में बाहर से आनेवाले देशी एवं विदेशी पर्यटकों की आधुनिक सुविधायुक्त, गुणवत्तापूर्ण आवासन एवं अन्य सुविधायें उपलब्ध नहीं होने से भी बिहार में भारी संख्या में पर्यटकों का झुकाव नहीं हो रहा है । महोदय, बिहार के महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों को जोड़ने वाले चिन्हित कुल राष्ट्रीय एवं राजकीय राजमार्गों पर पर्यटकों को यात्रा भ्रमण के दौरान विश्राम एवं अन्य गुणवत्तापूर्ण सुविधा उपलब्ध कराने हेतु पर्यटन विभाग द्वारा सुविधा प्रोत्साहन योजना 2022 का क्रियान्वयन बिहार सरकार द्वारा ठीक ढंग से नहीं किया जा रहा है जो निंदनीय है । महोदय, मैं अपने विधान सभा क्षेत्र पर, मैं आपसे कुछ बात रखना चाहूंगा कि मैं पूर्वी चंपारण के पिपरा विधान सभा का प्रतिनिधित्व करता हूं । पिपरा विधान सभा के पिपरा स्टेशन से सटे सीतापुरधाम अवस्थित है, पिपरा स्टेशन से एन0एच0-28 में दो कि0मी0 उत्तर तथा जिला मुख्यालय से 22 कि0मी0 पूर्व में ऐतिहासिक सीतापुरधाम अवस्थित है । यह पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है । उक्त धाम लगभग 14 फीट लंबे टीलानुमा आकार में 20 एकड़ में फैला हुआ है । यहां प्राकृतिक सौंदर्य की अनुपम छटा है इसके चारों तरफ सैकड़ों औषधीय पेड़-पौधे हैं । इनके बीच दो एकड़ में सीताकुंड और यहां पर मां जानकी का मंदिर है । जनश्रुति के अनुसार त्रेतायुग में भगवान श्रीराम की बारात जब जनकपुर से अयोध्या के लिए लौट रही थी तो उक्त स्थल पर ही बारात रुकी थी । उक्त स्थल पर भगवान श्रीराम और सीता की चौठारी का रस्म पूरा किया गया था । मां जानकी और श्रीराम का कंगन खोलने की रस्म भी यहीं पूरी हुई थी । महोदय, कंगन के पत्ते के समान आम का पेड़ था वह पेड़ 1934 के भूकंप में दब गया ।

(क्रमशः)

टर्न-16/अंजली/15.03.2023

श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव (क्रमशः) : माँ जानकी जहां स्नान की थी वह पोखर गंगा सागर के नाम से जाना जाता है । वहां प्रत्येक वर्ष लाखों की संख्या में लोग स्नान करने आते

हैं। उक्त पोखर के समीप पांच और बड़े पोखर हैं, जहां मां जानकी, भगवान राम के साथ एक अद्‌भुत शिवलिंग की स्थापना कर पूजा अर्चना की थी वह भगवान शंकर को समर्पित गिरिराज नाथ के नाम से प्रसिद्ध है । जब भी सूखाड़ की संभावना होती है इर्द-गिर्द के किसान गिरिराज नाथ लिंग को जब जल से डूबो देते हैं तब निश्चित ही वर्षा होती है, ऐसी मान्यता है, साथ ही यहां अन्य दर्जनों मंदिर अभिलेखयुक्त पत्थर हैं, जिनको देखने पर लगता है कि यह प्राचीन मंदिर की दीवार पर लगे किवाड़ का अवशेष है । यहां चैत रामनवमी के अवसर पर प्रत्येक वर्ष भव्य मेला का आयोजन होता है । यहां भारत और नेपाल से लाखों की संख्या में श्रद्धालू भक्तों का जुटान होता है । मेरे आग्रह पर सरकार ने 2018 में सीताकुंड महोत्सव को सरकारी, संस्कृति कलेंडर में सम्मिलित भी किया था । महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र का मेहषी जो कि शीप बटन के लिए...

उपाध्यक्ष : आपका टाइम हो गया ।

श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव : महोदय, एक मिनट । विश्वप्रसिद्ध है साथ ही भीमलपुर जंगल में जो बायोडायवर्सिटी पार्क बनने वाला है, वह पर्यटकों को लुभाने का एक मुख्य केंद्र होगा। यहां देश विदेश के पर्यटक आ सकेंगे ।

उपाध्यक्ष : अब समाप्त कीजिए ।

श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव : महोदय, उक्त बायोडायवर्सिटी पार्क मोतिहारी जिले को धरोहर के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है । उक्त निर्माण पर 22.34 करोड़ रुपये खर्च होने हैं जिसका प्राक्कलन तैयार कर वन विभाग द्वारा राज्य सरकार को भेज दिया गया है । इस पार्क के बीचो-बीच गंडक नदी है ।

उपाध्यक्ष : अब समाप्त कीजिए ।

श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव : जो इसे अदभुत रूप प्रदान करेगा । इस पार्क में इको फ्रेंडली हैंगिग ब्रिज का निर्माण किया जाएगा जो पर्यटकों के लिए खास आकर्षण का केंद्र बनेगा...

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब समाप्त कीजिए । माननीय सदस्या श्रीमती शालिनी मिश्रा । दस मिनट का समय है आपका ।

श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव : महोदय, एक मिनट । हम सरकार...

उपाध्यक्ष : अब समाप्त कीजिए ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय उद्योग मंत्री जी के द्वारा बजट प्रस्ताव जो रखा गया है उसके समर्थन में एवं विपक्ष के द्वारा जो कटौती प्रस्ताव रखा गया है उसके विरोध में बोलने के लिए खड़ी हूं । महोदय, मैं अभी माननीय सदस्य अरूण शंकर जी का कटौती प्रस्ताव में जो उन्होंने बोला, वह मैं सुन रही थी, वह सुनते हुए मुझे अपने कॉलेज के दिनों की याद आ गई । महोदय, उस समय में

फोटोक्रोमिक ग्लास का बहुत ही क्रेज था हम नौजवानों में, युवक और युवतियों में भी और मेरे बाबू जी भी यूज करते थे इसलिए मैं बहुत अच्छे से जानती हूं कि जब वे चश्मा पहनकर रूम के अंदर रहते थे तो ग्लास सफेद रहता था, जब आप धूप में जाएंगे तो वह ग्लास काला हो जाता है । महोदय, विपक्ष के माननीय सदस्यगण को मैं यह कहना चाहती हूं कि फोटोक्रोमिक ग्लास की याद मुझे इसलिए भी आ गई कि मैं उनके पिछले बार के भाषण को सुन रही थी, पिछले बार के भाषण को देख रही थी और उसमें मैंने यह देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी 2005 से लेकर अभी तक 17 सालों से सत्ता में हैं । जिसमें से बहुत मुश्किल से तीन-चार साल ही भाजपा सत्ता से बाहर रही है और जब-जब भाजपा सत्ता में रही है तो उन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी जैसा विकास पुरुष, ईमानदार पुरुष, कर्तव्यनिष्ठ इंसान और नेता कहीं नहीं मिला है और तो और उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा है कि इनमें सारी काबिलियत है जो उनको प्रधानमंत्री बना सकती है महोदय । आज जो इनके उच्च सदन में एक बिहार के बड़े नेता है, संसद के उच्च सदन में हैं जो आज पानी पी-पी कर माननीय मुख्यमंत्री जी की आलोचना करते रहते हैं, उन्होंने तो यहां तक भी कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री बनने के मेटेरियल हैं । महोदय, लेकिन जब ये सत्ता से बाहर चले जाते हैं तो इन लोगों को, जैसे फोटोक्रोमिक ग्लास अपना रंग बदलता है ये भी अपना रंग बदल देते हैं । महोदय, इनके सत्ता से जाने का फ्रस्ट्रेशन अभी गया नहीं है ये बहुत फ्रस्ट्रेट हैं येन-केन-प्रकारेण ये सत्ता में रहना चाहते हैं । 2014 के बाद से तो इनकी और भूख बढ़ गई है, हमने, आपने और सभी ने देखा है कि जिस राज्य में, जनता ने इन्हें सत्ता से बाहर किया है वहां खरीद-फरोख्त करके, अपने पालतू सरकारी एजेंसियों को यूज करके सदा से सत्ता में ये काबिल हो गए हैं, माध्यम से । महोदय, ये बिहार में भी इन्होंने अपने सारे एलायंस पार्टनर जैसे सी0बी0आई0, ई0डी0, आई0टी0 सब का उपयोग कर लिए, सारे जोर-आजमाइश कर ली परंतु महोदय यह बिहार है, मैं कहना चाहती हूं यह बिहार है इनकी दाल न गली है, न गलने वाली है कभी बिहार में महोदय । महोदय, सत्ता से हटने का इनको इतना मलाल है कि इन्हें न सच सुनना अच्छा लगता है, न सच बोलना अच्छा लगता है । मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सत्ता संभालने के बाद से इंडस्ट्रियल एंवायरमेंट बहाल करने के लिए, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए जो काम किया है उन्हें यह पूरा देश जानता है और ये विपक्ष के सदस्य अपने दिल पर हाथ रखकर कहें तो ये भी जानते हैं और यही कारण है 2021 इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में बिहार के उद्योग मंत्रालय को स्वर्ण पदक मिला था । महोदय, विपक्ष के लोग सच्चाई स्वीकार नहीं करना चाहते हैं लेकिन मैं ऑन रिकॉर्ड बोलती हूं, ऑन रिकॉर्ड बोलना चाहती हूं कि जो आज स्वयं विश्व गुरु

बन रहे हैं, जिन्हें यह गुमान है कि देश में सब कुछ 2014 के बाद हुआ है ये शायद भूल रहे हैं कि भारत में औद्योगिकीकरण इंडस्ट्रिलाइजेशन का सारा श्रेय तत्कालीन वित्तमंत्री और बाद के प्रधानमंत्री आदरणीय डॉ0 मनमोहन सिंह को जाता है महोदय । आज जो अहमदाबाद हो, मोदी जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, या दिल्ली हो, नोएडा हो, चेन्नई हो, हैदराबाद हो, गुड़गांव हो, बैंगलोर हो महोदय, ये सारे इंडस्ट्रियल हब अगर बने हैं तो ये किसकी देन है तो ये आदरणीय डॉ0 मनमोहन साहब की Liberalization policy की देन है महोदय, यह इनकी देन नहीं है । महोदय, आज के जो तथाकथित विश्वगुरु हैं इन्होंने औद्योगिकीकरण के नाम पर इस देश के सभी पुराने परिसंपत्तियों को अपने रिश्तेदारों को बेचने का काम किया है महोदय । मान्यवर, इन्होंने इंडस्ट्री को नहीं बढ़ाया है, महोदय, इन्होंने इंडस्ट्रिलिस्ट को बढ़ाया है, अडानी और अंबानी को बढ़ाया है और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट इसकी गवाह है जिसकी ये चर्चा किसी भी कीमत पर नहीं करना चाहते हैं । मान्यवर, अगर यही हालात रहे तो आज इन्होंने भेल बेचा है, सेल बेचा है, रेल बेचा है, पोर्ट बेचा है, एयरपोर्ट बेचा है, एयरलाइंस भी बेचा है, आने वाले दिनों में ये इस देश को भी बेच डालेंगे और झोला लेकर केदारनाथ जाएंगे और अपना फोटो खींचवाते रहेंगे महोदय । महोदय, माननीय सी0एम0 सर ने उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सभी आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया है, उद्योग लगाने की शुरुआत भी हो गई है और काफी लाभ भी हो गए हैं । इस क्षेत्र में किए गए महत्वपूर्ण कार्यों में से कुछ की चर्चा मैं करना चाहती हूं । इथेनॉल का बहुत बड़ा प्लांट पूर्णिया में लगकर तैयार है, चल रहा है, 24 और प्लांट निर्माणाधीन हैं और मैं यह भी कहना चाहती हूं कि...

(व्यवधान)

आप लोग सच्चाई नहीं स्वीकार करेंगे लेकिन आदरणीय शाहनवाज हुसैन जी, जो माननीय मुख्यमंत्री जी की जो बिहार के उद्योग के बारे में जो सोच थी, जो विकास के बारे में सोच थी उसके सपने को साकार करने में बहुत ही मार्केबल काम किया है और मैं खुशी से कहती हूं, बहुत खुशी होती है यह कहकर कि अभी के वर्तमान उद्योग मंत्री आदरणीय श्री समीर महासेठ जी बखूबी इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं ।

(क्रमशः)

टर्न-17/सत्येन्द्र/15.03.2023

श्रीमती शालिनी मिश्रा (क्रमशः) महोदय, काफी चर्चाएं हैं, काफी काम हमारे उद्योग मंत्री ने किया है जिसमें स्वरोजगार के तहत 10 लाख का लोन बिना गारंटर के किसी भी समाज के लोगों को दिया जाता है, किसी भी वर्ग के महिला और नौजवानों को दिया जाता है ।

प्रोत्साहन नीति, 2022 के तहत मुजफ्फरपुर में और फतुहा में बैग कलस्टर की शुरूआत की गयी है जिसमें जीविका दीदी को भी जोड़ा गया है । बियाडा में 9 इंडस्ट्रीयल एरिया है जहां 24 लाख स्क्वायर फीट जमीन पर प्ले इंडस्ट्रीयल सेड के रूप में विकसित किया गया है महोदय । जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम बिहार के उद्योग को हमेशा बढ़ावा देना चाहते हैं जबकि विपक्ष के माननीय सदस्य कह रहे थे कि वे बढ़ावा नहीं देना चाहते हैं जो सरासर गलत है । इन्हें सच्चाई स्वीकार नहीं है, मुख्यमंत्री जी के लिए बिहार के पूरे 12 करोड़ जनता उनका परिवार है और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उनका तन-मन-धन समर्पित है । महोदय, जिस तरह से बिहार में अभी काम हो रहा है, मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार उद्योग के क्षेत्र में भी अपने नये आयाम को छुयेगा । मान्यवर, इस अवसर पर हम आपके माध्यम से कुछ मांग करना चाहती हूँ । हमारे विधान-सभा क्षेत्र केसरिया में लीची की बहुत अच्छी पैदावार होती है और लीची का सहद अति उत्तम मानी जाती है इसलिए मेरा आग्रह है कि वहां पर एक लीची प्रोसेसिंग यूनिट खोला जाय । हमारे यहां महिषी में शिल्प उद्योग बंद पड़ा है इसके लिए बिहार सरकार ने 8 करोड़ का अनुदान भी दिया है फिर भी वह उद्योग बंद पड़ा है किसी लोकल कारणवश इसलिए इसकी भी शुरूआत की जाय । पूर्वी चम्पारण के बंद चीनी मिलें वह आपलोगों की वजह से बंद है, इस पर हम बाद में बात करेंगे । बिहार में पूर्वी चम्पारण के बंद चीनी मिलों की शुरूआत की जाय महोदय । टेक्निकल एडुकेशनल इंस्टीच्यूटस जो भी बिहार में है उन सबको एक एडुकेशनल हब बनाकर उसको उद्योग का दर्जा देने का काम करेंगे तो हमारे बिहार के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा । माननीय उद्योग मंत्री जी की अध्यक्षता में हम अगर एक कमिटी बनाते हैं तो बाहर के इंभेस्टर जो यहां आते हैं, प्रोसेस इजी करने के लिए एक टाईमलाईन फिक्स करते हैं, उनका पेपर वर्क 15 दिनों में पूर्ण करेंगे तो उद्योगपतियों को काफी बढ़ावा देगा आगे आने के लिए महोदय । चम्पारण का मरीचा चूड़ा, रोहतास करगहर के सोनाचूर चावल तथा कैमूर जिला के मोकरी बेतरी के काला जीरा चावल को जिओ टैग करवाने से हमारे बिहार में उद्योग की बहुत ही बढ़ोत्तरी होगी महोदय और वह यहां के लिए एक मिल का पत्थर साबित होगा । माननीय उद्योग मंत्री जी से मैं आग्रह करती हूँ कि यहां नयी परचेज पौलिसी जल्द से जल्द अप-टू-डेट कर के लागू किया जाय ताकि प्रोसेस सिम्पल हो जाय और लोगों को काम में डिले नहीं हो । महोदय, अन्य मंत्रालयों की तरह उद्योग मंत्रालय में भी अपिलीय ऑथिरिटी बनाने से काफी सुविधा हो जायेगी और लोगों को न्याय मिलने में काफी आसानी होगी। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से विपक्ष के सदस्यों से कहना चाहती हूँ, उनसे आग्रह करना चाहती हूँ कि अगर बिहार की सचमुच उन्हें चिन्ता है,

बिहारियों की सचमुच उन्हें चिन्ता है, बिहार के विकास की चिन्ता है महोदय तो केन्द्र सरकार से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवा दें महोदय यही इनके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी, इसके लिए उनको धन्यवाद बोलेंगे । महोदय, यह सिर्फ हमारी ही मांग नहीं है, इन सबों की भी मांग है । महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी के दूरदर्शिता से पर्यटन के क्षेत्र में भी ..

उपाध्यक्षः अब समाप्त कीजिये ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : महोदय एक मिनट का और समय चाहती हूँ । पर्यटन के क्षेत्र में भी बिहार में बहुत अच्छा काम हुआ है । केसरिया, नालंदा, राजगीर सहित कई जगहों पर पर्यटक आते हैं और हमारे हेरिटेज को निहारते हैं, आकर्षण के लिए काफी काम हमारी सरकार की है महोदय । पिछड़ा, अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक कल्याण के लिए भी काफी काम हुआ है महोदय, जिसका भरपूर लाभ इनलोगों को मिल रहा है । महोदय, अब मैं एक शेर कहकर अपनी बात को समाप्त करती हूँ जो मुख्यमंत्री जी की तरफ से आप सभी लोगों के लिए भी है और मेरी तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए है:-

अभी जिंदा है हौसला, उड़ान बाकी है,
यह हवाओं का सिलसिला है, तूफान बाकी है,
ये मुश्किलें, अभी तो चलना सीखा है,
छलांग बाकी है, असली मुकाम बाकी है ।

मान्यवर, अभी तो दिल्ली पहुंचना बाकी है । आपको और आदरणीय मुख्य सचेतक श्री श्रवण कुमार जी को बोलने का मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ।

उपाध्यक्षः माननीय सदस्य श्री इजहारूल हुसैन ।

श्री इजहारूल हुसैन : बहुत बहुत शुक्रिया उपाध्यक्ष महोदय । आपने मुझे उद्योग विभाग के बजट के पक्ष में बोलने का मौका दिया । मैं शुक्रिया अदा करता हूँ क्षेत्र की जनता को जिसने मुझे यहां पर उनकी आवाज बनकर उठाने का मौका दिया । उपाध्यक्ष महोदय, उद्योग विभाग के बजट को पढ़कर बहुत ही अच्छा लगा कि हमारी महागठबंधन सरकार उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कितने सजग और तत्पर हैं, तभी तो वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए उद्योग विभाग के अन्तर्गत वृहत, मध्यम तथा लघु प्रक्षेत्र के लिए 3253.81 करोड रू0 पुनरीक्षित उद्व्यय योजना मद में निर्धारित है जबकि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए योजना मद में 1545 करोड़ रू0 तथा स्थापना मद में 103.28 करोड़ रू0 यानि कुल मिलाकर 1648.82 करोड़ रू0 के बजट का प्रावधान किया गया है । इससे तो सरकार की तत्परता साफ दिखायी देती है । इसके लिए एक शेर बनता है सर-

काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाये,
हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाये,
यहां जिंदगी तो हर कोई काटता है,
जिंदगी जियो इस कदर की एक मिशाल बन जाये ।

महादय, मैं किशनगंज से आता हूँ जो भौगोलिक दृष्टिकोण से समस्त बिहार प्रदेश में कृषि उत्पादन के क्षेत्र में उत्तम जिला हैं । यहां की जलवायु धान, कपास, मखाना, गेहूं, आलू, अनानास आदि फसलों के लिए अत्यंत उपयोगी है साथ ही समस्त प्रदेश में किशनगंज ही एक मात्र जिला है, जहां के 30 प्रतिशत किसान चाय की खेती करते हैं जो बिहार को गौरवान्वित करता है, परन्तु यहां पर्याप्त राईस मिल नहीं है। एक भी जूट मिल नहीं है । मखाना प्रोसेसिंग यूनिट प्लांट नहीं है और न ही पर्याप्त फैक्ट्री है, इसका नतीजा यह है कि किसानों को अपने मेहनत पसीने से तैयार किये गये फसलों को पड़ोसी राज्य बंगाल के मंडी में औने-पौने कीमतों पर बेचने को मजबूर होना पड़ता है । इससे किसानों की आर्थिक स्थिति बद से बदतर दिखाई दे रहा है । हमारी सरकार एक मजबूत सरकार है और मुझे फक्र है कि मैं बिहार का निवासी हूँ जहां महागठबंधन की नीतीश सरकार ने शांति सुरक्षा एवं न्याय के साथ-साथ समस्त प्रदेश को चौतरफा विकास किया है । अंत में मैं अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उपमुख्यमंत्री जी, माननीय उद्योग मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि किशनगंज जिला में किसानों के हित में राईस मिल, जूट मिल, मखाना प्रोसेसिंग यूनिट प्लांट की फैक्ट्री खुलवाने की मांग करता हूँ । महोदय, हमारा क्षेत्र अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र है । यहां पर ज्यादातर अल्पसंख्यक लोग रहते हैं । मैं अल्पसंख्यक मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि सर, कब्रिस्तान की घेराबंदी वहां बहुत कम हो रहा है,जितना होना चाहिए उसका 1/3 भी नहीं हो रहा है तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि इस मद के पैसा को पोपुलेशन के हिसाब से दिया जाय ताकि किशनगंज में ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले और कब्रिस्तान की घेराबंदी हो। महोदय, सरकार की एक नीति है कि 2006-07 का लिस्ट था उसी के मुताबिक कब्रिस्तान की घेराबंदी होगी और जबतक पूरे राज्य में यह पूर्ण नहीं होगा तबतक दूसरा नहीं लिया जायेगा । मैं आग्रह करूंगा आपसे कि आप उस लिस्ट को न मानकर 2016-17 का जो लिस्ट है उसके हिसाब से बनायें ताकि हमारे जिला में कब्रिस्तान का घेराबंदी हो । महोदय, हमारे यहां अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो लगभग 10 साल से वैसे ही पड़ा हुआ है। पैसा का आवंटन होना चाहिए था 10 साल पहले लेकिन अबतक नहीं हुआ है।

(क्रमशः)

टर्न-18/मधुप/15.03.2023

श्री इजहारूल हुसैन (क्रमशः) : पैसा का आवंटन होना चाहिए था 10 साल पहले लेकिन अब तक नहीं हुआ है, सिर्फ 10 करोड़ रूपया देकर अब तक बंद है । मैं आग्रह करूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप कम से कम इस फंड को रिलीज करने के लिए केन्द्र सरकार से सिफारिश करें ।

सर, हमारे यहाँ मायोनरिटी के लोग काफी गरीब हैं, मैं सरकार से चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप ज्यादा से ज्यादा उद्योग वहाँ लगायें और वहाँ फैक्ट्रीज खोलें ताकि वहाँ के लोग बाहर पलायन न करें । मैं एक चीज और बता दूँ कि जो प्राइवेट लोग प्राइवेट कम्पनी खोले हैं चाहे वे टी फैक्ट्री हो चाहे आलू का गोडाउन हो तो लोग क्या करते हैं कि मनमौजी अपने हिसाब से उसका जमा लेते हैं । नतीजा यह है कि तीन महीना पहले ही बांड बाहर के लोगों से लेकर उसको भर दिया जाता है । नतीजा अब यह है हमारे यहाँ हजारों क्विंटल आलू वैसे ही जमीन पर पड़ा हुआ है । मैं सरकार से माँग करता हूँ कि इस सिस्टम को बदला जाय और लोकल लोगों को प्रायोरिटी के हिसाब से दिया जाय ।

उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त करें ।

श्री इजहारूल हुसैन : ताकि लोगों का जो इतनी मेहनत से खेती करते हैं, वह खेती बर्बाद नहीं हो।

उपाध्यक्ष : अब समाप्त कीजिये, समय हो गया ।

श्री इजहारूल हुसैन : ठीक है सर । आखिर में मैं आपके लिए, सरकार के लिए एक शेर पेश करना चाहता हूँ -

टूटने लगे हौसले तो यह याद रखना,
बिना मेहनत के तख्त ताज नहीं मिलता,
ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी,
क्योंकि जुगनू कभी रोशनी का मोहताज नहीं होता ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री राम सिंह ।

श्री इजहारूल हुसैन : महोदय, एक मिनट । मैं पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए एक शेर कहना चाहता हूँ ।

उपाध्यक्ष : अब आप बैठ जाइये, आपका समय हो गया ।

श्री इजहारूल हुसैन : एक मिनट सर ।

परवाज हैं दोनों एक ही फिजा के

शाहिन का जहॉ और है, करगश का जहॉ और है,

शाहिन वह चिड़िया है सर, जो चिड़िया अगर किसी शख्स के उपर से उड़ जाती है तो उसके साये एक गरीब आदमी राजा बन जाता है ।

उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त कीजिये ।

श्री इजहारूल हुसैन : लेकिन करगश एक वैसी चिड़िया है, अगर उसका साया पड़ जाय तो राजा रंक बन जाता है । फैसला आपको करना है कि इसमें करगश कौन है और शाहिन कौन है । बहुत-बहुत शुक्रिया । धन्यवाद । जय हिंद ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री राम सिंह ।

श्री राम सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के हमारे नेता माननीय विजय सिन्हा जी और सचेतक श्री जनक सिंह जी को मैं हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझको इनलोगों ने बोलने के लिए समय दिया । मैं बगहा की जनता को भी हार्दिक बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन लोगों ने एक छोटे-मोटे कार्यकर्ता को चुनाव जिताकर यहॉ भेजने का काम किया, इसलिये वहॉ की जनता का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ ।

मान्यवर, बिहार बजट 2023-24 के संदर्भ में बहुत सी बातें सदन में कही गई है । 14 करोड़ बिहारवासियों को फिर से नए-नए सपने दिखाए गए हैं । लेकिन मेरा सवाल उन सपनों को लेकर है जिसे बिहारवासियों ने, यहॉ के युवाओं ने बिहार के औद्योगिकीकरण की उम्मीदों में देखी थी । आज उन सपनों का क्या हुआ ? राज्य के औद्योगिकीकरण के लिए पिछली एनडीए सरकार में की गई कोशिशों का क्या हुआ ? क्या उसे भुला दिया गया है ? क्या राज्य का औद्योगिकीकरण महागठबंधन सरकार के लिए अहमियता नहीं रखता ?

मैं आपका ध्यान पश्चिम चंपारण के बगहा में मेगा टेक्सटाइल पार्क को लेकर देखे गए सपनों की ओर खींचना चाहूँगा । पिछली सरकार में इसके लिए जी-तोड़ कोशिशें की गई । हमारे क्षेत्र बगहा में 1719 एकड़ जमीन चिन्हित कर ली गई । स्थानीय लोगों में बड़ी उम्मीद जगी कि देश में बन रहे 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क में से एक बिहार में और पश्चिम चम्पारण के बगहा में बनेगा ।

मेरा कहना है कि सरकार बदल जाएगी तो क्या बड़ी योजनाओं के लिए प्रयास बंद कर दिए जाएंगे ? मुझे हैरानी हो रही है कि जिस मेगा टेक्सटाइल पार्क के लिए पिछली सरकार में हर दिन कुछ न कुछ प्रयास होता हुआ दिखता था, महागठबंधन की सरकार के 7 महीने बीत जाने के बाद भी पश्चिम चंपारण के मेगा

टेक्सटाइल पार्क की न कोई चर्चा है और न ही इसके लिए कोई प्रयास होता हुआ दिख रहा है ।

महोदय, जब समाधान यात्रा में माननीय मुख्यमंत्री चंपारण की धरती पर गये थे तो मैंने इसपर भी उनका ध्यान आकृष्ट किया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप बार–बार यहाँ से यात्रा शुरू करते हैं लेकिन अपनी पुरानी यात्राओं को याद कीजिए, जिस समय वे चुनावी यात्रा में 2005 में थे तो मैं उस मंच का संचालन कर रहा था, मैंने कहा था माननीय मुख्यमंत्री जी, यह गन्ना उद्योग क्षेत्र है, गन्ना बाहुल्य क्षेत्र है, गन्ना पर आप बोल दें, उन्होंने कहा था कि गन्ना का रेट हम ऐसा कर देंगे सरकार बनने के बाद कि उत्तर प्रदेश वाले लोग कहेंगे कि बिहार वाले गन्ना का रेट चाहिए । लेकिन मैंने उस समय कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने तो उसके समकक्ष तक नहीं किया जबकि उस समय बढ़ाने की बात किये थे । आज क्या हुआ ? मैंने उस समय कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी, तो उस समय अपने सचिव से पूछे थे कि उत्तर प्रदेश में उत्तम वेरायटी का क्या रेट है तो सचिव महोदय ने कहा था जो आई0ए0एस0 होते हैं उन्होंने कहा था 340, आप यही सचिव लोगों से, ब्यूरोक्रेसी के लोगों के घिर कर बैठे हुए हैं आपलोग, बहुत कुछ कर पाते, जो रेट वहाँ 350 उत्तर वेरायटी का था और बिहार में उसको 335 से 340 आप कर रहे हैं ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेगा टेक्सटाइल पार्क से पश्चिम चंपारण ही नहीं बल्कि पूरे राज्य की औद्योगिक तस्वीर बदल जाएगी । देश के टेक्सटाइल सेक्टर में जो सर्वाधिक बिहार के लोग कार्यरत हैं, वो अपने राज्य में लौटेंगे और बिहार के विकास में योगदान कर सकेंगे । पिछली सरकार में शानदार टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी भी बनाई गई । उद्योग का बहुत अच्छा माहौल बना था । आम नागरिकों से लेकर बिहार और अन्य राज्यों के उद्योगपतियों में भी काफी उत्साह नजर आ रहा था । पिछले 7 महीने में वो सब कुछ खत्म हो गया है ।

पश्चिम चंपारण के कुमारबाग में दो लाख वर्गफीट का प्लग एंड प्ले सुविधा के साथ औद्योगिक शेड का निर्माण भी शुरू हुआ था, उसमें भी तेजी लाने की जरूरत है। मेरा कहना है कि जब उद्योगों की स्थापना के लिए सरकार सजग नहीं होगी तो राज्य के युवाओं के लिए नौकरी और स्वरोजगार का सृजन कैसे होगा ।

महोदय, मुझे बताते हुए फक्र हो रहा है कि पिछली सरकार में, एनडीए की सरकार में उस समय जो उद्योग मंत्री शाहनवाज जी ने जो पहल किया था, वह सराहनीय है । अब मैं आज उसी बात को जैसे शालिनी जी कह रही थीं कि चश्मा का शीशा धूप और अन्य का उदाहरण दी थीं, क्या मेरे साथ 13 वर्षों तक बैठी रहीं, 13 वर्षों में एडीए शासन का जो फल है, मुख्यमंत्री जी जब उस समय भागलपुर और

नालंदा में प्रचार-प्रसार करने गए थे तो जो विभाग बिहार में भाजपा के पास था, स्वास्थ्य मंत्री चन्द्रमोहन राय जी थे और पथ निर्माण मंत्री नन्द किशोर जी थे, उसी का उदाहरण लोग दिया करता था नालंदा में और भागलपुर में, वह दिन याद कीजिए जब इन लोगों ने इस्तीफा दिया था ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, डेढ़ साल के अंतराल में 500 से औद्योगिक इकाईयों की स्थापना के लिए 36,253 करोड़ रूपए के निवेश प्रस्ताव आए । कई बड़ी औद्योगिक इकाईयाँ राज्य में स्थापित हुई - जैसे बरौनी में पेप्सी, पूर्णियां में इथेनॉल प्लांट । पिछली सरकार में पूरे राज्य में 17 इथेनॉल प्लांट की स्थापना के लिए जी तोड़ प्रयास हुए और जो जानकारी है कि 12 इथेनॉल प्लांट लगभग बनकर तैयार हैं । मुजफ्फरपुर के मोतीपुर ब्लॉक में 143.96 एकड़ भूमि में केन्द्र के सहयोग से मेगाफूड पार्क बनना शुरू हुआ । कई नामी कंपनियां यहाँ आ रही थीं । सिर्फ डेढ़ साल के अंतराल में बिहार में छोटी-बड़ी 87 औद्योगिक इकाईयां स्थापित हुईं ।

उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त कीजिए ।

श्री राम सिंह : मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के जरिए बिहार के युवाओं को आगे बढ़ने का शानदार मौका दिया गया । बीजेपी की सरकार में 16000 युवा उद्यमियों को 10-10 लाख की राशि उद्यम लगाने, उद्योग शुरू करने के लिए देने की प्रक्रिया शरू की गई थी । देश में सबसे बेहतर बिहार टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी लाई गई । निवेशकों को लाने के लिए पूरे देश में डेढ़ साल के अंतराल में दिल्ली, मुंबई, कोलकाला, लुधियाना, हैदराबाद, पटना समेत कई जगहों पर इंवेस्टर्स मीट हुए ।

उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त करें ।

श्री राम सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं शालिनी जी और सत्तापक्ष को उदाहरण देना चाहता हूँ, मैं यह कहना चाहता हूँ कि जब उस समय के प्रधानमंत्री डॉ0 मनमोहन सिंह जी का उदाहरण दीं तो क्या उस समय बिहार नहीं दिखाई पड़ा ।

उपाध्यक्ष : अब समाप्त कीजिए ।

श्री राम सिंह : धन्यवाद ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री शकील अहमद खाँ साहब, एक मिनट में अपनी बात रखिये ।

श्री शकील अहमद खाँ : महोदय, मायनोरिटीज के वजीर भी यहाँ बैठे हैं, मैं उनको सिर्फ तीन सुझाव देकर अपनी बात खत्म करूंगा । रेसिडेंसियल स्कूल बनाने का प्रावधान हमारी सरकार ने किया है तो मैं आपसे आग्रह भी करूंगा और सरकार को सुझाव भी दूँगा कि आपके 4 बन रहे हैं, और 10 जिले में इसी सत्र में इसी साल में अगर करवाने का प्रयास करेंगे तो यह बहुत अच्छा होगा क्योंकि जो बच्चे हैं उनके पढ़ने-लिखने का

साधन सरकार ने यह तय किया है । जो लघु उद्योग का मामला है जो पहले की स्कीम है ।

(क्रमशः)

टर्न-19/आजाद/15.03.2023

श्री शकील अहमद खॉं (क्रमशः) : जो लघु उद्योग का मामला है, जो पहले की स्कीम है । गवर्नमेंट ऑफ बिहार की पहले की जो स्कीम चल रही थी, उसी प्रावधान के तहत उस स्कीम में हमलोगों ने बजट भी बढ़ाया है । अगर उसको उसी तरह से लागू किया जायेगा तो यह बेहतर होगा । मेरे ख्याल से आप अपने डिपार्टमेंट में इस बात का जिक्र करेंगे । दूसरा यह है कि जिस तरह से ओ0बी0सी0, एस0सी0/एस0टी0 के लिए आपका बजटरी प्रोविजन है, उद्योग के लिए तो बजटरी प्रोविजन अलग है । उसी तरह से माइनोरिटी डेवलपमेंट के लिए भी अगर आप बजटरी प्रोविजन आप अलग कर देते हैं तो आपका काम आसान हो जायेगा, यही बात मुझे आपसे कहनी थी । बहुत ज्यादा कुछ नहीं है लेकिन इस सरकार के लिए सर, मुझे अभी कहा जा रहा था कि कुछ शेर कहिए तो लोग समझते हैं कि हम सिर्फ उर्दू का शायर पढ़ सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है ।

कहीं से भी नहीं आती जब रस्म रेखा,
जब अंधकार हो चारों तरफ

और फैलाया गया है इनलोगों के तरफ से पूरे देश में, तब योद्धा क्या करता है, मल्लाह क्या करता है,

कहीं से नहीं आती जब रस्म रेखा,
तुझे पथ दिखाती, त्वरित ज्योति रेखा,
न थक कर शिथिल हो, न भग कर अभागे,
उड़ा पाल मांझी, बढ़ाओ नाव आगे-बढ़ाओ नाव आगे ।

ये सब ठंढे हो जायेंगे, बहुत-बहुत धन्यवाद ।

उपाध्यक्ष : अब समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता ।

श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका और अपने पार्टी भाकपा माले के विधायक दल के नेता श्री महबूब आलम साहेब का और सचेतक श्री अरूण सिंह का आभार व्यक्त करता हूँ कि बजट सत्र में उन्होंने बोलने का मौका दिया । हम इस बात से अपनी शुरूआत करेंगे महोदय कि जो बिहार में माहौल है, वह उद्योग-धंधों के लिए कितना सही कौन बना रहा है, हम इस पर बात करेंगे । हम यह कहना चाहेंगे महोदय

कि उद्योग-धंधों के लिए बार-बार बात आती है कि उसके लिए बहुत अच्छा वातावरण चाहिए । अपराध नहीं होना चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए लेकिन यहां जो देखने में आ रहा है महोदय कि बेगुसराय में 7 वर्ष, 9 वर्ष की बच्चियों के साथ रेप होता है और उसमें XXX

(व्यवधान)

महोदय, यह सच्चाई है और छपरा में ......

उपाध्यक्ष : किसी का नाम नहीं लीजिए । प्रोसिडिंग्स से इसको निकाल दिया जाय ।

श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता : महोदय, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ । ये छपरा में मॉब लिचिंग करके और एक अल्पसंख्यक समाज के व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है । गया में एक मॉब लिचिंग करके एक व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है और फिर आपने देखा कि हमारे जिले में पश्चिम चम्पारण के मंझोलिया में भाजपा के कुशवाहा समाज से आने वाले भाजपा के एक नेता की हत्या करके और उन्हीं के ग्रुप के लोगों ने उनकी हत्या की और होली के हुड़दंग में जहां एक मस्जिद पर पथराव किया गया और उसमें एक मौत हो गयी, उस विवाद से उसको जोड़ने की एकदम नाकाप कोशिश हुई महोदय । हम यह कहना चाहते हैं कि ये क्या बिहार में हो रहा है । ये कह रहे हैं और इनके नेता जब उठते हैं, विपक्ष के माननीय सदस्य जब बोलने के लिए उठते हैं तो उनका मंत्रोचार है कि ''बिहार में भ्रष्टाचार है, बिहार में जो अपराध है'' ये मंत्रोचार से अपनी बात शुरू करते हैं । इसके वगैर, इस मंत्र के वगैर वो कोई बात नहीं बोलते । लेकिन है क्या महोदय, हकीकत तो यह है कि बिहार के माहौल को जो 1990 के दशक से हम यह कहना चाहते हैं कि 1990 के दशक से जो रणवीर सेना को संरक्षण देकर के तमाम अपराधी गिरोह का संरक्षण देकर के बिहार में जंगल राज खड़ा किया, जो आज भी हौवा खड़ा कर रहे हैं । यह बिहार के विकास के लिए यह कतई खतरनाक है महोदय और इसके लिए बिहार में अगर पूँजी निवेश नहीं हो रहा है तो इसके लिए हम समझते हैं कि यहां जो विपक्ष के माननीय सदस्य लोग हैं, वो जिम्मेवार हैं । उन्होंने बिहार को इतना बदनाम किया है कि आपको बिहार में पूँजी निवेश के जो प्रस्ताव आते हैं, वे भी लौट जाते हैं । हम आपसे कहेंगे कि यह जो एफ0डी0आई0 का प्रस्ताव 60,000 करोड़ रू0 का आया बाहर से यहां निवेश का, हुआ कितना तो 3500 करोड़, किसने महोदय यह माहौल खराब किया, हम यह कहना चाहेंगे महोदय कि पूरे तौर पर बिहार में ये नई पूँजी लाने नहीं देंगे और बिहार सरकार ने लगतार कोशिश किया कि बाहर से पूँजी आवे लेकिन ये बिहार को इतना बदनाम करते हैं कि बिहार में पूँजी नहीं आयेगी । दूसरी तरफ ये करते क्या है जो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए ताकि यहां के उद्योग-धंधों का विकास हो । इसमें

भी ये बाधक बने हुए हैं, इसमें भी ये कुछ भी नहीं बोलते हैं । चुनाव के समय में ये भाषण देंगे कि 10,000 करोड़ दें, 50,000 करोड़ दें, 1,00,000 करोड़ दें, 1,20,000 करोड़ दिया और उन्होंने कुछ दिया क्या, इन्होंने एक नया नहीं दिया। हम यह कहना चाहेंगे महोदय कि बिहार में जो विकास अवरूद्ध है उद्योग-धंधों के मामले में एक तरह से, बिहार ने जो भी काम किया है अपने बल-बूते पर किया है। हम आपके माध्यम से सदन से से कहना चाहेंगे महोदय कि हमारे यहां कुमारबाग में एक स्टील फैक्ट्री है, जो बन्द पड़ी है । इसका कौन जिम्मेवार है ? इसके लिए केन्द्र सरकार जिम्मेवार है । हम आपसे कहना चाहेंगे महोदय कि यहां कटिहार की जूट मिल के जीर्णोद्धार की बात आती है तो उसके लिए कौन जिम्मेवार है, वह तो केन्द्र सरकार के अधीन है, उसको क्यों नहीं जीर्णोद्धार किया? यहां बिहार में जो किसान खाद के लिए त्राहिमाम करते हैं और यहां बिहार में खाद का आवंटन कम किया जा रहा है । हम आपसे कहना चाहेंगे महोदय कि बरौनी का खाद कारखाना किनके जिम्मे है । बरौनी का खाद कारखाना उन्हीं के जिम्मे है और वह अपनी उत्पादन क्षमता से मात्र 40 प्रतिशत उत्पादन करता है, उसके जीर्णोद्धार के लिए कौन जवाबदेह है ? महोदय, यहां रोहतास में पैराईट्स की खादानें हैं । वहां एक भंडार है और फॉसफोरस आधारित खाद बन सकता है लेकिन वहां खाद का कारखाना खोलने की किसको जवाबदेही है ? यह जो हम समझत हैं कि यह सीधे केन्द्र सरकार की जवाबदेही है और ये लोग आरोप लगाते हैं कि बिहार में जो है भ्रष्टाचार है, अपराध है और ये पूरे तौर पर बिहार को बदनाम करते हैं । कभी ये ई0डी0 का छापा मरवाते हैं, कभी ये सी0बी0आई0 का छापा मरवाते हैं, कभी एन0आई0ए0 का छापा मरवाते हैं और इस तरह से तमाम समुदायों को यहां के तमाम लोकतांत्रिक पार्टियों को ये उत्पीड़न का शिकार बनाये हुए हैं । इसलिए हम आपसे कहेंगे महोदय कि यहां ही नहीं हो रहा है, हम यह कहना चाहते हैं, यह हमें बोलने नहीं देंगे महोदय....

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : शांति-शांति । जब विपक्ष की बारी आयेगी तो इसपर आपलोग जवाब देंगे ।

श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता : महोदय, ये लोग सच्चाई से इतने डरते हैं, आप देख रहे हैं, ये यहां पर ही नहीं, दिल्ली में भी देखा जा रहा है दो दिनों से संसद को ठप्प किया गया है और किस सवाल पर, अदाणी और मोदी जो पूरा घोटाला कर रहे हैं, देश की जनता के बैंकों का पैसा हजम कर रहे हैं, एल0आई0सी0 का पैसा ये लोग हजम कर रहे हैं, उसपर कोई सवाल नहीं करें । हम यह कहना चाहेंगे महोदय कि यह बिहार का जो सदन है, उसमें भी आपने देखा कि कैसे ये लोग बिहार के सवाल को दूसरे दिशा में ....

उपाध्यक्ष : अब समाप्त करें ।

श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता : ये लोग बिहार के सवालों को कैसे दूसरे दिशा में खेलने के लिए इन्होंने क्या किया- तमिल बनाम हिन्दी का विवाद किया, यह झुठ-मुठ का प्रचार किया और आपने देखा है कि पुराने जमाने में हमलोग देखते थे कि जमींदार का जो जमींदारी का विरोध करेगा, उसके अपराध का विरोध करेगा, जो सच्चाई का विरोध करेगा, उसी गरीब को सजा दी जाती थी । आज सदन में भी हमने यह देखा कि हमारे माननीय विधायक और विधान सभा में उप नेता श्री सत्यदेव राम पर हम समझते हैं कि उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने सच बात कही थी कि माईक तोड़ा गया है और माईक माननीय सदस्य ने तोड़ा है, हमने कोई अपराध नहीं की है, हमने कोई अपराध नहीं की है, हमने सच बोलने के लिए सजा कि उनसे खेद व्यक्त कराया जा रहा है .....

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब आप अपनी बात समाप्त करें । माननीय सदस्य श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी ।

श्री वीरेन्द्र कुमार गुप्ता : महोदय, दो मिनट में अपनी बात रखना चाहता हूँ ।

उपाध्यक्ष : आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता : मैं दो मिनट में अपनी बात रखना चाहता हूँ कि बाल्मीकीनगर में भोजपुरी फिल्मों का एक दौड़ चल रहा है और हम समझते हैं कि बाल्मीकीनगर को अगर शुटिंग सेंटर बनाया जाय फिल्मों का तो वहां पर पर्यटन का विकास होगा। वहां जो सोमेश्वर पर्वत पहाड़ी श्रेणी है, उसमें अगर एडवेंचर टूरिज्म की व्यवस्था की जाय तो उस क्षेत्र में पर्यटन से लाभ होगा । टूरिज्म के जो अधिकारी हैं, उनसे भी हम कहना चाहेंगे कि मात्र 0.39 प्रतिशत पिछले बजट का खर्च हुआ, इसके लिए कौन जिम्मेवार है, इसके लिए हम समझते हैं कि इसकी भी समीक्षा होनी चाहिए और बिहार की जरूरत के हिसाब से हरेक जिला में जो कलस्तर बनाया जा रहा है छोटे उद्योगों को बढ़ाने के लिए ....

उपाध्यक्ष : श्री वीरेन्द्र गुप्ता जी, अब आप बैठ जाईए । माननीय सदस्य श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी जी बोलें।

श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी : उपाध्यक्ष महोदय, हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि हम अपने नेता जीतन राम मांझी जी का और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का, तेजस्वी प्रसाद यादव जी का । हम यह कहना चाहते हैं कि हम जमुई जिला के सिकन्दरा विधान सभा से आते हैं, जो भगवान महावीर की जयंति है ......

(व्यवधान)

श्री कुंदन कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, ...

उपाध्यक्ष : जब आपका समय आयेगा तो आप उसका जवाब दे दीजियेगा ।

श्री कुंदन कुमार : उपाध्यक्ष महोदय .....

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप क्या बोलना चाहते हैं ? एक मिनट प्रफुल्ल कुमार जी, बैठ जाईए ।

श्री कुंदन कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री गुप्ता जी ने दो-दो गलत ब्यानी दिया है, इसको एक्सपंज कराना चाहिए । इन्होंने कहा कि बरौनी खाद कारखाना के बारे में केन्द्र सरकार ने 8600 करोड़ रू0 के लागत से इसको चालू किया है, ये गलत ब्यानी कर रहे हैं ......

उपाध्यक्ष : यह असंसदीय नहीं न है । आपकी बारी आयेगी तो आपकी पार्टी इसपर बोलेगी, इसमें असंसदीय कहां से है ।

माननीय सदस्य श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी जी ।

टर्न-20/शंभु/15.03.23

श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी : उपाध्यक्ष महोदय, हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं अपने नेता श्री जीतन राम मांझी, लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार और तेजस्वी प्रसाद यादव का । हम उस क्षेत्र से आते हैं जहां भगवान महावीर की जन्मस्थली है और एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है । हम बात करते हैं जब उद्योग विभाग का तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारे उद्योग धंधे को सफल बनाने का काम किया है, उसे लागू करने का काम किया है । महोदय, अभी युवाओं और महिलाओं के लिए उद्योग धंधे लगाने के लिए उन्होंने जो स्कीम चलाया है वह काबिले तारीफ है । बहरहाल हम कहना चाहेंगे अपने विधान सभा क्षेत्र के लिए कि जब लछुआर जैसे भगवान महावीर की जन्म स्थली है और वह एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है वहां उद्योग धंधे लगाने का बहुत सारा स्कोप है । साथ ही साथ हम अपने माननीय मंत्री उद्योग विभाग से मांग करना चाहते हैं कि जमुई जिला में बियाडा का कोई वैसा क्षेत्र कार्यरत नहीं है, वहां उद्योग धंधे लगाने के लिए बियाडा का कोई एजेंसी काम नहीं कर रहा है । हम अपने विधान सभा लछुआर के लिए.......

उपाध्यक्ष : ठीक है समाप्त कीजिए अब । आपका समय हो गया ।

श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी : उपाध्यक्ष महोदय, हम आपका संरक्षण चाहेंगे चूंकि हम भी अपने क्षेत्र से आते हैं । हमारे क्षेत्र की जनता देखती है कि हम विधान सभा में उनकी बात रखते हैं या नहीं रखते हैं । हमारा क्षेत्र कृषि जनित क्षेत्र है और वहां उद्योग धंधा लगाने का बहुत ज्यादा स्कोप है, जमीन भी उपलब्ध है और जो विधि व्यवस्था की बात है वहां एस0एस0बी0 सुरक्षा के लिए खड़ी है । हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र लछुआर में,

अलीगंज में, खैरा में जो भी उद्योग धंधा लगाया जाय वह काबिले तारीफ होगा । आपने मुझे समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अजय कुमार जी ।

श्री अजय कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, आज मैं कटौती प्रस्ताव के विपक्ष में और बजट के पक्ष में बोलने के लिए मैं खड़ा हूँ । महोदय, किसी भी राज्य का विकास औद्योगिक विकास के बिना नहीं हो सकता ये मैं नहीं कहता बल्कि नवीस कमीशन ने कहा था आजादी के बाद लेकिन हमारा ये आपसे अनुरोध है आपके माध्यम से और सरकार से मैं अपील करना चाहता हूँ कि अभी जो उद्योग के बारे में इधर से बोले जा रहे थे कि हमने किया, सरकार तो कर ही रही है और जो सरकार कर रही है वह आइने की तरह दिखायी पड़ रहा है वह कहने की जरूरत नहीं है । लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूँ अपने मित्रों से कि आप जो बोल रहे हैं कि हम बहुत कारखाना लगाये थे, मैं तो सिर्फ सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप कितने कारखाने लगाये थे ? देश की आजादी के बाद इस देश में 1947 के बाद जो उद्योग लगे थे सोवियत रूस की मदद से पंडित नेहरू के प्रयास से इस देश में उद्योग लगे थे और उद्योग को खतम करने का काम किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत जो आज दिल्ली में बैठी हुई है एक-एक उद्योग को बेचने का काम किया, किसी उद्योग को खड़ा करने का काम आपने नहीं किया, उद्योग पर बोलने का आपको क्या हक बनता है ? मित्रों मैं अपील करना चाहता हूँ, मैं सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि उद्योग सिर्फ विकास का सवाल नहीं है बल्कि उद्योग देश की, राज्य की आर्थिक प्रगति का एक रास्ता होता है और राज्य के अंदर नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर पर को पैदा करता है । हमारे बिहार का एक गौरवशाली इतिहास था । बिहार के अंदर काफी उद्योग लगाये गये थे- 20 चीनी मिल था, कई पेपर उद्योग थे उस मिल को खोलने का प्रयास आपने किया है, उस प्रयास को और तेज करने की जरूरत है । एक अपील हम और करना चाहते हैं कि बिहार के अंदर जो उद्योग धंधा बंद हो चुका है उस कारखाने को जिसके बारे में कह रहे हैं कि बेहतर उद्योग मंत्री थे, उन्होंने समस्तीपुर के चीनी मिल के जमीन को बियाडा के माध्यम से उद्योग नहीं बल्कि एक बड़ा मॉल खोलने के लिए दिया था। वे उद्योग खोलते तब आप दंभ भरते, वहां पर होटल खोलने के लिए जमीन दिया था । मैं सरकार से मांग करना चाहता हूँ कि उस एग्रीमेन्ट को कैंसिल कीजिए और उद्योग के जगह पर आप उद्योग खोलने की घोषणा कीजिए । मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप जब बोलने के लिए खड़े होंगे जवाब देने के लिए निश्चित तौर पर आप जवाब जरूर देंगे । आपसे मैं दूसरा अपील करना चाहता हूँ कि बिहार के अंदर एक रेशम उद्योग जो भागलपुर में था आज वह खतम हो गया है । उस रेशम उद्योग को भी आज

जिंदा करने की जरूरत है । वहां सब चीज है, हुनर है वहीं सारी चीजें हैं, लेकिन आज बंद पड़ गया है । उसे खोलने की अपील करते हुए मैं अपनी पार्टी की ओर से आपके इस बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री सूर्यकान्त पासवान ।

श्री सूर्यकान्त पासवान : उपाध्यक्ष महोदय, कटौती प्रस्ताव के विरोध में मैं बोलने के लिए खड़ा हूँ और सरकार के बजट प्रस्ताव के पक्ष में । महोदय, राज्य सरकार ने अपने प्रयास के बल पर राज्य में कई उद्योग शुरूआत करने की पहल की जिसके कारण अब बिहार में भी उद्योग का विकास रफ्तार पकड़ रहा है । आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान बिहार की औद्योगिक राजधानी बेगुसराय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ । बेगुसराय में दर्जनों छोटे बड़े कल कारखाने हैं जिसके कारण बेगुसराय प्रदूषण में भारत में नंबर वन का शहर है और विश्व में आठवें नंबर पर है । महोदय, बेगुसराय के लोग इस प्रदूषित हवा के कारण विभिन्न बीमारियों से ग्रसित हैं मगर इन कारखानों की ओर से कोई सुविधा नहीं मिल रही है । महोदय, मैं सरकार से मांग करना चाहता हूँ कि बेगुसराय में बिजली, पेयजल और अच्छे अस्पताल की व्यवस्था की जाय । महोदय, इतने कल कारखाने के बावजूद भी बेगुसराय में मजदूरों के लिए ई0एस0आइ0 अस्पताल और कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि कार्यालय नहीं है । महोदय, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत आज महिला पुरूष आत्मनिर्भर है जो दूसरों के यहां नौकरी करता था आज वह फैक्टरी का मालिक है । महोदय, राज्य सरकार पर्यटन को बढ़ावा लगातार दे रही है, मगर महोदय, बेगुसराय का कांवर झील एशिया का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील होने के बावजूद भी आज तक उपेक्षित है, अगर कांवर झील पर सरकार काम करे तो वह बिहार का डल झील बन सकता है । बेगुसराय का सिमरिया गंगा तट जहां पहले भी कुंभ मेला आयोजित होता रहा है और 2023 में भी अर्द्ध कुंभ आयोजित होना है, मगर सुविधा के नाम पर वहां कुछ नहीं है । महोदय, मैं कुछ बातों की ओर इशारा करना चाहता हूँ । भाजपा के राज में हमारे बिहार के अंदर हमारे एक माननीय सदस्य बोल रहे थे कि 8 हजार करोड़ की लागत से हम बेगुसराय के खाद कारखाना को चालू करने का काम किया, लेकिन बंद किसने किया यह भी इनको बोलना चाहिए । आज बेगुसराय के अंदर मक्का अनुसंधान केन्द्र है जिसको संयुक्त मोर्चा की सरकार ने बनाया था । आज वह उद्योग भी फल फूल रहा है, लेकिन इनके शासन काल में वह मृतप्राय था । महोदय, जिस बात का वे विरोध कर रहे थे मैं साहबपुर कमाल प्रखंड के पंचवीर गांव की घटना की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ जहां दो नाबालिक बच्ची का बलात्कार भाजपा समर्थित शराब माफिया ने किया है । महोदय, भाजपा के राज्य सभा सांसद राकेश सिन्हा के साथ आरोपियों

की तस्वीर वायरल हो रही है । महोदय, यही भाजपा का चरित्र है । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

टर्न-21/पुलकित/15.03.2023

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री विद्या सागर केशरी ।

श्री विद्या सागर केशरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उद्योग विभाग का जो बजट आया है उसके लिए माननीय सदस्य श्री अरूण शंकर प्रसाद द्वारा जो कटौती प्रस्ताव लाया गया है उसके पक्ष में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए वर्तमान सरकार का कोई इरादा नहीं है । उद्योग के लिए बजट 2023-24 में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की गयी है । उपाध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने निवेशकों के लिए सबसे बेहतर उद्योग नीति होने के बाद भी इसकी सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य बिहार में उद्योग की भारी कमी है । उद्योग नीति होने के बावजूद भी आखिर क्यों बिहार में उद्योग स्थापित नहीं हो पा रहे हैं, इसकी वजह क्या है, यह जानने की जरूरत है ।

उपाध्यक्ष महोदय, हालाँकि बिहार सरकार ने राज्य में निवेश के लिए कई तरह की योजनाएं शुरू की हैं लेकिन जमीनी स्तर पर इन योजनाओं का कोई विशेष फायदा होता नजर नहीं आ रहा है । उपाध्यक्ष महोदय, बियाडा की जमीन के संबंध में बहुत सारी बातें सामने आईं । हमारे यहां भी फारबिसगंज में बियाडा की जमीन पर स्टार फैक्टरी लगी है । करीब 20 साल होने को है, मक्का के लिए हमारा सीमांचल क्षेत्र, हब है, इतनी भारी मात्रा में मक्का की फसल लगती है । पंजाब और तेलंगाना के लोग भी यहां से मक्का के उत्पादन को ले जाते हैं और वहां उद्योग लगाकर के उसका फिनिसगुड्स देश के अन्य राज्यों को देते हैं लेकिन सीमांचल क्षेत्र में इस तरह की मक्का की फैक्टरी को उपेक्षित रखना कहीं से भी अच्छा संकेत नहीं जाता है । हमारे यहां जो स्टार फैक्टरी, फारबिसगंज में है, उसको जरूर से जरूर जितनी जल्दी हो उसको चलाने का प्रयास किया जाए ताकि उस क्षेत्र के, सीमावर्ती क्षेत्र के बहुत सारे मक्का के जो किसान हैं, व्यवसायी हैं उनको सही समय पर सही लाभ प्राप्त हो सके।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे यहां एक अररिया जिला में हलहलिया पंचायत में मांस फैक्टरी लगी हुई है, पशु वधशाला फैक्टरी लगी हुई है । मैंने बहुत लम्बे समय से इस पर वर्ष 2016 से अबतक कई बार सदन को अवगत कराया, हमने उस फैक्टरी को बंद कराने के लिए अवगत कराया था लेकिन उस फैक्टरी पर कोई समाधान आजतक नहीं निकला । माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने

तीन-तीन बार स्वहस्तलिखित और लोगों के द्वारा 3000 लोगों के हस्ताक्षरित, मोबाइल नं0 के साथ दिये थे, वहां की जो व्यवस्था है, वहां जो बसावट है, लाखों की बसावट में इस तरह की मांस फैक्टरी को लगा देना कहां से न्यायोचित है । बार-बार यह हवाला दिया जा रहा है कि क्या परेशानी खड़ी है ? वहां जाने के बाद महाशय, आपको पता लगेगा कि लाखों लोग, क्षेत्र के सात-आठ पंचायत के लोग वहां से पलायन करने को विवश है और वहां सात-सात ऐसी फैक्टरी है- अलसमीर, जकारिया, महरवा सात-सात ऐसी बड़ी-बड़ी फैक्टरी है जहां सात हजार पशुओं का रोज वध किया जाता है । बावजूद वहां की जो स्थिति है वह भयावह स्थिति है । महोदय, सात महीने की गर्भवती महिला वोमिटिंग करती है, सात महीने के बाद भी । वहां जो स्थिति है, वहां स्कीन में कैंसर के रोग देखें जा रहे हैं । जल में मक्खियों को बैठा देखा जा रहा है । जल में मक्खी बैठ रही है वहां इतना प्रदूषित पानी हो गया है कि वहां के लोग पानी पीने के लिए तरस रहे हैं । लोगों का उस क्षेत्र से पशुधन घट रहा है, लोगों के बच्चों से दूध का निवाला छीना जा रहा है । बावजूद सरकार उस पर कोई चिंता नहीं कर रही है । यह कैसे संभव होगा, इस पर सरकार एक ठोस निर्णय ले, एक कमेटी विधान सभा से बनायें और जाकर के कमेटी वहां की वस्तुस्थिति को देखें कि उस पशु वधशाला से लोगों की क्या स्थिति है ? यह भयावह स्थिति है । माननीय मुख्यमंत्री जी जब समाधान यात्रा के लिए गये हुए थे तो उस समय मैंने उस फैक्टरी को लेकर के उनको मैंने त्राहिमाम संदेश दिया था लेकिन उस पर भी अभी तक कोई ठोस कार्रवाई देखने को हमलोगों को नहीं मिली । प्रदूषण बोर्ड दिल्ली से कई बार टीम आई वहां और खानापूर्ति करके लाल फीताशाही के चंगुल में फंसकर के उस फैक्टरी को बढ़ावा देने का काम किया । मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय से कहना चाहूंगा कि इस तरह की फैक्टरी को ऐसे स्थान पर स्थापित किया जाए ताकि वहां किसी प्रकार की आम जनता को कोई परेशानी नहीं हो । इतनी बड़ी आबादी में, इतनी बड़ी बसावट में इस तरह की फैक्टरी को लगाना बहुत बड़ा अपराध महसूस किया जा रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में....

उपाध्यक्ष : अब कन्क्लूड कीजिये ।

श्री विद्या सागर केशरी : हमारे क्षेत्र में मखाना का जो काम है, बहुत बड़ी मात्रा में मखाना का काम होता है । देश में 90 प्रतिशत मखाने की उपज हमारे सीमांचल क्षेत्र से ही आती है और इतना बड़ा मखाना का उत्पादन होने के बावजूद भी किसी अच्छी फैक्टरी का आजतक निर्माण नहीं हुआ । माननीय उद्योग मंत्री, उसी क्षेत्र से आते हैं और इनको सब पता है कि मखाना के रोजगार की वहां क्या स्थिति पैदा की जा सकती है लेकिन मखाना की फैक्टरी को सिरे से खारिज कर दिया गया है । इस बार जो किसान

मखाना लगाये उनको मूल्य इतना कम मिल रहा है कि मखाना की खेती को छोड़ने को लोग विवश है । देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेन्द्र मोदी जी के द्वारा कोरोना के काल में मखाना के किसानों को प्रोत्साहित राशि कुछ उपलब्ध कराई गयी थी । वह बहुत ही अच्छा संदेश मखाना के किसानों को गया है । मैं चाहूंगा कि बिहार की सरकार भी मखाना की खेती को ध्यान में रखते हुए वहां उद्योग के नये आयाम को विस्तारित करें ।

उपाध्यक्ष : अब समाप्त कीजिये । माननीय सदस्य श्री चन्द्रहास चौपाल ।

श्री विद्या सागर केशरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम चाहेंगे कि जो इधर के उद्यमी है, जो इस इलाका के पूर्वी बिहार के और उत्तरी बिहार के जो मजदूर हैं वे बाहर नहीं जाएं, क्योंकि यहां पर भी बहुत सारी पलायन की समस्याएं हैं....

उपाध्यक्ष : अब समाप्त कीजिये ।

श्री विद्या सागर केशरी : महोदय, थोड़ा समय चाहिए ।

उपाध्यक्ष : अब हो गया, समय समाप्त हो गया है, अब बैठ जाइये ।

श्री विद्या सागर केशरी : महोदय, एक शेर को बोलकर मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूँ।

श्री चन्द्रहास चौपाल : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के नेता, बिहार के विकास पुरूष आदरणीय श्री नीतीश कुमार के प्रति कृतज्ञ हूं, गरीबों के मसीहा....

उपाध्यक्ष : एक मिनट रूक जाइये । ठीक है, आप बोलिये ।

श्री विद्या सागर केशरी :

यह मंदिर है, वही है, बस आसन बदल गया है
कुर्सियां क्या बदली, भाषण बदल गया है,
खुली कारखाना कहियां, बहार कहियां आई,
बिहार के मजदूर कब-ले, बाहर पिटाई,
हवा-हवाई बात होता, हवा से सरकार बा
बिहार में भ्रष्टाचार बा, नीतीश ए कुमार बा ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री चन्द्रहास चौपाल ।

श्री चन्द्रहास चौपाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूँ । राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष गरीबों के मसीहा, दलितों की आवाज आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं । सदन के नेता बिहार के विकास पुरूष आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के प्रति कृतज्ञ हूं और युवाओं के आइकॉन, बिहार के यशस्वी उप मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी एवं सदन के सभी मंत्रिगण, विधायकगण और अपनी विधान सभा की महान जनता के प्रति आभार प्रकट करता हूं । आज विरोधी दल के द्वारा उद्योग विभाग के कटौती प्रस्ताव के विरोध में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ । मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि तभी से

सभी विरोधी दल के माननीय सदस्यों के द्वारा उद्योग पर कई तरह के वक्तव्य सदन में दिये गये लेकिन द्वारा, विरोधी दल के द्वारा हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी पर भी कटाक्ष किया गया और इधर से यदि कोई कटाक्ष करते हैं तो उतावले होकर के सदन में आक्रोश फैलाना चाहते हैं । इतनी आपकी केन्द्र की सरकार ने कोशिश करने के बाद भी एक उद्योग मंत्री बिहार में नहीं हो पाया, आप जब सरकार में थे तो उद्योग मंत्री केन्द्र से लाने पड़े जो शाहनवाज हुसैन साहब हमारे सुपौल से आते हैं । वे लगातार केन्द्र में सांसद बने, केन्द्रीय मंत्री बने और बिहार में एक भी भाजपा में ऐसा विधायक नहीं था जिसको उद्योग मंत्री बनाते । हम उद्योग पर नहीं बोलेंगे, हम आज बुलेटन में पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग पर बोलना चाहेंगे ।

(क्रमशः)

टर्न-22/अभिनीत/15.03.2023

श्री चन्द्रहास चौपाल (क्रमशः) : माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आज जो बिहार में पिछड़ा वर्ग व अति पिछड़ा वर्ग का विकास हुआ है वह काबिले तारीफ है । आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में जो अति पिछड़ा वर्ग को पंचायती राज में आरक्षण देकर बिहार के जो पिछड़ा वर्ग की महिला, अति पिछड़ा वर्ग के पुरूष आजतक अपना प्रतिनिधित्व नहीं कर पाते, उन्होंने एक मौका देकर पंचायत चुनाव में अति पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देकर उनको, पिछड़ा वर्ग को एक पहचान बनाने का बिहार में स्थान दिया मैं उसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्रीजी का कृतज्ञ हूं । बिहार में आदरणीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मुखिया, सरपंच, समिति प्रमुख, जिला परिषद और जिला परिषद के अध्यक्ष पद पर अपना परचम लहराने का काम अति पिछड़ा वर्ग के लोगों ने किया इसके लिए अति पिछड़ा वर्ग के लोग माननीय मुख्यमंत्री के प्रति हृदय से कृतज्ञ हैं । इस विभाग द्वारा इस वर्ष छात्र-छात्राओं के सर्वांगीन विकास हेतु कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं । वित्तीय वर्ष 2008-09 में विभाग का वार्षिक योजना बजट 42 करोड़ 70 लाख 40 हजार मात्र से प्रारंभ किया गया, जो वित्तीय वर्ष 2022-23 में बढ़कर 19 अरब 99 करोड़ 14 लाख रुपये हो गये । 2008-09 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2022-23 में वार्षिक बजट योजना का आकार लगभग 74 गुना से अधिक बढ़ाया गया । पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित की जा रही हैं जो निम्नवत हैं:-

1. मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रि-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब समाप्त कीजिए ।

श्री चन्द्रहास चौपाल : मैं पुनः अपने विधान सभा सिंहेश्वर की आम जनता और सदन के प्रति आभार प्रकट करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या श्रीमती प्रतिमा कुमारी ।

श्रीमती प्रतिमा कुमारी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं बाबा साहब भीम राव अम्बेदकर को नमन करती हूं और आसन के प्रति आभार व्यक्त करती हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया ।

महोदय, विपक्ष द्वारा लाये गये कटौती प्रस्ताव के विपक्ष में बोलने के लिए मैं खड़ी हुई हूं । माननीय अध्यक्ष महोदय, देश एवं राज्य की आत्मनिर्भरता के लिए उद्योग का विकास होना जरूरी है । बिहार के उद्यमी योजना के तहत बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी और बिहार के माननीय उद्योग मंत्री परम आदरणीय श्री समीर महासेठ जी द्वारा बिहार में रहने वाले तमाम महिलाएं, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक और वैसे जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग हैं, जो सामान्य वर्ग से आते हैं उन सभी के लिए बिहार सरकार ने प्रावधान किया है जो कि काबिले तारीफ है और मैं सदन के माध्यम से बिहार की जनता को बताना चाहती हूं कि बिहार ऐसा राज्य है जहां दिव्यांगजनों और साथ ही थर्ड जेंडर के लोगों को समाज में सम्मान के साथ जीने के लिए उन्हें भी उद्योग विभाग द्वारा लोन उपलब्ध कराया जा रहा है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरीके से अभी जिस भी योजना और उद्योग की बात कही जाती है और विपक्ष के साथी माननीय सदस्य द्वारा बार-बार यह कहा जाता है कि हमारी सरकार, केंद्र की सरकार, भाजपा की सरकार ने की है । मैं सदन के माध्यम से यह बताना चाहती हूं कि जब देश आजाद हुआ था तो देश में एक सुई बनाने की भी फैक्ट्री नहीं थी और हमारे केंद्र में वर्तमान की सरकार जब हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, आदरणीय नेहरू जी जब देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने सुई की फैक्ट्री से लेकर के आज हवाई जहाज देश में बन रहा है । यह नींव कांग्रेस पार्टी की रखी हुई है, तो यह नहीं भूलना चाहिए कि जो केंद्र में होते हैं, जो सत्ता में होते हैं उनका कर्त्तव्य बनता है देश और राज्य का विकास करना । उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक शेर बोलना चाहती हूं, जिस तरीके से आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी और उनके परिवार को परेशान और तंग किया जा रहा है सी0बी0आई0, ई0डी0, एन0आई0ए0 और तमाम सरकारी संस्थानों का दुरूपयोग करके, तो मैं यही कहना चाहती हूं कि-

''रोज-रोज गिरकर भी मुक्कमल खड़ा हूं, ये मुश्किल देख मैं तुमसे कितना बड़ा हूं ।''

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार सरकार और माननीय मुख्यमंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने पटना में खादी मॉल की जो स्थापना किये हैं वह बहुत ही अनुकरणीय है । अभी हमारे शराबबंदी का अध्ययन करने के लिए कांग्रेस पार्टी के डेलिगेशन आदरणीय सत्यनारायण शर्मा जी के नेतृत्व में आठ सदस्यीय कमेटी आयी थी बिहार में और मैं भी भी उनके साथ थी । उनलोगों ने इच्छा जाहिर की कि वे यहां के खादी मॉल जाएंगे । सबलोग गये और उसमें महिलाएं भी थीं उन्होंने काफी तारीफ की और उन लोगों ने कहा कि मैं इस खादी मॉल की चर्चा अपने राज्य की सरकार, माननीय मुख्यमंत्रीजी से कहकर वहां भी खादी मॉल की स्थापना करवाउंगा ताकि वहां के लोग भी एक छत के नीचे, जो हैंडी क्रॉफ्ट के सामान हैं, जो स्थानीय बुनकर हैं, जो लोग स्थानीय स्तर पर अपना कुटीर उद्योग चला रहे हैं उनके सामानों की बिक्री हो सके और वे अपने मान-सम्मान और आर्थिक रूप से मजबूत हो सकें । बिहार सरकार शाहनवाज...

(व्यवधान)

बिल्कुल, मैं तो कह ही रही हूं कि जो सरकार होती है उसका कर्त्तव्य बनता है कि वह बिहार को, देश को आगे बढ़ाये । मैं उनको भी धन्यवाद देती हूं और अपने माननीय मुख्यमंत्रीजी को धन्यवाद देती हूं कि उनकी सोच इतनी सकारात्मक है कि जो उनके नेतृत्व में आयेगा वह अच्छा काम करेगा । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बिहार सरकार ने और उद्योग विभाग ने जो निर्णय लिया है कि मुजफ्फरपुर और पूर्णिया में खादी मॉल की स्थापना करेंगे यह काबिले तारीफ है । मैं सदन के माध्यम से, चूंकि आज पर्यटन और अल्पसंख्यक साथ ही पिछड़ा विभाग का भी बजट पेश होना है । पिछड़ा विभाग में जिस तरीके से पिछड़े बच्चों को, पिछड़े समाज के बच्चों को नि:शुल्क हॉस्टल मुहैया कराया जा रहा है, उनको 15 किलो अनाज दिया जा रहा है, उनको अनुदान के रूप में प्रति महीने एक-एक हजार रुपये दिये जा रहे हैं जो कि बहुत ही सराहनीय है, वैसे गरीब बच्चों के लिए जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं । अल्पसंख्यक विभाग ने जो तलाकशुदा महिलाएं हैं, जो गरीब हैं, जो पतियाप्ता हैं, जिनको पति ने छोड़ दिया है पहले दस हजार मिलता था, अब उनको स्वरोजगार शुरू करने के लिए, आत्म सम्मान के साथ जीने के लिए हमारे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री और माननीय मुख्यमंत्रीजी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने वैसी महिलाओं को 25 हजार रुपये देने का जो प्रावधान रखा है वह काबिले तारीफ है । महिला होने के नाते मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहती हूं ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, अब कंक्लूड कीजिए ।

श्रीमती प्रतिमा कुमारी : हमारे यहां भूईयां बाबा स्थान है और पर्यटक स्थल के रूप में मैं माननीय मुख्यमंत्रीजी से सदन के माध्यम से मांग करती हूं कि उसको पर्यटल स्थल के रूप में उसको डेवलप किया जाय । एक आखिरी है, मैं आपसे संरक्षण चाहती हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजनांतर्गत एस0सी0, एस0टी0, ओ0बी0सी0 के उद्यमियों की चयन प्रक्रिया ऑनलाईन द्वारा की जाती है । इसमें पाया जा रहा है कि आठ से नौ हजार आवेदन एक्सेप्ट होते हैं जबकि लाखों लोग इसमें आवेदन करते हैं । लॉटरी के माध्यम से उनको इसका फायदा मिलता है, तो मैं यही कहना चाहती हूं कि एक टाईम पीरियड हो और एक संख्या उसमें निर्धारित कर दी जाय कि उतने आवेदन के बाद उसको लॉक कर दिया जाय ताकि अन्य जो लोग ऑनलाईन आवेदन करते हैं..

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, अब समाप्त कीजिए ।

श्रीमती प्रतिमा कुमारी : अनायास ही वे परेशान होते हैं और वे हमलोगों से पूछते हैं कि मेरे आवेदन का क्या हुआ । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह ।

(व्यवधान)

श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह : पूरा सही ही रहेगा चिंता नहीं करनी है । आपलोगों की तरह थोड़े ही हैं कि जब इधर जायेंगे तो दूसरा दिखेंगे और जब उधर जायेंगे जो दूसरा दिखने लगेंगे । जो है वही बोला जायेगा, क्योंकि बदलने का काम आपलोगों का है । जब हमलोगों के साथ रहते हैं तो हमलोग आपको साधु नजर आते हैं और जैसे आपलोग दूसरे साईड में चले जाते हैं तो हमलोग शैतान नजर आने लगते हैं ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आसन की तरफ देखकर बात कीजिए । टोका-टोकी मत कीजिए, आपका समय बर्बाद होगा । आपका समय मात्र पांच मिनट है ।

श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह : महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्रीजी एवं उप मुख्यमंत्रीजी एवं मुख्य सचेतक श्री श्रवण सर को जिन्होंने मुझे उद्योग विभाग के कटौती प्रस्ताव के विपक्ष में बोलने का अवसर दिया है । मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने क्षेत्र के लोगों को जिन्होंने मुझे यहां भेजकर इस सदन में बोलने का अवसर प्रदान किया । किसी भी राज्य का विकास तभी संभव है जब वहां उद्योग का विकास हो । माननीय मुख्यमंत्रीजी के दिशा निर्देशन में..

(क्रमशः)

टर्न-23/हेमन्त/15.03.2023

श्री धिरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह (क्रमशः) : हमारी सरकार ने बड़े पैमाने पर उद्योगों को आकर्षित करने के लिए नये संस्थान स्थापित कर उद्योगों के विकास के लिए नई नीतियां लागू की हैं । साथ ही, लघु उद्योगों को भी प्रोत्साहित किया गया है । नई

पीढ़ी के उद्यमियों को आकर्षित करने के लिए राज्य सरकार ने बिहार स्टार्ट-अप नीति 2022 भी सूचीबद्ध की है, जिसके तहत हमारी सरकार नीतिगत पहल करते हुए पुराने ढंग के उद्यमों एवं स्टार्ट-अप जैसे नई पीढ़ी के उद्यमियों के लिए अनुकूल वातावरण बनाने का सार्थक प्रयास कर रही है । हमारे राज्य में समस्त औद्योगिक क्षेत्र को दो समूहों में बांटा गया है, एक कृषि पर आधारित है, दूसरा गैर कृषि आधारित है । कृषि उद्योग के रूप में खासकर गन्ना उत्पादित चीनी एवं दूध से उत्पादन होने वाले डेयरी प्रोजेक्ट प्रमुखता से कार्य कर रहे हैं । चीनी मिलों के द्वारा इथनॉल उत्पादन अब बड़े पैमाने पर किया जा रहा है जिससे आने वाले समय में हमारी पेट्रोल एवं डीजल पर निर्भरता कम होगी, साथ ही राज्य के प्रमुख 08 चीनी मिलों के द्वारा लगभग 88.5 मेगावाट बिजली का उत्पादन भी किया जा रहा है ।

हैण्डलूम और पावरलूम के माध्यम से बुनकर समुदायों की संख्या की उपस्थिति को ध्यान में रखते हुए उनकी संभावनाओं के उपयोग हेतु राज्य सरकार ने बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति सूचीबद्ध की ताकि हमारा बिहार राज्य देश में वस्तु और परिधान के उत्पादन का महत्वपूर्ण केन्द्र बन सके । जिसके तहत 10 करोड़ रुपये का पूंजीगत अनुदान 2 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली का प्रावधान किया गया है । फिर भी राज्य में निवेश को प्रभावशाली बनाने के लिए सात दिनों के अंदर जो आवेदन आते हैं, उन आवेदन और उनके ऊपर जो समस्याएं आती हैं, उनके समाधान का प्रावधान किया गया है । इस वर्ष 95 प्रतिशत मामले सुलझाये गये हैं और इसी का नतीजा है कि विगत 6 वर्षों में 60.86 हजार करोड़ रुपये का निवेश हमारे बिहार में हुआ है । भागलपुर संकुल का रेशम उत्पादन और निर्यात में देश में दूसरा स्थान है । बिहार के 358 में 14 जिलों में वस्त्रों के उत्पादन का कार्य होता है । उत्पादों में भागलपुर के रेशम से लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा-निर्देशन में पश्चिम चम्पारण के जिला पदाधिकारी श्री कुन्दन कुमार द्वारा चनपटिया स्टार्ट-अप जोन स्थापित कर गमछा, तौलिया, बिस्तर की खोल, साल, जीन्स आदि का निर्माण हो रहा है जिससे वहां के हजारों बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्राप्त हो रहा है ।

माननीय विकास पुरुष मुख्यमंत्री जी एवं उद्योग मंत्री जी से आग्रह है कि वाल्मिकी नगर में भी 14.5 एकड़ भूमि रेशम पालन के लिए आवंटित है, जिस पर पूर्व में कार्य प्रारम्भ हुआ था, परन्तु बाद में बंद हो गया । आग्रह है कि इसे पुनः प्रारम्भ कराया जाए जिससे वहां के युवाओं को रोजगार मिल सके । निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 को संशोधित कर बिहार औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना औद्योगिक क्षेत्रों के लिए जमीन उपलब्ध कराने हेतु भूमि आवंटन नीति वर्ष 2022 लागू की गई है । बियाडा ने सितम्बर, 2022 तक

9 जोनों में कुल 8231.9 एकड़ भूमि अधिग्रहण की है जिसमें सितम्बर, 2022 तक 680 शेड बनाए गए जो कि 634 उद्यमी को दिया जा चुका है ।

माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि मेरे विधान सभा के भितहां-मधुबनी प्रखण्ड में लगभग 2200 एकड़ भूमि टेक्सटाईल पार्क के लिए चिन्हित की गयी है । उक्त भूमि की सारी प्रक्रियाओं को पूर्ण कर टेक्सटाईल पार्क की स्थापना जल्द-से-जल्द की जाए ताकि क्षेत्र के हजारों युवाओं को रोजगार मिल सके और रोजगार सृजन हो सके ।

उपाध्यक्ष : अब समाप्त कीजिए ।

श्री धिरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह : महोदय, दो मिनट और । लघु और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए हमारी सरकार द्वारा 10 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है । मेरे विधान सभा के मिश्रौली और सेमरा में, खासकर मिश्रौली को स्टार्ट-अप जोन के लिए चुन लिया गया है । तो सरकार से आग्रह है कि वहां पर जल्द-से-जल्द स्टार्ट-अप का जो भी कार्य है शुरू किया जाय और सेमरा, जो कि अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है, में लघु एवं कुटीर उद्योग की अपार संभावनाएं हैं, इन्हें अवसर प्रदान कर उद्योग की स्थापना की जाय । जय नीतीश कुमार ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री इजहार अशफी ।

श्री इजहार अशफी : ''पक्ष-विपक्ष सब मिलकर करेंगे, सबको यह बतलाना है,
चहुंमुखी विकास करके जनता को दिखलाना है,
कैसे खुशहाली आये बिहार में, करके बंद शराब दुनिया को दिखलाना है ।''

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, युवा दिलों की धड़कन माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, मुख्य सचेतक श्री श्रवण कुमार जी, जिसने मुझे उद्योग विभाग के कटौती प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया । साथ ही, मैं विपक्ष के साथियों से खासतौर पर सुनने की गुजारिश करता हूं । साथ ही, धन्यवाद देना चाहता हूं अपने विधान सभा क्षेत्र की जनता का जिसने मुझे चुनकर भेजा, मैं उसका भी आभार प्रकट करता हूं । जिस तरह मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी बिहार के सर्वांगीण विकास के लिए दिन-रात मेहनत करते हैं, उसके लिए अपने विधान सभा क्षेत्र सहित बिहार की तमाम जनता की तरफ से आभार प्रकट करता हूं । आज मुझे उद्योग विभाग के मामले में मौका मिला, इसी संदर्भ में कहना चाहता हूं कि अभी के युग में उद्योग के क्षेत्र में विकास करके ही प्रदेश की दिशा और दशा बदल सकते हैं । मेरे प्रदेश के नौजवानों को रोजगार के लिए जिन्हें प्रदेश के बाहर जाना पड़ रहा है, इसको रोकने के लिए उद्योग क्षेत्र में

विकास अति आवश्यक है । जिसके लिए हमारी सरकार अनेकों योजनाओं का लोकार्पण कर प्रदेश को उद्योग क्षेत्र को बढ़ाने का काम कर रही है ।

महोदय, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से रोजगार के सृजन के साथ ही बिहार की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा । मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से पूरे प्रदेश के नौजवानों में खुशी है कि लोग अपने प्रदेश में ही रहकर रोजगार का सृजन करेंगे । मुख्यमंत्री उद्यमी योजनान्तर्गत सैकड़ों अभ्यर्थियों ने प्रशिक्षण लेकर ऋण की राशि से अपना करोबार शुरू किया है । जिससे आर्थिक सुधार में तेजी आयी है ।

उपाध्यक्ष : अब कन्क्लूड कीजिए । अपने क्षेत्र की बात कीजिए ।

श्री इजहार अशफी : महोदय, राज्य परिवेश में प्रोत्साहन को प्रभावशाली बनाते हुए सात दिनों के अंदर 95.31 प्रतिशत मामले को सुलझाया गया है । स्टार्ट-अप को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार नयी स्टार्ट-अप नीति...

उपाध्यक्ष : अब समाप्त कीजिए ।

श्री इजहार अशफी : सर, मेरा समय दस मिनट है ।

उपाध्यक्ष : समय का अभाव है । सरकार का उत्तर होगा ।

श्री इजहार अशफी : अब एक अच्छा माहौल पूरे प्रदेश में तैयार किया जा रहा है ताकि बाहरी निवेशकों को उद्योग लगाने और बड़े पैमाने पर राज्य में उद्योग स्थापित हो सके ।

उपाध्यक्ष : अब हो गया, समाप्त कीजिए । माननीय सदस्य श्री रामवृक्ष सदा ।

टर्न-24/धिरेन्द्र/15.03.2023

श्री रामवृक्ष सदा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज कटौती प्रस्ताव के विरोध में और सरकार के पक्ष में अपनी बातों को रखता हूँ । सबसे पहले मैं आपको और आपके आसन के प्रति आभार प्रकट करता हूँ ।

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

आभार प्रकट करता हूँ बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जी का और आभार प्रकट करता हूँ इस सदन के सारे सदस्यों को जिनके सामने मैं, आज माननीय अध्यक्ष जी ने मुझे बोलने का मौका दिया । अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूँ आज बिहार में कितना विकास हुआ है, आज उद्योग विभाग की माँग है और उस माँग में अगर विकास की बात की जाय तो बिहार में उद्योग विभाग में बहुत ज्यादा विकास हुआ है और उस विकास के मायने में मैं कहना चाहता हूँ, आज जो हमलोगों के क्षेत्र में, पूरे बिहार में जो बेरोजगार लोग पढ़-लिख कर, मैट्रिक कर, इंटर कर जो इधर-उधर घूमते थे, बौखते थे, आज हमारी सरकार ने उद्योग व्यवस्था में उद्योग विभाग स्थापित कर

उनको ऋण देने का काम किया और उस ऋण से आज वे सबल बनने का काम किये, उस ऋण से आज आगे निकलने का काम किये, यह हमारी सरकार की उद्योग व्यवस्था है बिहार की । महोदय, दूसरा मैं कहना चाहता हूँ, उद्योग में चाहे वह चमड़ा उद्योग की बात हो, चाहे कपड़ा उद्योग की बात हो, चाहे रेशम उद्योग की बात हो, चाहे चीनी मिल की बात हो, चाहे कल-कारखाने की बात हो, आज बिहार में जो सरकार है, इससे पहले सरकार में जो थे हमारे विरोधी साथी लोग, वे अभी भी बोलते हैं कि यही पाँच-छः महीना में क्या विकास हुआ ? लगभग 15 साल ये साथ में रहे, क्या ये 15 साल का हिसाब देंगे कि इनके रिजिम में क्या विकास हुआ । ये हिसाब नहीं दे सकते हैं, इसलिए नहीं दे सकते हैं कि इनका काम है सिर्फ अफवाह फैलाना, इनका काम है काम नहीं करना और न काम करने देना । इसलिए हमलोगों की सरकार में पहली प्राथमिकता है लोगों को काम मिले, लोगों को रोजगार मिले, लोगों को नौकरी मिले, लोगों को दवाई मिले, लोगों को स्वास्थ्य मिले, लोगों को शिक्षा मिले, लोगों को सड़क मिले और लोगों को औद्योगिक क्षेत्र में बहुत सारे विकास मिले, यह हमारी सरकार की प्राथमिकता है और इस पर हमारी सरकार काम कर रही है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब स्थान ग्रहण करें । अब सरकार का...

श्री रामवृक्ष सदा : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, मैं अपने क्षेत्र की एक समस्या रख देना चाहता हूँ और इसी में आपका आदेश आया समाप्त करने के लिए, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को रखते हुए पुनः उद्योग क्षेत्र ही नहीं बल्कि सरकार का आज बजट जो है पिछड़ा-अत्यंत पिछड़ा के लिए भी इन्होंने काम किया है, अल्पसंख्यक के लिए भी इन्होंने काम किया है और पर्यटक के क्षेत्र में जो काम अभी चल रहा है जो हुआ है वह देखने योग्य है, आप देख लीजिये जो पर्यटक की स्थिति लाखों में थी, आज पर्यटक की स्थिति करोड़ों में पहुँच गई है । विदेशी पर्यटक आज करोड़ों-के-करोड़ों लोग बिहार में आ रहे हैं, बिहार में औद्योगिक व्यवस्था स्थापित हो रही है । पिछड़ा-अत्यंत पिछड़ा छात्राओं के लिए एक ऐसा समय था जब बिहार में पढ़ाई के अभाव में पिछड़ा-अत्यंत पिछड़ा के बच्चें ऊपर तक स्कूल या कॉलेज नहीं पहुँच सकते थे, उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते थे लेकिन बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी की व्यवस्था के तहत आज गरीब के, जो अत्यंत पिछड़ा का बेटा है, जो पिछड़ा का बेटा है उनको भी सरकार ने लोन के माध्यम से उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए देश एवं विदेश भेजता है और बिहार का वह नाम रौशन करता है । महोदय, आगे मैं कहना चाहता हूँ विकास की बात है...

अध्यक्ष : अब संक्षेप में कहें ।

श्री रामवृक्ष सदा : महोदय, इन्हीं बातों के साथ पुनः आपके और आपके आसन के प्रति आभार प्रकट करते हुए मैं अपने क्षेत्र की एक माँग रखना चाहता हूँ । अलौली विधान सभा के अंतर्गत खगड़िया प्रखंड में कृषि विभाग का 200 एकड़ से ज्यादा जमीन बहुत दिनों से इमली फार्म में पड़ा हुआ है, अगर वहाँ, हमलोगों के खगड़िया जिला में, मक्का ऐशिया महादेश में सबसे ज्यादा खगड़िया जिला में होता है, उस जगह पर, उस स्थान पर अगर कोई औद्योगिक व्यवस्था स्थापित हो जाये तो सरकार का बहुत बड़ा काम आयेगा । इन्हीं बातों के साथ मैं साथियों से कहना चाहता हूँ:

छेड़ने पर मन भी बौचाल हो जाता है दोस्त,
टूटने पर आईना भी काल हो जाता है दोस्त,
मत करो हवन उतना गरीबों के खून से,
जलने पर कोयला भी लाल हो जाता है दोस्त ।

इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को समाप्त करता हूँ । धन्यवाद ।

अध्यक्ष : सरकार के उत्तर के पहले माननीय मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग बोलेंगे ।

श्री मो॰ जमा खान, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तावित करता हूँ कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के वित्तीय वर्ष 2023-24 की अवधि में...

(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, अल्पसंख्यक विभाग में बहुत सारे काम हुए हैं जो हमारे नेता ने निदेशित किया है काम करने के लिए । मुख्य काम मैं बताना चाहता हूँ, जो आवासीय विद्यालय है, हमारे माननीय सदस्य बड़े भाई शकील साहब ने बात को रखी है, मैं उन्हें आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आवासीय विद्यालय बनेगा । साथ ही, ऋण खोलने के लिए कह रहे थे, तीन बिन्दुओं की बात उन्होंने रखा है माननीय सदस्य श्री शकील साहब, तीनों बिन्दुओं पर मैं सहमत हूँ, सरकार काम करेगी । शुक्रिया ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग । संक्षेप में अपना पक्ष रखें ।

श्रीमती अनिता देवी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं के लिए विभिन्न छात्रवृत्ति एवं मेधावृत्ति योजना, छात्रावास योजना, प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण योजना, कौशल विकास योजना, कन्या आवासीय विद्यालय, छात्रावास अनुदान योजना, छात्रावासों में खाद्यान्न आपूर्ति योजना आदि योजनाएँ संचालित हैं ।

पिछड़े वर्ग एवं अत्यंत पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं के लिए पूर्व में संचालित केन्द्र प्रायोजित अन्य पिछड़ा वर्ग प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत भारत सरकार की नई मार्गदर्शिका में पी॰एम॰-यशस्वी योजना के तहत कक्षा-1 से 8 के छात्र/छात्राओं

को वंचित कर मात्र कक्षा-9 एवं 10 के छात्र/छात्राओं को ही आच्छादित किये जाने के आलोक में वित्तीय वर्ष 2022-23 से राज्य योजना के अंतर्गत कक्षा-1 से 10 तक अध्ययनरत सभी छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति से आच्छादित करने हेतु मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है । वित्तीय वर्ष 2021-22 में अन्य पिछड़ा वर्ग प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत कुल 95,39,477/- (पंचानवे लाख उनचालीस हजार चार सौ सतहत्तर) छात्र/छात्राओं के बीच कुल राशि लगभग 1123.89 करोड़ रुपये मात्र (ग्यारह सौ तेईस करोड़ नवासी लाख) वितरित की गयी है ।

पिछड़े वर्ग एवं अत्यंत पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं के लिए केन्द्र प्रायोजित अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति तथा राज्य स्कीम के तहत मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर योजना संचालित है । वित्तीय वर्ष 2018-19 में छात्रवृत्ति वितरण की प्रक्रिया में एन॰आई॰सी॰ पोर्टल में हुई तकनीकी समस्या के आलोक में शिक्षा विभाग के द्वारा पी॰एम॰एस॰ पोर्टल विकसित किया गया एवं वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21 तथा 2021-22 के लिए एक साथ आवेदन प्राप्त की गई है, जिसके अंतर्गत अब तक 9,52,243 (नौ लाख बावन हजार दो सौ तैंतालिस) छात्र/छात्राओं के बीच कुल राशि लगभग 475.03 करोड़ रुपये (चार सौ पचहत्तर करोड़ तीन लाख) छात्रवृत्ति वितरित की गयी है । अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदया, आप संक्षिप्त में अपने पक्ष को रखिये ।

श्रीमती अनिता देवी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 2023-24 में इस विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु राज्य स्कीम मद में 1,70,014.00 लाख रुपये मात्र (सत्रह सौ करोड़ चौदह लाख), केन्द्र प्रायोजित स्कीम मद में केन्द्रांश के तहत 13,379.00 लाख रुपये मात्र (एक सौ तैंतीस करोड़ उन्यासी लाख), राज्यांश के तहत 4,460.00 लाख रुपये (चौवालीस करोड़ साठ लाख) तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 11,052.17 लाख रुपये (एक सौ दस करोड़ बावन लाख सत्रह हजार) मात्र का बजट उपबन्ध प्रस्तावित है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदया, आपका जो भाषण है...

श्रीमती अनिता देवी, मंत्री : महोदय, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

अध्यक्ष : आप उसको टेबल पर रख दें, वह प्रोसीडिंग का अंश बन जायेगा ।

(माननीय मंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का वक्तव्य- परिशिष्ट-1 द्रष्टव्य)

श्रीमती अनिता देवी, मंत्री : महोदय, हमारी सरकार हर तरह से प्रेरित है कि पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज के जो हमारे लोग हैं, हर तरह से उनको मदद की जा रही है

छात्र/छात्राओं को और केन्द्र सरकार जो है कक्षा-1 से 8 तक के छात्रों को जो छात्रवृत्ति मिलती थी 400, 800 और 1200 वह बंद कर दिया गया है । मैं आप लोगों से भी कहती हूँ कि आप लोग पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग पर बहुत जोर दे रहे हैं, आप लोग भी माननीय प्रधानमंत्री जी से जोर लगाइये । पिछड़ और अति पिछड़ा का जो पैसा है और हक है वह दे दें ।

अध्यक्ष : अब अपना स्थान ग्रहण किया जाय । माननीय मंत्री, उद्योग विभाग ।

टर्न-25/संगीता/15.03.2023

सरकार का उत्तर

श्री समीर कुमार महासेठ, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आज मुख्यतः जो कटौती प्रस्ताव में जो सम्मानित हमारे श्री अरूण शंकर प्रसाद जी, सम्मानित श्री श्यामबाबू, श्री विद्या सागर केशरी जी, श्री फते बहादुर सिंह जी, श्रीमती शालिनी मिश्रा जी, श्री इजहारूल हुसैन साहब, रिस्पेक्टेड मो0 शकील अहमद खाँ साहब, श्री वीरेन्द्र बाबू, माननीय अजय कुमार जी, श्री सूर्यकान्त पासवान जी, श्रीमती प्रतिमा कुमारी जी, माननीय रिंकू बाबू, मो0 असफी साहब, माननीय रामवृक्ष सदा जी सबों की बातों को उद्योग विभाग निश्चित तौर पर ग्रहण करने का काम किया । आज इस उपलक्ष्य में हम निश्चित तौर पर अपने माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी के साथ-साथ सारे सदन के प्रति हम एक सोच के लिए हम कहना चाहता हैं चूंकि समय जितने वक्त लग गये उसमें लगता है कि हम अपनी बातों को पूरा नहीं कर पाने का है लेकिन अरूण शंकर प्रसाद जी ने स्टार्ट किया था, उन्होंने कहा था कि पिछली सरकार के बारे में, हम हालांकि चर्चा नहीं करना चाह रहे थे, मेरा मानना है आजादी के बाद जितने भी मंत्री हुए, जिन लोगों का लक्ष्य था बिहार को आगे बढ़ाने का, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अभी की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी उसमें लगे हुए हैं और उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक छोटी लकीर को बड़ी लकीर खींचने में हमलोग लगे हुए हैं इतना ही कहेंगे किसी के बारे में कहना नहीं है लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि जितनी जानकारी आप हमारे अरूण शंकर बाबू आपने कहा इथेनॉल फैक्ट्री, मधुबनी में उनका किया हुआ था, तो जानकारी रखना चाहिए, जिनका उन्होंने किया था वे छोड़कर के भाग करके चले गए, उन्होंने फैक्ट्री नहीं खोला, कारण आप पता कर लें लेकिन...

(व्यवधान)

नहीं, हमारा शिकायत करने का नहीं है, किसी को भी जब आधारभूत संरचना मिलेगा देश में अगर हम इस बात को फिर हम डाइवर्ट करें कि कोई व्यापारी कोई उद्योगपति

देश में सिर्फ सम्मान चाहता है वह नहीं चाहता है कि भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं उसे पाला पड़ता है 14 इन्स्पेक्टर राज का, उस 14 इन्स्पेक्टर राज के दर्द को आपको समझना पड़ेगा, उसमें भारत के प्रधानमंत्री ने कितना कम किया, ये बात उन व्यापारियों और उद्योगपति के पास जाकर आप बात करें तो ज्यादा अच्छा है । मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरे सारे व्यापारी उद्योगपति यह चाहते हैं कि जो हैं लगातार रहें लेकिन मैं व्यापार अच्छे ढंग से करूं, मैं इन्कम टैक्स और ईडी और सेल्स टैक्स जी0एस0टी0 से परेशान नहीं होऊं, जो टैक्स बनता है हन्ड्रेड परसेंट आप टैक्स लीजिए, व्यापारी उद्योगपति कभी नहीं चाहता है लेकिन परेशानी की वजह से चाहे वह जो हो, हम नहीं कहना चाहते हैं, हम कहना चाहेंगे कि उन व्यापारियों को परेशानी नहीं हो, कैसे मान-सम्मान बढ़े इस बात के लिए हमारी चर्चा होनी चाहिए और जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेंट पहले था उससे आगे बढ़ करके हमलोगों ने काम करने का प्रयास किया है । छह महीने के अंदर अगर आप चर्चा करना चाहते हैं तो मात्र जान लें कि 30 हजार लगभग ऐसे माननीय मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत अलग-अलग कैसे 30 हजार लोगों को हमलोगों ने 10 लाख से, चूंकि आप याद करें कि कोरोना काल के बाद यह सोच बना था कि बिहार में रोजी-रोजगारपरस्त कैसे बनाया जाय उस सोच के बाद जहां हमारे बिहार के लोग बाहर काम कर रहे थे आपने देखा होगा अलग-अलग कलस्टर बन रहे हैं, लोग पहले आना नहीं चाहते थे अब स्वतः आने का प्रयास कर रहे हैं यह क्यों...

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, नेता प्रतिपक्ष कुछ कहना चाहते हैं ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : हमारी सहानुभूति आपके साथ है कि आपको बहुत कम समय दिया गया । उद्योग की क्या स्थिति है इसी से अनुमान लगाया जाता है, नेत्र हमें केवल दृष्टि देता है, हम क्या देखते हैं यह हमारी भावनाओं पर निर्भर करता है । आपने अच्छी बात बोला कि जो इथेनॉल में आया था वह भाग गया, पलायन क्यों हो रहा है...

श्री समीर कुमार महासेठ, मंत्री : नहीं, मधुबनी का...

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : पलायन क्यों हो रहा है उद्योगपतियों का, उद्योगपतियों का पलायन क्यों है, हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार व्यापारियों का क्यों हो रहा है, इसपर आपका विजन और नीति क्या है...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, उद्योग विभाग ।

(व्यवधान)

श्री समीर कुमार महासेठ, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हम सिर्फ अपनी बातों पर आयेंगे...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : नहीं, नहीं आप देखिए, माननीय मंत्री जी का उत्तर हो रहा है इसलिए आप स्थान ग्रहण करें ।

(व्यवधान)

श्री समीर कुमार महासेठ, मंत्री : निश्चित तौर पर, ये जो अरूण बाबू...

अध्यक्ष : अब स्थान ग्रहण करें आप ।

(व्यवधान)

अरूण शंकर बाबू आप अपना स्थान ग्रहण करें ।

(व्यवधान)

सरकार के उत्तर को सुनिए । आपको जो कहना था आपने कहा । माननीय मंत्री उद्योग विभाग ।

(व्यवधान)

श्री समीर कुमार महासेठ, मंत्री : पूरा विपक्ष चाहता है मधुबनी पर चर्चा करें । आज तक एक रुपया इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट खर्चा नहीं किया था पिछली सरकार ने भी नहीं किया । अभी जाकर देख लीजिए अपनी नजरों से कितना काम हो रहा है, इन्फ्रास्ट्रक्चर पर डेवलपमेंट हो रहा है, शालिनी मिश्रा जी ने बहुत स्पष्ट कहा जिस चश्मे से आप देखना चाहते हैं...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : टोका-टोकी न किया जाय ।

श्री समीर कुमार महासेठ, मंत्री : उस चश्मे से कृपया न देखें असलियत पर बात करें । अगर इन्फ्रास्ट्रक्चर पर खर्चा हो रहा है तो निश्चित तौर पर खर्चा हो रहा है, वह 38 जिले में 75 इन्डस्ट्रीयल एरिया में खर्चा हो रहा है, कोई एक मधुबनी पर खर्चा नहीं हो रहा है इस बात की चर्चा होनी चाहिए । आज बजट में हमारा टारगेट है कि लगभग हम जिस ढंग से...

(व्यवधान)

अरे भाई, हम अपने ही टाईम में हम कह सकते हैं, आप बजट की बात करते हैं, पुनरीक्षित बजट में डबल से ज्यादा हो गया इस बात की चर्चा यहां होनी चाहिए । अगर हुआ है तो कम से कम इस सरकार को आपको धन्यवाद देना चाहिए कि क्यों हुआ, कहीं न कहीं आप 38 जिलों की बात करते हैं जो आप वन डिस्ट्रिक्ट वन आप कहिएगा कि वन नेशन की बात कर रहे हैं, हम तो कहते हैं ट्राई पोर्ट बना करके आप

विशेष राज्य के दर्जा की बात करते तो ज्यादा अच्छा था, आप नहीं कर पाए तो कम से कम स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की बात करिए चूंकि पूरे देश में 377 है और बिहार में एक भी नहीं है और आप मदद करते तो बिहार में भी 3-4 एरिया में होता । एक जी0आई0 टैग की बात हो रही है अगर मखाना डेवलप हुआ, मधुबनी पेंटिंग डेवलप हुआ तो पूरी दुनिया में मधुबनी पेंटिंग का नाम हो रहा है कि आर्ट कल्चर में इतना किसी जगह अवार्ड नहीं मिला जितना मधुबनी को मिला । आप जाकर देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी अभी गए थे, वहीं मीटिंग किए थे और जो हमारा उस तरह का जो मधुबनी को विकास के लिए है उसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहिए । यहां से आप अपने एरिया में 22 एकड़ जमीन की बात करते हैं जहां पर इतना ज्यादा जहां 10 हजार एकड़ पूरा उद्योग विभाग चाहता है कि हमारा लैंड बैंक बने हरेक जिले में लैंड बैंक बने...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी...

श्री समीर कुमार महासेठ, मंत्री : उद्योग का पार्ट है...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी आप आसन की तरफ देखकर के बोलिए ।

श्री समीर कुमार महासेठ, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हम बार-बार यह कहना चाहते हैं...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप बोलिए, अपना बोलते रहिए आप ।

श्री समीर कुमार महासेठ, मंत्री : उद्योगों की स्थापना हेतु प्रत्येक स्तर पर निवेशकों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं । राज्य का हर युवा उद्यमी बने, यह उपभोक्ता का बिहार है सर, यह उद्यमी का बिहार बनाने के लिए हमलोग सोच रहे हैं जो कभी आज तक नौकरी करता था, रोजी रोजगार पाता था, खुद उद्यमी बने, उस तरह का हम तो यह चाहेंगे कि जितने लोग हैं अध्यक्ष महोदय, उस बात के लिए मन में सोचें केवल अगर कटाक्ष करना था तो 10 रुपया घटाने की बात क्यों किए, क्यों आप चाह रहे हैं कि 10 रुपये से कम करने का और उचित उपयोग कर राज्य के त्वरित विकास के लिए बिहार औद्योगिक निवेश 2016 लागू की गई और आप जान लें जो परचेज पॉलिसी जो अभी लागू हुआ है वह कहीं न कहीं बताता है कि पूरा भारत सरकार 25 परसेंट परचेज पॉलिसी में दी है और बिहार सरकार हन्ड्रेड परसेंट देने जा रही है और बड़े बड़े उद्योगों को 2 परसेंट ज्यादा भी होगा तो उसे सबसे ज्यादा ऑर्डर मिलेंगे और 7 परसेंट तक अगर छोटे उद्योग होंगे कुटीर उद्योग उनको लाभ मिलेगा । हम कह सकते हैं यह 12 से 13 करोड़ का बिहार है लेकिन आपने एक प्लानिंग अगर किया

होता तो नेपाल का रास्ता इधर से ही आता है वह आपमें जुड़ जाता, नॉर्थ-ईस्ट का रास्ता इधर से ही जुड़ जाता है । आपके उद्योग धंधे में इतना बराबर बनता और पिछली बार आपने कहा था हन्ड्रेड उद्योग निश्चित तौर पर मधुबनी में छोटे-बड़े एक सौ उद्योग खुलेंगे, और आपका भी सहयोग लेंगे और आपसे भी आग्रह करेंगे घोर आर0एस0एस0 के जितने लोग हैं उनसे हम आग्रह करेंगे आपको बिहार में भय लगता है आइए उद्योग विभाग और आपको पूरा सरकार पूरी तरह मदद करके आपको भी उद्योग खुलवाने में बिहार सरकार मदद करेगी और आपलोग बिहार को बदनाम करने पर मत तुलिए और जो रोजी रोजगार के लिए बाहर से पलायन करके आए उनको कैसे सेटल करें इस बात का दर्द आपको होना चाहिए । अगर दर्द है तो बिहार की तरक्की में आप निश्चित तौर पर अपना योगदान करते रहेंगे । अन्यथा अभी तो इधर से अपोजिशन में गए हैं फिर कहां नहीं कहां मुझे तो डर लगता है कि जनता के बीच जाने के बाद आपकी क्या स्थिति होने वाली है वह हम देख रहे हैं इसलिए हमने कहा है और आने वाला वर्ष 2023-24 के लिए भावी योजनाएं जो हमारी हैं, वित्तीय वर्ष 2023-24...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप, आप अपना जारी रखिए ।

टर्न-26/सुरज/15.03.2023

श्री समीर कुमार महासेठ, मंत्री : 2023-24 में मशीन उपकरण का क्रय करते हुये सुचारू रूप से दोनों कोकून बैंक का संचालन जीविका, बिहार, पटना द्वारा किया जाएगा ।

पूर्णिया एवं मुजफ्फरपुर में बिहार राज्य खादी बोर्ड के जमीन पर खादी मॉल का निर्माण आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार द्वारा किया जा रहा है, जिसके लिये 16 करोड़ 50 लाख रुपये दिये गये हैं ।

(व्यवधान)

निश्चित तौर पर भविष्य में आप हमारे साथ रहेंगे तो मधुबनी के साथ दरभंगा को भी जोड़कर के वहां भी किया जायेगा । लेकिन आपको रटना पड़ेगा, मुख्यमंत्री योजना के बारे में सोचना पड़ेगा कि पूरे बिहार में अगर 30 हजार लोगों को मिल गया । एक छोटी-सी बात है अगर 30 हजार मिला है, आने वाले टाइम में फिर 8 हजार लोगों को मिलेगा । पूरे बिहार में...

(व्यवधान)

सुन लिया जाये, 38 जिले आप घूमेंगे, हरेक जिले में पांच सौ लोग महिलाएं, पुरूष, युवा, अल्पसंख्यक और साथ में दिव्यांग को भी जोड़ा गया है जो आज तक के हिस्ट्री में नहीं है और 176 दिव्यांग को बिहार में उद्यमी योजना में डाला गया है । इसलिये आप कह सकते हैं कि किसी जिला में जायेंगे तो पांच सौ से ज्यादा नये उद्योग खोलने वाले आपको मिलेंगे और वे कहीं न कहीं आपके भाई-भतीजा ही होंगे । चूंकि आपलोग ज्यादा उद्योग की बात करते रहे हैं इसलिये हमने कहा कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में नवचयनित लगभग 8 हजार लाभुकों को प्रशिक्षण प्रदान कर उनके बीच राशि का वितरण भी किया जायेगा ।

राज्य के युवाओं को बिहार का स्टार्ट-अप यूनिकॉर्न बनाने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है । इसके लिये पटना के मौर्यालोक कॉम्पलेक्स में 64...

(व्यवधान)

जी नहीं, आप जाकर देख लीजिये, अपका मन-मिजाज बदल जायेगा । चाईना, रूस में पानी आता था न तो कुछ लोग यहां छाता निकाल लेते थे इसलिये वह बात भी नहीं करिये । समझे न, इसलिये पटना के मौर्यालोक चले जाइये । आप जाकर के देखिये कि कैसे सौ रुपया में एक दिन के लिये मिलता है और एक हजार से...

(व्यवधान)

पहले जाकर के तो देखिये कि कैसे उद्यमी को क्या आवश्यकता है ? क्या केवल व्यापारियों के लिये आप बोलते हैं । वोट तो ले लेती है भारतीय जनता पार्टी लेकिन व्यापारी के पक्ष में कोई बात आपलोग नहीं कर रहे हैं । आपको करना चाहिये तो जाकर देखिये, आप उद्यमी बनाने का काम करिये । अगर कोई कमियां हो रही है तो सरकार को बताने का करें ताकि सरकार उसको इम्प्रूव करके उसको पूरा करने का प्रयास करे, ये मेरा है । ढ़ेर सारा क्लस्टर खुला आप बताइये कि टेक्सटाइल क्लस्टर खुला...

(व्यवधान)

हम तो कह रहे हैं कि छः महीना के अंदर 30 हजार लोगों को 10 लाख रुपया दिया गया । हरेक जिला में 5 सौ लोगों को...

(व्यवधान)

नहीं, नहीं भारतीय जनता पार्टी दिल्ली से भेज दी थी । भारतीय जनता पार्टी का एक रुपया का है इसमें इन्वेस्ट...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सरकार के द्वारा अपने जो कार्य किये गये हैं इस स्टेट के लिये वे इसके संबंध में अपना पक्ष रख रहे हैं । मैं आपलोगों से चाहूंगा कि आप शांति बनाकर के सुनिये ।

श्री समीर कुमार महासेठ, मंत्री : अगर मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में जो 10 लाख रुपये तक है, आपका को-ऑपरेशन तब होगा । सारा बिहार का बैंक 10 लाख से 1 करोड़ रुपये तक उसको देने का दृढ़ संकल्पित रहे तो बिहार को कोई पीछे नहीं हटायेगा । एस0एल0बी0सी0 की बैठक होती है, कमिटमेंट होता है उस तरह के प्रस्ताव के साथ...

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : माननीय मंत्री जी आप व्यापार से भी जुड़े हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं । बिहार स्टार्ट-अप योजना भ्रष्टाचार की भेंट क्यों चढ़ गया और अफसर के द्वारा दबाव डालकर के व्यापारियों और उद्योगपतियों से वसूली की व्यवस्था पर सरकार की क्या नीति है ?

अध्यक्ष : हो गया । माननीय उद्योग मंत्री जी ।

श्री समीर कुमार महासेठ, मंत्री : आपलोग जाने वाले नहीं न हैं अंत तक सुनियेगा, क्यों चिंता करते हैं ? समय है जब तक बैठिये नहीं तो हमको लगा कि जाने वाले हैं इसलिये ऐसा बोल रहे हैं । मेरा यह कहना है कि राज्य के युवाओं को स्टार्ट-अप यूनिकॉर्न में जो आपने कहा प्रोत्साहन किया जा रहा है । इसके लिये पटना का मौर्यालोक जाकर के देखें । जो...

(व्यवधान)

हमने कह दिया न आप जाकर देखेंगे न और 10 लाख से लेकर के जो 50 लाख तक हमारा है आप उसे एक करोड़ तक, आप भी बैंकों को चूंकि आपका कोई बिहार में बैंक नहीं है, कोई स्थापित नहीं है और जब आप सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं तो सदन छोड़कर के भागेंगे इसलिये कि बिहार के प्रति कितना दृढ़ संकल्पित हैं, व्यापारियों के प्रति कितना दृढ़ संकल्पित हैं, उद्योगपतियों के प्रति हैं तो पहले के सरकार में और आपके सरकार में 80 करोड़ आबादी बराबर 100 उद्योग पूरे देश में हो गया, बिहार में वैसी बात नहीं है ।

अध्यक्ष : नेता प्रतिपक्ष, माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं, आप स्थान ग्रहण कीजिये । आप बोलिये मंत्री जी । आप स्थान ग्रहण कीजिये ।

श्री समीर कुमार महासेठ, मंत्री : यहां 104 सीट और 200 से अधिक सीटों के लिये आधुनिक कार्यालय विकसित किया जा रहा है...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : नहीं, नहीं आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये । माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं ।

श्री समीर कुमार महासेठ, मंत्री : पी0एम0एफ0एम0ई0 के तहत अधिक लाभुकों को उद्योगों के लिये बैंक ऋण उपलब्ध कराने हेतु भी डिपार्टमेंट दृढ़ संकल्पित है ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गये)

हरेक जिलों में जा रही है, इस कार्य को कर रही है और मलबरी रीलिंग यूनिट की स्थापना धमदाहा पूर्णियां में भी किया जाना है ।

बांका जिला में दो तसर कोकून बैंक को संचालित करने की भी योजना है । बजट मांग- वित्तीय वर्ष 2022-23 में उद्योग विभाग का स्कीम मद में पन्द्रह अरब पैंतालीस करोड़ रुपये तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय में अंठानवे करोड़ चौहत्तर लाख सोलह हजार रुपये अर्थात कुल प्राक्कलन सोलह अरब पैंतालीस करोड़ चौहत्तर लाख सोलह हजार रुपये था । वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्कीम मद में पन्द्रह अरब पैंतालीस करोड़ रुपये तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय में एक सौ तीन करोड़ इक्यासी लाख तिहत्तर हजार रुपये अर्थात कुल प्राक्कलन सोलह अरब अड़तालीस करोड़ इक्यासी लाख तिहत्तर हजार रुपये की अनुदान मांग का प्रस्ताव सदन के पटल पर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी समय कम है । क्या माननीय...

श्री समीर कुमार महासेठ, मंत्री : महोदय, अनुरोध कर लेते हैं । महोदय, मैं माननीय सदस्यों से...

अध्यक्ष : आप रख दीजिये, प्रोसीडिंग का हिस्सा बनेगा ।

श्री समीर कुमार महासेठ, मंत्री : आग्रह करता हूं कि राज्य के औद्योगिकीकरण को गति देने में सहयोग करने हेतु प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव को वापस लेते हुये उद्योग विभाग की मांग को सर्वसम्मति से पारित करने की कृपा करें और इसको हमारा प्रोसीडिंग का पार्ट बनाया जाय ।

(माननीय मंत्री, उद्योग विभाग का वक्तव्य- परिशिष्ट-2 द्रष्टव्य)

अध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य श्री अरूण शंकर प्रसाद अपना कटौती प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''इस शीर्षक की मांग 10/- रुपये से घटाई जाय ।''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अब मैं मूल प्रस्ताव को लेता हूं ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

"उद्योग विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 16,48,81,73,000/- (सोलह अरब अड़तालीस करोड़ इक्यासी लाख तिहत्तर हजार) रुपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय ।"

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

मांग स्वीकृत हुई ।

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक-15 मार्च, 2023 के लिये स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या-48 है, अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभाग को भेज दिया जाय।

(सदन की सहमति हुई)

अब सभा की बैठक वृहस्पतिवार, दिनांक-16 मार्च, 2023 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिये स्थगित की जाती है ।

XXX - आसन के आदेशानुसार अंश विलोपित किया गया ।

(माननीय मंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का वक्तव्य- परिशिष्ट-1)

बिहार सरकार

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

माननीया मंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, का बजट भाषण

माननीय अध्यक्ष / सभापति महोदय,

मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के बजट पर माँग प्रस्तुत करने की अनुमति दी है।

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्गत पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र / छात्राओं के लिए विभिन्न छात्रवृत्ति एवं मेधावृत्ति योजना, छात्रावास योजना, प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण योजना, कौशल विकास योजना, कन्या आवासीय विद्यालय, छात्रावास अनुदान योजना, छात्रावासों में खाद्यान्न आपूर्ति योजना आदि योजनाएँ संचालित हैं।

पिछड़े वर्ग एवं अत्यंत पिछड़े वर्ग के छात्र / छात्राओं के लिए पूर्व में संचालित केन्द्र प्रायोजित अन्य पिछड़ा वर्ग प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत भारत सरकार की नई मार्गदर्शिका में पी0एम0–यशस्वी योजना के तहत कक्षा–1 से 8 के छात्र / छात्राओं को वंचित कर मात्र कक्षा–9 एवं 10 के छात्र / छात्राओं को ही आच्छादित किये जाने के आलोक में वित्तीय वर्ष 2022–23 से राज्य योजना के अंतर्गत कक्षा–1 से 10 तक अध्ययनरत सभी छात्र / छात्राओं को छात्रवृत्ति से आच्छादित करने हेतु **"मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना"** की स्वीकृति प्रदान की गई है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में अन्य पिछड़ा वर्ग प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत कुल 9539477 (पंचानवे लाख उनचालीस हजार चार सौ सतहत्तर) छात्र / छात्राओं के बीच कुल राशि लगभग रू0 1123.89 करोड़ (रू0 ग्यारह सौ तेईस करोड़ नवासी लाख) मात्र वितरित की गयी है।

पिछड़े वर्ग एवं अत्यंत वर्ग के छात्र / छात्राओं के लिए केन्द्र प्रोयोजित अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति तथा राज्य स्कीम के तहत मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर योजना संचालित है। वित्तीय वर्ष 2018–19 में छात्रवृत्ति वितरण की प्रकिया में एन0 आइ0 सी0 पोर्टल में हुई तकनीकी समस्या के आलोक में शिक्षा विभाग के द्वारा पी0 एम0 एस0 पोर्टल विकसित किया गया एवं वित्तीय वर्ष 2019–20, 2020–21 तथा 2021–22 के लिए एक साथ आवेदन प्राप्त की गई है, जिसके अंतर्गत अबतक 9,52,243 (नौ लाख बावन हजार दो सौ तैतालिस) छात्र / छात्राओं के बीच कुल राशि लगभग रू0 475.03 करोड़ (रू0 चार सौ पचहत्तर करोड़ तीन लाख) छात्रवृत्ति वितरित की गयी है।

E/Rajesh Sn/Report

मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना राज्य सरकार की एक महत्वकांक्षी योजना है, जिसके तहत बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा आयोजित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा (पी0टी0) में उत्तीर्ण होने वाले अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को अग्रेत्तर तैयारी हेतु एकमुश्त रू0 50,000/–(रूपये पचास हजार) तथा संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा (पी0टी0) में उत्तीर्ण होने वाले अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को एकमुश्त रू0 1,00,000/– (रूपये एक लाख) का लाभ प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत अबतक बी0पी0एस0सी0 (पी0टी0) उत्तीर्ण करने वाले कुल 5518 (पाँच हजार पाँच सौ अठारह) एवं यू0पी0एस0सी0 (पी0टी0) उत्तीर्ण करने वाले कुल 143 (एक सौ तैतालिस) छात्र/छात्राओं अर्थात कुल 5661 (पाँच हजार छः सौ इकसठ) छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया है। विगत वर्ष में बी0पी0एस0सी0 (पी0टी0) उत्तीर्ण करने वाले लाभान्वित 882 (आठ सौ बयासी) छात्र/छात्राओं में से 71 (इकहत्तर) अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्रा तथा यू0पी0एस0सी0 (पी0टी0) उत्तीर्ण करने वाले लाभान्वित कुल 24 (चौबीस) छात्र/छात्राओं मे से 05 (पाँच) अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्रा अंतिम रूप से संबंधित परीक्षाओं में चयनित हुए हैं।

➢ **पिछड़े वर्ग एवं अत्यंत पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं के सर्वांगीण विकास हेतु राज्य सरकार के द्वारा निम्नांकित नई पहल किए गए हैं:–**

- राज्य में पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन को सुगम बनाने हेतु मुख्यालय स्तर पर निदेशालय तथा क्षेत्रीय स्तर पर– प्रमंडलीय उप निदेशक पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी तथा अति पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुमंडल पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी कार्यालय का सृजन करते हुए निदेशालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों को संचालित कर दिया गया है। निदेशालय स्तर पर कुल 26 (छब्बीस) पद तथा क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए 420(चार सौ बीस) सहित कुल 446 (चार सौ छियालिस) पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गयी है। अनुमंडल पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी के 139 (एक सौ उनचालीस) पदों पर नियुक्ति हेतु चयन की कार्रवाई बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा की जा रही है।

- पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग अन्तर्गत संचालित 12 एवं प्रस्तावित 27 कुल 39 अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय हेतु विभिन्न कोटि के 1092 (एक हजार बानवे) शैक्षणिक पद एवं 273 (दो सौ तिहत्तर) गैर शैक्षणिक पद अर्थात 1365 (एक हजार तीन सौ पैसठ) पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गयी है। सृजित पदों के आलोक में नियुक्ति हेतु नियमावली तैयार करने की अग्रेत्तर कार्रवाई की जा रही है।
- राज्य के 11 जिलों में 12 अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय संचालित हैं। राज्य सरकार द्वारा सभी 38 जिलों में अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय की सैद्धांतिक स्वीकृति के आलोक में अबतक 28 जिलों में 520 आसनवाले 29 विद्यालय निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गयी है एवं निर्माण कार्य चल रहा है।
- वित्तीय वर्ष 2021–22 में कुल 10 छात्रावास एवं वित्तीय वर्ष 2022–23 में 7 जिले में 1–1 अर्थात् कुल 7 छात्रावास के निर्माण की स्वीकृति प्रदान करने के उपरांत अब सभी 38 जिलों में छात्रावास संचालित होंगे। अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावासों में आवश्यक सामग्रियों/उपस्करों की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु सामग्रियों की मानक सूची प्रति छात्रावास रू0 18,59,000/– (रू0 अठारह लाख उनसठ हजार) मात्र की दर से कुल रू0 4,27,57,000/– (रू0 चार करोड़ सताईस लाख संतावन हजार) मात्र व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है।
- जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास योजना के अन्तर्गत सभी जिलों में 1–1 छात्रावास के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसमें कुल 33 जिलों में छात्रावास संचालित हैं एवं शेष 05 जिलों में निर्माण कार्य चल रहा है, जिसे आगामी वित्तीय वर्ष में संचालित कर दिया जायेगा।
- प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण योजनान्तर्गत पात्रता की शर्तों के तहत वार्षिक आय अधिसीमा को रू0 1.00 लाख (रू0 एक लाख) से बढ़ाकर रू0 3.00 लाख (रू0 तीन लाख) किया गया है एवं राज्य के 36 जिलों में केन्द्र का नियमित संचालन किया जा रहा है।

- मुख्यमंत्री व्यवसायिक पाठ्यक्रम मार्गदर्शन एवं उत्प्रेरण योजनान्तर्गत पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को व्यवसायिक पाठ्यक्रमों यथा–प्रबंधन, विधि आदि की तैयारी एवं संबंधित रोजगारपरक प्रतियोगी परीक्षाओं तथा उच्च शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति में भागीदारी बढ़ाने हेतु तैयारी निःशुल्क करायी जाती है। योजनान्तर्गत 10 केन्द्रों की स्वीकृति प्रदान की गयी है एवं नामांकन प्रक्रिया चल रही है। इन सभी केन्द्रों का ग्रीष्मकालीन सत्र अप्रैल माह से प्रारंभ होगा।
- जननायक पुस्तकालय एवं डिजिटल अध्ययन केन्द्र योजनान्तर्गत राज्य में संचालित सभी जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास, अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय+2 उच्च विद्यालयों में डिजिटल अध्ययन के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सुनिश्चित करने हेतु जननायक पुस्तकालय एवं डिजिटल अध्ययन केन्द्र के रूप में विकसित किया गया है, जिससे छात्रों का प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के साथ ऑनलाईन पढ़ाई एवं ऑनलाईन परीक्षा अभ्यास करने में सुविधा होगी।

माननीय मुख्यमंत्री की समाधान यात्रा कार्यक्रम के दौरान स्वयं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा रोहतास जिला में मोकर, सासाराम में नवनिर्मित 520 आसन वाले अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय, तथा समस्तीपुर जिला में नवनिर्मित जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास का उद्घाटन किया गया। समाधान यात्रा के क्रम में नवादा जिला में भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास का निरीक्षण किया गया एवं व्यवस्था पर खुशी जाहिर की गयी।

आगामी वित्तीय वर्ष 2023–24 में छात्रावासों/प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्रों/अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों में छात्र/छात्राओं को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु स्मार्ट क्लास के माध्यम से कराये जाने पर विचार किया जा रहा है। वर्तमान में 11 जिलों में 12 अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है तथा शेष 27 जिलों में भी अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों का संचालन शुरू करने की कार्रवाई की जा रही है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 में इस विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु राज्य स्कीम मद में रू0 170014.00 लाख (रूपये सत्रह सौ करोड़ चौदह लाख) मात्र, केन्द्र प्रायोजित स्कीम मद में केन्द्रांश के तहत रू0 13379.00 लाख (रूपये एक सौ तैतीस करोड़ उन्यासी लाख) मात्र, राज्यांश के तहत रू0 4460.00 लाख (रूपये चौवालीस करोड़ साठ लाख) तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में रू0 11052.17 लाख (रूपये एक सौ दस करोड़ बावन लाख सत्रह हजार) मात्र का बजट उपबन्ध प्रस्तावित है।

हमारी सरकार समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के विकास के लिए कटिबद्ध है। हमें विश्वास है कि राज्य सरकार की इन योजनाओं से पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोगों का सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक स्तर सुदृढ़ होगा।

अतः मैं वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के माँग संख्या–11 अंतर्गत स्कीम मद में रू0 167653.00 लाख (रूपये सोलह सौ छिहत्तर करोड़ तिरपन लाख) मात्र तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय में रू0 11052.17 लाख (रूपये एक सौ दस करोड़ बावन लाख सत्रह हजार) से अनधिक माँग प्रस्तुत करती हूँ।

मंत्री
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग
कल्याण विभाग, बिहार, पटना।

****

(माननीय मंत्री, उद्योग विभाग का वक्तव्य - परिशिष्ट-2)

उद्योग मंत्री का बजट अभिभाषण– 2023

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आपकी अनुमति से मैं वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए उद्योग विभाग का बजट अनुमान प्रस्तुत कर रहा हूँ।

➤ राज्य सरकार द्वारा उद्योगों की स्थापना हेतु प्रत्येक स्तर पर निवेशकों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। राज्य का हर युवा उद्यमी बने, सरकार का यह प्रयास है। बिहार में विपुल मात्रा में उपलब्ध प्राकृतिक एवं मानव संसाधनों का उचित उपयोग कर राज्य में त्वरित औद्योगिक विकास के लिए **बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016** लागू की गई है।

इस नीति के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष में **10 मार्च, 2023 तक कुल चार सौ इकतीस ऑनलाईन आवेदन प्राप्त हुए जिसमें चार सौ पाँच आवेदनों को स्टेज–1 क्लियरेंस प्रदान किया गया, जिसमें प्रस्तावित निवेश राशि आठ हजार पाँच सौ अन्ठावन करोड़ तेईस लाख रूपये है। कुल 144 इकाइयों को वित्तीय प्रोत्साहन हेतु क्लियरेंस दिया गया, जिसमें निवेश राशि दो हजार बेरानवे करोड़ नौ लाख रूपये है, तथा कुल 71 इकाइयाँ कार्यरत हुईं, जिसमें निवेश राशि एक हजार एक सौ दो तिरानवे लाख रूपये है। 71 कार्यरत ईकाईयों में तीन हजार छः सौ तिरपन व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ।**

➤ औद्योगिक प्रोत्साहन नीति–2011 एवं बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति–2016 के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष में **470** करोड़ सब्सिडी (अनुदान) विमुक्त की **जाएगी।**

❖ औद्योगिक विकास को गति देने हेतु बिहार सरकार द्वारा बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 (यथा संशोधित 2020) में पुनः संशोधन करते हुए निवेशकों को सहयोग हेतु निम्न प्रावधानों को जोड़ा गया है।

- बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार द्वारा नियंत्राधीन औद्योगिक क्षेत्रों में विनिर्माण करने वाली इकाइयों एवं सेवा प्रक्षेत्र की निम्न प्रकार की इकाइयों को जमीन आवंटित की जाएगी।
    - आईटी पार्क
    - स्टार्ट अप को–वर्किंग स्पेस एवं स्टार्ट अप हब
    - ग्रेड ए वेयर हाउस
    - लॉजिस्टिक पार्क
    - रिसर्च/टेस्टिंग लैब

- बियाडा में "प्राथमिकता वाले क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए रिक्त औद्योगिक भूखंड का आवंटन" को विभिन्न परियोजनाओं के लिए रिक्त औद्योगिक भूखंड के आवंटन से प्रतिस्थापित किया गया है।

- राज्य में विद्यमान इकाइयाँ औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत शर्तों/दरों पर अनुदान प्राप्त करने के लिए योग्य होगी, जब तक इकाई की समय सीमा एवं/अथवा सीमा समाप्त न हो गयी हो। साथ ही जिन इकाइयों द्वारा पूर्व की प्रोत्साहन नीतियों में किसी भी प्रकार का प्रोत्साहन प्राप्त किया गया है, वे वर्तमान नीति में मात्र उन मदों में प्रोत्साहन के लिए पात्र होंगे जो उन्होंने पूर्व में प्राप्त नहीं किये हैं।

❖ **राज्य कैबिनेट के फैसले के मुताबिक बियाडा के 54 औद्योगिक क्षेत्रों में लीज दरों में 80% तक की कमी की गई है।**

माननीय अध्यक्ष महोदय,

बिहार स्टार्ट–अप नीति–2022– बिहार स्टार्ट–अप नीति, 2017 की अवधि मार्च, 2022 में समाप्त होने के बाद राज्य सरकार द्वारा दिनांक– 27 जून, 2022 से बिहार स्टार्ट–अप नीति, 2022 लागू की गयी है जो अगले पाँच वर्षो तक प्रभावी है। इस नीति के द्वारा राज्य में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना तथा उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु वातावरण तैयार किया जा रहा है। वित्तीय सहायता, इन्क्यूबेशन सेन्टर, फन्डिंग, प्रचार–प्रसार, प्रमाणीकरण आदि की व्यवस्था इस नीति के मुख्य अंग हैं। इसके तहत 28 फरवरी, 2023 तक कुल प्राप्त आवेदनों में 327 आवदेकों को प्रमाणीकृत किया गया है। इन्हें सोलह करोड़ तीस लाख रुपयों की वित्तीय सहायता प्रदान की गयी है। इसके साथ ही इस नीति के अन्तर्गत स्टार्ट–अप की आवश्यक सुविधाओं के लिए पटना में 2 प्रमुख स्थानों पर को–वर्किंग स्पेस रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट, कॉमन सॉफ्टवेयर एण्ड हार्डवेयर सुविधा, क्वालिटी इंश्योरेन्स लैब आदि की व्यवस्था की गयी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय,

मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अति पिछड़ा वर्ग/युवा/महिला उद्यमी योजनाः–

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अति पिछड़ा वर्ग के युवाओं तथा सभी वर्ग के युवाओं एवं महिलाओं को उद्योग स्थापित करने में अभिरूचि पैदा करने तथा सूक्ष्म एवं लघु उद्योग

को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक विशेष स्व–रोजगार योजना राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही है।

इस योजना के अन्तर्गत संबंधित प्रक्षेत्र के युवा एवं युवतियों को कुल परियोजना लागत (प्रति इकाई) अधिकतम दस लाख रूपये का 50 प्रतिशत (अधिकतम पाँच लाख रूपये) विशेष प्रोत्साहन योजना अन्तर्गत अनुदान/सब्सिडी तथा 50 प्रतिशत (अधिकतम पाँच लाख रूपये) ब्याज मुक्त ऋण के रूप में उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। केवल मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अन्तर्गत अन्य समान प्रावधानों के साथ ऋण पर मात्र एक प्रतिशत वार्षिक ब्याज का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त सभी लाभुकों के प्रशिक्षण एवं परियोजना अनुश्रवण समिति की सहायता के लिए प्रति इकाई पच्चीस हजार रूपये की दर से व्यय किये जाने का प्रावधान है। इस योजना का कार्यान्वयन बिहार स्टार्ट–अप फंड ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2022–23 में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना को कैटेगरी ए, बी एवं सी में वर्गीकृत किया गया है। कैटेगरी ए के अन्तर्गत कुल 51 परियोजनाओं में आवेदन प्राप्त किये गये, जबकि कैटेगरी बी के अन्तर्गत सिर्फ चर्म एवं वस्त्र तथा खाद्य प्रसंस्करण प्रक्षेत्र के लिए ही आवेदन प्राप्त किये गये। कैटेगरी सी में बियाडा के औद्योगिक क्षेत्रों में मात्र चर्म एवं वस्त्र प्रक्षेत्र के उद्यम की स्थापना के लिए ही आवेदन स्वीकार किये गये।

वित्तीय वर्ष 2022–23 में मुख्यमंत्री उद्यमी योजनान्तर्गत कम्प्यूटरीकृत रैण्डेमाईजेशन पद्धति द्वारा कैटेगरी ए, बी एवं सी में क्रमशः चार हजार बीस, एक हजार पाँच सौ अस्सी तथा छः सौ सत्तर एवं दिव्यांग श्रेणी से 162 अर्थात् कुल छः हजार चार सौ बत्तीस लाभुक चयनित किये गये।

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत अब तक चयनित 29828 लाभुकों को चौदह सौ पचास करोड़ रूपयों की सहायता राशि विमुक्त की जा चुकी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय,

मुख्यमंत्री सूक्ष्म एवं लघु उद्योग क्लस्टर विकास योजना

राज्य में आर्थिक विकास एवं स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री सूक्ष्म एवं लघु उद्योग क्लस्टर विकास योजनांतर्गत सामान्य सुविधा केन्द्र (CFC) की स्थापना पर राज्य सरकार तथा क्लस्टर SPV का अंशदान क्रमशः 90 प्रतिशत (अधिकतम दस करोड़) एवं 10 प्रतिशत का प्रावधान किया गया है। विशेष परिस्थिति में यदि क्लस्टर के सभी सदस्य गरीबी रेखा से नीचे के हों तो राज्य सरकार का अंशदान 100 प्रतिशत तक दिए जाने का प्रावधान है।

मुख्यमंत्री सूक्ष्म एवं लघु उद्योग क्लस्टर विकास योजनांतर्गत कुल आठ क्लस्टरों में सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना हेतु तैयार डी0पी0आर0 पर राज्य स्तरीय समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है जिसके अन्तर्गत अबतक सात क्लस्टरों यथाः–**राईस मिल क्लस्टर–लखीसराय,** मेनमेहसी सीप बटन क्लस्टर–पूर्वी चम्पारण, **बथना सीप बटन क्लस्टर–पूर्वी चम्पारण,** सिलाव खाजा क्लस्टर–नालन्दा, **कन्हैयागंज झूला क्लस्टर – नालन्दा,** काँसा–पीतल कलस्टर, वैशाली एवं **काँसा–पीतल कलस्टर, पश्चिमी चम्पारण** में सामान्य सुविधा केन्द्रों की स्थापना की जा रही है, जिसमें से सीप बटन क्लस्टर, मेनमेहसी, मोतिहारी सीप बटन क्लस्टर, बथना, मोतिहारी एवं लखीसराय, राईस मिल कलस्टर में वाणिज्यिक उत्पादन कार्य प्रारम्भ हो चुका है।

माननीय अध्यक्ष महोदय,

निवेश आयुक्त, मुम्बई कार्यालय

देश के भीतर एवं बाहर निवेशकों के बीच निवेश हेतु प्रचार–प्रसार के लिए निवेश आयुक्त का कार्यालय बनाया गया है जो कि देश की वाणिज्यिक राजधानी मुम्बई में अवस्थित है।

बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के अन्तर्गत 10 प्रौद्योगिक प्रक्षेत्रों को प्राथमिकता प्रक्षेत्र घोषित किया गया है। इसी के तहत जून, 2022 में लेदर एवं टेक्सटाइल पॉलिसी लाई गयी जिसमें निवेशकों को कई सुविधाएँ दी गयी। उक्त पॉलिसी एवं औद्योगिक प्रोत्साहन नीति में उल्लेखित अन्य प्रक्षेत्रों के प्रसार हेतु तीन हजार दो सौ बाईस निवेशकों से संपर्क किया गया, 8 इन्वेस्टमेंट मीट का आयोजन किया गया तथा विभिन्न कम्पनियों द्वारा आयोजित 4 सेमिनार मीट में भाग लिया गया।

निवेश आयुक्त कार्यालय के प्रयास से वित्तीय वर्ष 2022–23 में अबतक कुल 36 'निवेश निश्चय' (मेमोरेन्डम ऑफ अन्डरस्टैन्डिंग) हुए, जिसमें एक हजार दो ग्यारह करोड़ रुपये का निवेश तथा आठ हजार नौ सौ दो प्रत्यक्ष रोजगार का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

बिहार फाउण्डेशन

बिहार फाउण्डेशन बिहार सरकार का प्रवासी प्रकोष्ठ है। राज्य के बाहर, देश–विदेश में अवस्थित बिहारी समुदायों को उनके स्वयं के बीच तथा गृह राज्य के साथ भावनात्मक रूप से जोड़ने के उद्देश्य के साथ बिहार फाउण्डेशन का गठन किया गया है।

देश एवं विदेशों में प्रवासी बिहारी समुदाय के सहयोग एवं फाउण्डेशन के उद्देश्यों के प्रति एकजुटता की वजह से अबतक कुल 26 (छब्बीस) चैप्टर्स खुल चुके हैं जिनमें विदेशों में 14 (चौदह) चैप्टर्स एवं भारत में 12 (बारह) चैप्टर्स हैं। विदेशों में कतर, जापान संयुक्त अरब अमीरात (यू0ए0ई0), बहरीन, कनाडा,

ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, हांगकांग, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, यू0एस0ए0 (वेस्टर्न टाईम जोन), यू0एस0ए0 (ईस्टर्न टाईम जोन), सऊदी अरब तथ यू0के0 में चैप्टर मौजूद हैं। भारत में मुम्बई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, नागपुर, वाराणसी, पुणे, गुजरात, गोवा, गुवाहाटी, सिलीगुड़ी तथा सिक्किम चैप्टर कुल 12 चैप्टर शामिल हैं।

बिहार फाउण्डेशन द्वारा सोशल मीडिया के व्यापक तथा विस्तृत पहुँच को ध्यान में रखते हुए प्रमुख सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म यथाः– फेसबुक, ट्वीटर, यू–ट्यूब के माध्यम से बिहार की सकारात्मक तथा उभरती छवि को देश–विदेश में अवस्थित प्रवासी बिहारियों तक पहुँचाया जा रहा है। बिहार फाउण्डेशन के सोशल मीडिया प्लेटफार्म की वर्तमान स्थिति फेसबुक–छः लाख नब्बे हजार लाईक्स, ट्वीटर–सैंतीस हजार दो सौ फॉलोवर्स तथा यू–ट्यूब–दस लाख व्यूज़ हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय

बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (बियाडा) अंतर्गत नौ कलस्टर कार्यालय हैं, जिनके अधीन कुल 75 औद्योगिक क्षेत्र/ प्रांगण/विकास केन्द्र एवं मेगा औद्योगिक पार्क अवस्थित है। बियाडा अन्तर्गत स्थापित विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों, औद्योगिक प्रांगणों, औद्योगिक विकास केन्द्रों के अन्तर्गत आधारभूत संरचना का कार्य किया जा रहा है। जिसमें सड़क निर्माण, चहारदीवारी निर्माण, सोलर स्ट्रीट लाईट, नाला निर्माण, फूड पार्क, बैग क्लस्टर एवं प्लग एण्ड प्ले का निर्माण किया जा रहा है। उपरोक्त सारे कार्यो में होने वाली व्यय की राशि लगभग चौदह सौ करोड़ रूपये है।

वर्ष 2022–23 में उद्योग की स्थापना हेतु अबतक कुल 259 इकाइयों के बीच दो सौ सैंतीस एकड़ भूमि का आवंटन किया गया

है। इस आवंटन से कुल दो हजार छब्बीस करोड़ तेईस लाख रुपये का निवेश होगा एवं कुल दस हजार आठ सौ तैतीस लोगों को रोजगार की प्राप्ति होगी। वर्त्तमान में बियाडा के अंतर्गत राज्य में आठ हजार पाँच सौ साठ एकड़ औद्योगिक भूमि है। इनमें स्थापित दो हजार आठ सौ तीन औद्योगिक इकाइयों में से एक हजार सात सौ पचप्पन इकाइयाँ कार्यरत है।

माननीय अध्यक्ष महोदय

आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार (आयडा) के तहत भूमि बैंक रिवॉलविंग फंड हेतु बिहार सरकार (उद्योग विभाग) द्वारा कुल रू0 एक हजार नौ अठारह करोड़ उन्तीस लाख मात्र राशि उपलब्ध करायी गयी है। उक्त भूमि बैंक निधि से विभिन्न परियोजनाओं के लिए राशि उपलब्ध करायी गयी है। वर्त्तमान में गया जिलान्तर्गत डोभी अंचल में अमृतसर–कोलकाता औद्योगिक गलियारा के स्थापनार्थ एक हजार छः सौ सत्तर एकड़ भूमि का अर्जन तथा फतुहाँ के पास मल्टी–मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना हेतु एक सौ आठ एकड़ भूमि का अर्जन तथा कई अन्य भू–अर्जन की योजनाएँ प्रक्रियाधीन है।

माननीय अध्यक्ष महोदय,

हस्तशिल्प प्रक्षेत्र

उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना राज्य में हस्तशिल्प प्रक्षेत्र के मुख्य संस्थान के रूप में जाना जाता है। संस्थान द्वारा अप्रैल, 2022 से अबतक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिनमें बिहार क्राफ्ट मेला तथा गया में आयोजित अखिल भारतीय हस्तशिल्प मेला–सह–प्रदर्शनी शामिल हैं। इसके अलावा संस्थान द्वारा छः माह के निःशुल्क हस्तकला प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

दिनांक 14–27 नवम्बर, 2022 तक नई दिल्ली में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन किया गया। इस अन्तर्राष्ट्रीय मेला में बिहार पवेलियन को सुंदर और शानदार प्रदर्शन के लिए रजत पदक मिला।

माननीय अध्यक्ष महोदय,

हस्तकरघा प्रक्षेत्र

हस्तकरघा बुनकरों को कार्यशील पूँजी उपलब्ध कराने की योजना– बुनकर अपना कच्चा माल खरीद सकें, इसके लिए दस हजार रूपये प्रति पात्र बुनकर को कार्यशील पूँजी सीधे उनके बैंक खाते में दिये जाते हैं। इस वर्ष अबतक एक हजार पाँच सौ बुनकरों को कुल एक करोड़ पचास लाख रूपये कार्यशील पूँजी के रूप में उपलब्ध कराया जा चुका है।

हस्तकरघा एवं पावरलूम पर यू0आई0डी0 का उत्कीर्णः– हस्तकरघा एवं पावरलूम पर राज्य सरकार द्वारा यूनिक आईडेन्टिफिकेशन संख्या (यू0आई0डी0) का उत्कीर्ण कराया जा रहा है। अबतक ग्यारह हजार पाँच सौ आठ हस्तकरघा/पावरलूम एवं दो हजार आठ सौ सैंतालीस विद्युतकरघा पर यू0आई0डी0 उत्कीर्ण किया गया है।

हस्तकरघा विपणन सहायताः– वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022–23 में वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तीन स्टेट हैण्डलूम एक्सपो, गया, पटना, भागलपुर एवं दो जिला हैण्डलूम एक्सपो, नालन्दा, मुजफ्फरपुर की स्वीकृति प्रदान की गयी है। गया में आयोजित स्टेट हैण्डलूम एक्सपो में 60 स्टॉल के माध्यम से चौवालीस लाख रूपये मूल्य के हस्तकरघा वस्त्रों की बिक्री बुनकरों द्वारा की गयी है। साथ ही स्टेट हैण्डलूम एक्सपो, पटना में 118 स्टॉल के माध्यम से एक करोड़ दस लाख रूपये मूल्य के हस्तकरघा वस्त्रों एवं अन्य सामग्रियों की बिक्री की गयी।

विद्युतकरघा प्रक्षेत्र

विद्युतकरघा बुनकरों को विद्युत अनुदानः– राज्य में लगभग उनतीस हजार विद्युतकरघा कार्यरत है। ये सघन रूप से गया, भागलपुर एवं बांका में हैं। साथ ही नालन्दा, प० चम्पारण एवं पटना में भी विद्युतकरघा कार्यरत हैं। विद्युतकरघा पर वस्त्र बुनाई के लिए बिजली खपत पर तीन रूपये प्रति यूनिट की दर से विद्युत अनुदान उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय वर्ष 2022–23 में पन्द्रह करोड़ रूपये अनुदान की स्वीकृति प्रदान की गयी है। अनुदान की राशि सीधे पावर कम्पनी को भेज दी जाती है।

मलवरी विकास परियोजना

कोशी प्रमण्डल में रेशम उत्पादन को मूर्त रुप देने के क्रम में मलवरी रेशम विकास परियोजना अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का क्रियान्वयन जीविका, बिहार के माध्यम से किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में योजनान्तर्गत पाँच हजार दो सौ सतहत्तर कृषकों/लाभान्वितों को मलवरी रेशम कीट खाद्य–पौधों (मलवरी/शहतूत) का दो हजार छः सौ अड़तीस एकड़ में पौधारोपण, कीटपालन गृह निर्माण सहायता, कीटपालन उपस्कर की आपूर्ति, सिंचाई व्यवस्था (5 कृषकों की एक इकाई), प्रशिक्षण एवं स्थल भ्रमण, नोडल सेंटर की स्थापना के साथ–साथ जन जागरुकता कार्यक्रम जीविका, बिहार, पटना द्वारा किया जा रहा है। किशनगंज में ही पूर्व स्थापित मलवरी रीलिंग केन्द्र को भेड़ियाडांगी, किशनगंज के परिसर में स्थानान्तरित करते हुए राशि सात लाख चौदह हजार रुपये की लागत से आयडा, बिहार, पटना द्वारा शेड निर्माण किया गया है। अबतक 20.25 मिट्रिक टन मलवरी कोए का उत्पादन किया गया है।

तसर विकास परियोजना

तसर रेशम कीट खाद्य–पौधों का निजी भूमि में तीन हजार चार सौ एक हे0 एवं वन भूमि में छः हजार एक सौ बीस हे0 (कुल नौ हजार पाँच सौ इक्कीस हे0) पर पौधारोपित भूखण्डों पर कीटपालन कार्य किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में नवादा

जिला में केन्द्र प्रायोजित सिल्क समग्र योजना के अन्तर्गत एक करोड़ तिरसठ लाख पचास हजार रुपये की लागत से तसर रेशम विकास हेतु कुल 400 कृषकों के द्वारा तसर वृक्षारोपण एवं 50 कृषकों को मोटराईज्ड/पैडल स्पिनिंग मशीन उपलब्ध कराया गया है। राज्य योजना अन्तर्गत कुल बीस लाख इकतीस हजार रुपये की लागत से 105 लाभुकों को कीटपालन उपस्कर/सामग्री का वितरण किया गया है। जमुई जिले में अनु0 जनजाति के परिवारों को तसर रेशम उत्पादन से जोड़े जाने हेतु राशि एक करोड़ पैंतालीस लाख सन्तावन हजार रुपये से कुल 200 लाभुकों को लाभान्वित किया जा रहा है। अबतक चार करोड़ बावन लाख चौदह हजार रुपये तसर रेशम कोए का उत्पादन किया गया है।

अंडी रेशम

वित्तीय वर्ष 2022–23 में मुजफ्फरपुर जिला के 204 लाभुकों को अंडी रेशम कीटपालन का प्रशिक्षण देते हुए इन्हें कीटपालन उपस्कर एवं कीटपालन गृह निर्माण हेतु सहायता उपलब्ध करायी गयी है। साथ ही बेगूसराय में 93 अंडी कृषकों को राज्य अंडी रेशम विकास योजनान्तर्गत लाभान्वित किए जाने हेतु राशि सात करोड़ बावन लाख से लाभान्वित किया जा रहा है। अबतक 16.43 मिट्रिक टन अंडी कोए का उत्पादन किया गया है।

हैण्डलूम प्रक्षेत्र

राज्य के हस्तकरघा बुनकरो को अपने उत्पादों की बिक्री करने के लिए पटना में हैण्डलूम हाट का निर्माण किया गया है जिसमें बुनकरों द्वारा बिक्री के लिए आपूर्ति किये गये वस्त्रों के मूल्य का 25 प्रतिशत राशि का भुगतान अग्रिम के रूप में किया जाता है। शेष राशि उत्पादन के बिक्री के पश्चात् बुनकरो को दी जाती है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में राष्ट्रीय हस्तकरघा विकास कार्यक्रम के तहत बुनकर अंशदान की राशि 10 प्रतिशत को राज्य योजना से प्रतिपूर्ति किये जाने हेतु कुल दो करोड़ रूपये मात्र सब्सिडी की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गयी है। माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के करकमलों द्वारा 7 अगस्त, 2022 को

राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस के अवसर पर "बिहार हैण्डलूम" लोगो का लोकार्पण किया गया है। इससे राज्य के बुनकरों द्वारा उत्पादित हस्तकरघा वस्त्रों को एक पहचान मिलेगी।

खादी प्रक्षेत्र

बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा खादी मेला सह प्रदर्शनी का आयोजन राज्य के विभिन्न जिलों में किया गया है। मोतीहारी, गया, भभुआ, पूर्णिया और आरा में मेला का आयोजन हो चुका है। जबकि सिवान में मेला का आयोजन प्रस्तावित है।

बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा राज्य के खादी संस्था/समितियों के माध्यम से विभिन्न जिलों में कुल 53 केन्द्रों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें एक हजार तीन सौ पच्चीस प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण देकर स्वावलंबी बनाया गया।

बिहार स्थित खादी संस्थाओं को संस्था के कार्य सुचारू रूप से चलाने तथा कच्चा माल एवं कातिनों/बुनकरों को समय पर पारिश्रमिक भुगतान एवं अन्य भुगतान हेतु कार्यशील पूँजी (ऋण) मात्र 4: के ब्याज दर पर ऋण के रूप में 07 वर्षों के लिए संस्था/समितियों को उपलब्ध कराया जा रहा है। कार्यशील पूंजी के रूप में संस्थाओं के बीच तीन करोड़ पैंतीस लाख रूपये ऋण के रूप में वितरण किया गया है।

रिबेट योजना–राज्य के 45 खादी संस्था/समितियों को खादी वस्त्रों के उत्पादन पर 10% की छूट (रिबेट) की राशि एक करोड़ तैंतालीस लाख रूपये का भुगतान किया गया है।

खादी मॉल पटनाः– खादी मॉल, पटना में वित्तीय वर्ष 2022–23 में अब तक कुल सोलह करोड़ रूपये की बिक्री हुई है। जिससे खादी मॉल, पटना से जुड़े प्रमाणित खादी/ग्रामोद्योग संस्थाओं के कामगारों को लाभ पहुंचा है।

अब मैं वित्तीय वर्ष 2023–24 की भावी योजनाओं की संक्षिप्त रूप–रेखा प्रस्तुत कर रहा हूँ:–

1. वित्तीय वर्ष 2023–24 में मशीन उपकरण का क्रय करते हुए सुचारु रुप से दोनों कोकून बैंक का संचालन जीविका, बिहार, पटना द्वारा किया जाएगा।
2. पूर्णिया एवं मुजफ्फरपुर में बिहार राज्य खादी बोर्ड के जमीन पर खादी मॉल का निर्माण आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार द्वारा किया जा रहा है। जिसके लिए सोलह करोड़ पचास लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान की गयी है।
3. मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में नवचयनित लगभग आठ हजार लाभुकों को प्रशिक्षण प्रदान कर उनके बीच राशि का वितरण किया जायेगा।
4. राज्य के युवाओं को बिहार का स्टार्ट–अप यूनिकॉर्न बनाने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए पटना के मौर्यालोक कॉम्पलेक्स में 64 स्टार्ट–अप को 104 सीटें तथा फ्रेजर रोड के वित्तीय निगम भवन में 200 से अधिक सीटों के लिए आधुनिक कार्यालय विकसित किया जा रहा है।
5. पीएमएफएमई के तहत अधिक लाभुकों को उद्योगों के लिए बैंक ऋण उपलब्ध कराने हेतु तेजी से कार्रवाई की जा रही है।
6. मलबरी रीलिंग यूनिट की स्थापना धमदाहा पूर्णियां में किया जाना है।
7. बांका जिले में दो तसर कोकून बैंक को संचालित करने की योजना है।

बजट माँग संख्या–23

वित्तीय वर्ष 2022–23 में उद्योग विभाग का स्कीम मद में पन्द्रह अरब पैंतालीस करोड़ रुपये तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय में अंठानवे करोड़ चौहत्तर लाख सोलह हजार रूपये अर्थात् कुल प्राक्कलन सोलह अरब तैंतालीस करोड़ चौहत्तर लाख सोलह

हजार रूपये था। वित्तीय वर्ष 2023–24 में स्कीम मद में पन्द्रह अरब पैंतालीस करोड़ रुपये तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय में एक सौ तीन करोड़ इक्यासी लाख तिहत्तर हजार रूपये अर्थात् कुल प्राक्कलन सोलह अरब अड़तालीस करोड़ इक्यासी लाख तिहत्तर हजार रूपये की अनुदान मांग का प्रस्ताव सदन के पटल पर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करता हूँ।

महोदय, मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूँ कि राज्य के औद्योगिकीकरण को गति देने में सहयोग करने हेतु प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव को वापस लेते हुए उद्योग विभाग की मांग को सर्वसम्मति से पारित करने की कृपा करें।

*****